कल्पमेधा

एक अच्छे यात्री की कोई तय योजना नहीं होती और वह कहीं पहुंचने के लिए हड़बड़ी में नहीं होता।

– लाओत्से

समझौते की राह

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के लिए वार्ता पिछले कई महीने से टुकड़ों में चलती रही है, लेकिन अब तक यह अंतिम स्वरूप में नहीं पहुंच सकी है। इसी क्रम में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपने ताजा भारत दौरे में एक बार फिर कुछ नए संकेत दिए, जिसमें इस मसले पर कदम आगे बढ़ाए जाने की रूपरेखा बनती दिख रही है। हालांकि व्यापार वार्ता में अपने-अपने हित के मद्देनजर दोनों पक्षों की ओर से दबाव बनाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन पिछले कुछ समय से अमेरिका ने एकतरफा तौर पर जिस तरह की कसौटियां तय करने की कोशिश की है, वह कई मायनों में भारत के लिए सहज स्वीकार्य नहीं रही हैं। यही वजह है कि अब तक इस समझौते का अंतिम स्वरूप सामने नहीं आ सका है। अब अमेरिका की ओर से रूबियो ने जिस तरह परस्पर हित सुनिश्चित किए जाने की बात की है, उससे इसमें सकारात्मक प्रगति की उम्मीद जगी है। गौरतलब है कि भारत के विदेश मंत्री के साथ व्यापक वार्ता के बाद रूबियो ने कहा कि यह व्यापार समझौता दोनों देशों के लिए 'लाभकारी' और 'टिकाऊ' होगा। साथ ही यह अमेरिका और भारत के पारस्परिक हितों को आगे बढ़ाएगा।

निश्चित तौर पर अमेरिका की ओर से दिए गए ये संकेत बीते कुछ समय से आर्थिक मसले पर जारी तनाव के माहौल में नरमी लाने का जरिया हो सकते हैं, लेकिन यह देखने की बात होगी कि व्यापार समझौता अपने अंतिम रूप में 'परस्पर और समान हित' के सिद्धांत पर आधारित होता है या नहीं। यह छिपा नहीं है कि अमेरिका ने कुछ महीने पहले दूसरे देशों से आयात पर पच्चीस से लेकर पचास फीसद तक शुल्क लगा कर किस तरह के हालात पैदा करने की कोशिश की थी। उसके इस रुख की वजह से दुनिया भर में प्रकारांतर से व्यापार युद्ध जैसी स्थितियां पैदा हो गई थीं। खासतौर पर तेल खरीद को लेकर अमेरिका ने भारत पर जिस तरह की शर्तें थोपीं, रूस से तेल खरीदने पर शुल्क में बढ़ोतरी की जिद ठानी, उससे साफ था कि वह इस मसले पर अपनी मनमानी थोपना चाहता है। उसका यह रुख किसी भी तरह से 'परस्पर और समान हित' को सुनिश्चित किए जाने की मंशा के अनुकूल नहीं लगता।

अभी भी अमेरिका यही संदेश दे रहा है कि भारत उससे जितना तेल खरीदना चाहता है, उतना देने के लिए वह तैयार है। सवाल है कि तेल के लिए अगर भारत की निर्भरता केवल अमेरिका पर बनती है, तो इसके नतीजे क्या होंगे? अमेरिका एक विकल्प जरूर हो सकता है, लेकिन अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए जरूरी है कि भारत अपने लिए अन्य देशों के वैसे व्यापक और विश्वसनीय स्रोतों का रास्ता भी खुला रखे, जो ज्यादा बेहतर और सस्ते हों। पश्चिम एशिया में जारी तनाव की स्थिति और होर्मुज जलमार्ग से आपूर्ति शृंखला बाधित होने की वजह से गहराते संकट से सभी वाकिफ हैं। इसी को आधार बना कर आज सरकार तेल और गैस की कीमतों में लगातार इजाफा कर रही है और आम लोगों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। अब नई परिस्थितियों में अगर भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता आगे बढ़ती है, तो यह ध्यान रखने की जरूरत होगी कि वह दोनों देशों के समान हित के सिद्धांतों पर आधारित हो। विदेश नीति के मामले में अमेरिका अगर खुद को प्राथमिकता देता है, तो यह उचित है, लेकिन इसके समांतर भारत के लिए भी अपने हित को सबसे महत्त्वपूर्ण मानना स्वाभाविक है।

तेल की धार

पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, जिस कारण ऊर्जा संकट दिनोंदिन गहराता जा रहा है। इसी का नतीजा है कि सोमवार को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में फिर से इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल के दाम में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। पिछले दो हफ्तों से भी कम समय में यह चौथी बार की गई वृद्धि है। खबरों के मुताबिक, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के साथ उसके खुदरा दाम बढ़ा रही हैं। मगर सवाल सिर्फ कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी का नहीं है, बल्कि इस बात का भी है कि सरकार इस संकट से निपटने के लिए वैकल्पिक उपायों पर कितनी तेजी और गंभीरता से काम कर रही है। बार-बार ईंधन की कीमतें बढ़ने से स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में माल ढुलाई की लागत भी बढ़ेगी, जिससे जरूरी वस्तुएं महंगी होंगी। ऐसे में पहले से ही आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे आम लोगों पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

दरअसल, फरवरी के अंत से अब तक वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में पचास फीसद से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इसका मुख्य कारण पश्चिम एशिया में तनाव और होर्मुज जलमार्ग को अवरुद्ध करने से तेल आपूर्ति का बाधित होना है। सरकार ने संघर्ष शुरू होने के बाद तकरीबन ढाई महीने तक तेल के दामों को स्थिर रखने का प्रयास किया, लेकिन तेल कंपनियों पर बढ़ते आर्थिक दबाव की वजह से अब स्थिति नियंत्रण से बाहर होती दिख रही है। हालांकि सरकार यह दावा करती रही है कि वैश्विक संकट के बीच ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन बीते करीब दो सप्ताह से पेट्राल-डीजल और सीएनजी के दाम में जिस तरह से लगातार बढ़ोतरी हुई है, उससे सरकार के प्रयास सफल होते नजर नहीं आ रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा असर समाज के उस वर्ग पर पड़ेगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर है और अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन भर संघर्ष करता है। इससे पहले कि स्थिति और ज्यादा बिगड़े, सरकार को ऊर्जा संकट पर काबू पाने के वैकल्पिक रास्ते तैयार करने होंगे और महंगाई से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।

पर्यटन में संभावनाओं की नई डगर

भारत कई संस्कृतियों का देश है। नई वैश्विक चुनौतियों के बीच पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार समृद्ध हो सकता है और बड़े पैमाने पर रोजगार के रास्ते भी खुलेंगे।

सुरेश सेठ

हमारे देश में पर्यटन को विशेष महत्त्व दिया गया है। वैसे तो भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन कमाई पर्यटन क्षेत्र से होती है। इसको कई तरीके से वर्गीकृत कर देखा जा सकता है जैसे, चिकित्सा पर्यटन और धार्मिक पर्यटन। इस तरह के पर्यटन से विदेशी राजस्व भी प्राप्त हो जाता है, क्योंकि कई देशों से पर्यटक और यात्री भारत आते हैं और हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को समृद्ध करते हैं। रमणीक स्थलों के पर्यटन को भी कमाऊ माना गया है। पहाड़ों, नदी किनारे और समुद्र तट पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। इस पर्यटन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। कई स्थलों का पुनरुद्धार कर पर्यटकों को आकर्षित किया गया है। आकर्षक पर्यटन स्थलों को देखने जब विदेश वे आते हैं, इससे देश को फायदा ही होता है। मगर अब एक नया संकट हमारे सामने हैं। ईरान और अमेरिका युद्ध के कारण कच्चे तेल, गैस और उर्वरक का भारी संकट पैदा हो गया है। देश के शीर्ष नेतृत्व ने मितव्ययी होने का संदेश दिया है। सोना न खरीदने, पेट्रोल-डीजल बचाने और विदेशी यात्राएं कम करने की नसीहत दी गई है। लक्ष्य एक ही है कि विदेशी पूंजी बचाई जाए, ताकि विदेशी विनिमय में हम अपने बजट घाटे और चालू घाटे को संभाल सकें और डालर के मुकाबले रुपए के गिरते जाने से बचा सकें।

इन चुनौतियों के बीच पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। उसे और विकसित किया जा सकता है। इस पर काम करने की जरूरत है। भारत कई संस्कृतियों का देश है। इतनी विविधता वाला राष्ट्र दुनिया में कहीं नहीं हैं। कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत की एक अनूठी लोक संस्कृति भी है। ग्रामीण समाज के हर क्षेत्र की अपनी विशेषता है। अपने-अपने लोकगीत हैं और अपनी-अपनी लोक परंपराएं हैं। अगर इनकी ओर देश और विदेश के पर्यटकों को आकर्षित किया जाए, तो हमारा राजस्व बढ़ेगा। विदेशी पूंजी कमाने का एक नया रास्ता निकलेगा। हमारे सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े बताते हैं कि कृषि क्षेत्र के मुकाबले सेवा क्षेत्र से कहीं अधिक राजस्व प्राप्त होता है। सेवा क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र मुख्य भागीदार है। अगर पर्यटन क्षेत्र में हम लोक संस्कृति से परिचय का एक नया आयाम जोड़ दें, तो पर्यटकों की एक बड़ी संख्या हमारे सामने होगी। देश के कई कोने पर्यटन का आकर्षण बन जाएंगे। भारत में विदेशी पर्यटकों की आमद इस तरह भी बढ़ाई जा सकती है। हमारी घरेलू दस्तकारियां, हमारे अनूठे लोक नृत्य और ग्रामीण समाज का लोक व्यवहार पर्यटकों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है। बस इसको और प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इससे हम विदेशी पर्यटकों के लिए भारत में एक नई दुनिया खोज सकते हैं।

पिछले दिनों पंजाब में एक नई नीति शुरू हुई है जिसे 'होमस्टे नीति' कहा जाता है। इसमें पंजाबी संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने का 'मास्टर प्लान' बनाया गया है। 'होमस्टे' को लेकर नवाचार या उससे जुड़े नव उद्यमियों के लिए आनलाइन पंजीकरण की नीति बनाई गई है। यह भी घोषणा की गई है कि ऐसे उद्यमियों को योजनाबद्ध तरीके से पांच करोड़ तक की सबसिडी दी जा सकती है। मगर पंजाब ही क्यों, हम इसका विस्तार देश के हर राज्य में कर सकते हैं, क्योंकि हर राज्य की ग्रामीण संस्कृति और उसका

लोकाचार और व्यंजन अलग-अलग हैं। इसे बढ़ावा दें, तो पर्यटक देश के हर कोने में जाना पसंद करेंगे। इस प्रकार हम देखते ही देखते पूरे देश को पर्यटकों के लिए आकर्षक स्थल बना सकते हैं। पंजाब में जो योजना बनाई गई है, इसका नाम 'फार्मस्टे पालिसी 2026' दिया गया है। आजकल होटलों

> **कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत की एक अनूठी लोक संस्कृति भी है। ग्रामीण समाज के अनूठेपन का तो क्या ही कहना। इसमें हर क्षेत्र की अपनी विशेषता है। अपने-अपने लोकगीत हैं और अपनी-अपनी लोक परंपराएं हैं। अगर इनकी ओर देश और विदेश के पर्यटकों को आकर्षित किया जाए, तो हमारा राजस्व बढ़ेगा। विदेशी पूंजी कमाने का एक नया रास्ता निकलेगा। हमारे सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े बताते हैं कि कृषि क्षेत्र के मुकाबले सेवा क्षेत्र से कहीं अधिक राजस्व प्राप्त होता है। सेवा क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र मुख्य भागीदार है। अगर इसमें हम लोक संस्कृति से परिचय का एक नया आयाम जोड़ दें, तो पर्यटकों की एक बड़ी संख्या हमारे सामने होगी।**

के अतिरिक्त रमणीक स्थलों पर आने वाले नव दंपतियों या विदेशी पर्यटकों को 'होमस्टे' की सुविधा दी गई है। हिमाचल और उत्तराखंड की सरकारें इस तरह के निवेश को अपने यहां प्रोत्साहित कर रही है। अब पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों को पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाया जा सकता है।

पंजाब ने इस दिशा में पहल कर दी है। अब यहां किसान पर्यटकों को ठहराने, खाने-पीने और ठेठ ग्रामीण जीवनशैली का अनुभव कराने की सुविधा शुरू कर सकेंगे। ध्यान देने की बात है कि पंजाब ही नहीं पूरे देश में छोटे किसानों की की बड़ी संख्या है, जिनके पास औसत क्षेत्र दो एकड़ से पांच एकड़ तक जमीन है। इससे आय इतनी कम होती है कि उनका जीना मुश्किल हो जाता है। आजादी के इतने साल गुजर जाने के बाद भी वे अपनी खेती को व्यावसायिक नहीं बना सके और आज भी उन्हें मानसून पर निर्भर रहना पड़ता है। मगर अब यह सहारा भी कमजोर पड़ने लगा है। पर्यावरण पर प्रदूषण की मार का असर उन पर भी पड़ा है। बारिश के मौसम में भीषण गर्मी पड़ती है और जब फसलें पकने लगती हैं तो बारिश होने लगती है। ऐसी स्थिति में किसानों को अतिरिक्त आय की जरूरत है। विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को जो इस समय खेतीबाड़ी में हाथ बंटा कर परिवार की मदद करती हैं। उनको अतिरिक्त आय का साधन दिया जा सकता है। वह साधन है- 'फार्मस्टे'। इसमें इनकी भूमिका महत्त्वपूर्ण हो सकती है। वे पर्यटकों को ठहराने और ग्रामीण जीवनशैली से परिचित कराने में सहयोग कर आय का उपार्जन कर सकती हैं।

अगर हम लोक संस्कृति के वाहक बन कर पूरे देश के ग्रामीण परिवेश को पर्यटकों के लिए विशेष पर्यटन क्षेत्र बना दें, तो सोचिए, इससे राजस्व में कितनी वृद्धि हो जाएगी। यही सोच कर पंजाब ने नई नीति बनाई है। पहाड़ों में बने 'होमस्टे' की तर्ज पर 'फार्मस्टे' को विकसित किया जा रहा है। ऐसा हर राज्य क्यों न करें? सभी राज्यों की अपनी लोक संस्कृति है और अपना ग्रामीण आकर्षण। पंजाब आने वाले पर्यटक खेतों में रह कर ट्रैक्टर चलाने, बैलगाड़ी की सवारी करने, पशुपालन देखने और गांवों के पारंपरिक खानपान व रहन-सहन को करीब से महसूस कर सकेंगे। इसी प्रकार हर राज्य अपनी-अपनी ग्रामीण संस्कृति के अनूठेपन और अपने लोकगीतों एवं लोकनृत्यों से पर्यटकों को लुभा सकता है। पंजाब में यह तय किया गया कि इस तरह के पर्यटन के लिए किसान के पास कम से कम एक एकड़ कृषि भूमि जरूर हो। इस प्रकार यहां के छोटे किसानों को अतिरिक्त आय का एक साधन मिल गया है। पंजाब में बनी नई नीति में साफ किया गया है कि कुल जमीन के केवल दस फीसद हिस्से पर ही निर्माण किया जा सकेगा, जबकि बाकी 90 फीसद क्षेत्र खुला रखना होगा, ताकि पर्यटकों के लिए खेती और उसका प्राकृतिक स्वरूप बना रहे।

पंजाब में इस परियोजना पर निवेश में दस फीसद सबसिडी मिलेगी। इसकी अधिकतम सीमा पंच करोड़ है। विदेशी पर्यटक आते हैं तो 'फार्मस्टे' संचालक को 24 घंटे के भीतर फार्म-सी भरकर प्रशासन को सूचना देनी होगी और ध्यान रखना होगा कि उनका 'फार्मस्टे' ग्रामीण परिवेश को बरकरार रखे। गांवों की शांति और सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। यह योजना अपने आप में महत्त्वपूर्ण है। इससे पहले निर्यात के लिए भी हर राज्य की दस्तकारी को विशेष रूप से प्रोत्साहन देने की योजना बनाई गई थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। मगर इस योजना में क्योंकि साधारण व्यक्ति का अपना उद्यम शामिल है, इसलिए इसके कामयाब होने की गुंजाइश काफी अधिक है।

स्पंदनों का संगीत

मनीषा मंजरी

अक्सर हम जीवन को उन दृश्यों में बांध देते हैं, जो हमारी आंखों के सामने घटित होते हैं। जैसे रोजमर्रा की घटनाएं, सफलताएं, असफलताएं, रिश्ते और समय के साथ बदलते हालात। मगर जीवन का एक और आयाम भी है, जो दृश्य नहीं है, फिर भी उतना ही वास्तविक है। यह आयाम है कंपन, स्पंदन, वह सूक्ष्म ऊर्जा, जो हमारे भीतर और चारों ओर निरंतर बहती रहती है। हम उसे देख नहीं पाते, फिर भी हम उसे महसूस अवश्य करते हैं। जैसे रंगों का प्रभाव केवल उनकी आकृति या चमक में नहीं, बल्कि उनकी ऊर्जा में छिपा होता है, वैसे ही जीवन की गहराई भी उसकी अनदेखी तरंगों में बसती है।

जीवन में कंपन का अर्थ केवल भौतिक विज्ञान की किसी परिभाषा से नहीं है। यह एक ऐसा अनुभव है, जो भावनाओं, विचारों और चेतना के स्तर पर घटित होता है। हम कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के प्रसन्न हो जाते हैं, तो कभी भीतर एक अनजानी उदासी उतर आती है। ये भावनाएं केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं होतीं, बल्कि हमारे भीतर चल रहे स्पंदनों की अभिव्यक्ति होती हैं। यही कारण है कि दो लोग एक ही परिस्थिति में अलग-अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, क्योंकि उनके भीतर के कंपन अलग होते हैं।

दरअसल, जीवन 'घटनाओं' का नहीं, बल्कि 'अनुभवों' का नाम है और ये अनुभव हमारे भीतर के स्पंदनों से निर्मित होते हैं। जब हम यह समझने लगते हैं, तो हमारी दृष्टि अपने आप ही बाहर से भीतर की ओर मुड़ने लगती है। हम यह प्रश्न पूछने लगते हैं कि हमारे भीतर क्या चल रहा है या हमारी भावनाओं का स्रोत क्या है! यह भी कि क्या हम अपने अनुभवों के साक्षी बन सकते हैं! और यहीं से आत्मबोध की यात्रा प्रारंभ होती है।

इस यात्रा में सबसे बड़ी बाधा है, हमारी आदत, जो हर अनुभव को तुरंत नाम देने को आतुर होती है। हम हर भावना को 'अच्छा' या 'बुरा' कहकर सीमित कर देते हैं, लेकिन हम अगर इन स्पंदनों को बिना किसी निर्णय के देखें, तो वे केवल ऊर्जा के रूप में प्रकट होते हैं। एक शुद्ध, गतिशील ऊर्जा, जो आती है और चली जाती है। इस दृष्टि से, जीवन एक स्थिर वस्तु नहीं, बल्कि एक सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया है। यह एक प्रवाह है, जिसमें हर क्षण कुछ नया जन्म लेता है और कुछ पुराना विलीन हो जाता है। और इसी प्रवाह में, हम अक्सर स्वयं को भूल जाते हैं, क्योंकि हम उन तरंगों से जुड़ जाते हैं, जो अस्थायी हैं। अगर हम इस भूल को पहचान लें, तो जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल सकता है। हम यह समझने लगते हैं कि हमें हर भावना के साथ बहना नहीं है, बल्कि उसे देखना-समझना और उसके पार जाना है। इसी अवस्था में 'जीवन' एक अनुभव से उठकर एक 'साधना और कला' बन जाता है।

इस संदर्भ में 'कलाकार' का रूपक अत्यंत सार्थक है। एक कलाकार जब अपने कैनवास पर रंग भरता है, तो वह केवल बाहरी चित्र नहीं बनाता, बल्कि अपनी आंतरिक स्थिति को व्यक्त करता है। उसके रंग उसके भीतर के स्पंदनों का रूप होते हैं। ठीक उसी प्रकार, हमारा जीवन भी एक कैनवास है और हमारे विचार, भावनाएं और कर्म उसके रंग हैं। मगर यहां हम केवल कलाकार ही नहीं, बल्कि स्वयं कैनवास भी हैं। यानी हम ही सृजनकर्ता हैं और हम ही सृजन। यह द्वैत और अद्वैत के बीच का वह सूक्ष्म बिंदु है, जहां जीवन अपनी सबसे गहन अनुभूति में प्रवेश करता है। जब हम अपने विचारों को सजगता से देखने लगते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हर विचार एक बीज है, जो भविष्य के अनुभवों को जन्म देता है। हर भावना एक तरंग है, जो हमारे भीतर और बाहर दोनों को प्रभावित करती है। और हर कर्म उस तरंग को एक दिशा देता है।

इस प्रकार, हम अनजाने में ही अपने जीवन का संगीत रचते रहते हैं। 'जीवन का संगीत' एक अत्यंत सूक्ष्म और सुंदर रूपक है। संगीत में स्वर होते हैं, लय होती है और एक संतुलन होता है। अगर कोई स्वर असंतुलित हो जाए, तो पूरी रचना प्रभावित हो जाती है। इसी प्रकार, हमारे जीवन में भी संतुलन आवश्यक है। यह संतुलन बाहरी परिस्थितियों से नहीं, भीतर की सजगता से आता है। जब हमारे विचार, भावनाएं और कर्म एक ही दिशा में प्रवाहित होते हैं, तो जीवन में एक स्वाभाविक लय उत्पन्न होती है। जब यह लय स्थापित हो जाती है, तो जीवन में एक सहज सुंदरता प्रकट होती है, एक ऐसी सुंदरता, जो किसी प्रयास का परिणाम नहीं, बल्कि एक आंतरिक सामंजस्य का प्रतिबिंब होती है।

हालांकि जीवन में असंतुलन भी अति महत्त्वपूर्ण है। जैसे संगीत में आरोह-अवरोह, विराम और तीव्रता उसे पूर्ण बनाते हैं, वैसे ही जीवन के उतार-चढ़ाव भी उसे गहराई देते हैं। दुख, संघर्ष और अनिश्चितता- ये सब भी उसी संगीत का हिस्सा हैं। इनसे बचने की नहीं, इन्हें समझने की आवश्यकता है। जब हम जीवन को इस दृष्टि से देखना प्रारंभ करते हैं, तो धीरे-धीरे हमारे भीतर एक नई संवेदनशीलता जन्म लेती है। हम अपने अनुभवों को केवल 'जीने' के बजाय 'महसूस' करने लगते हैं। हम हर क्षण में उपस्थित होने लगते हैं।

यही उपस्थिति हमें उस अदृश्य स्पंदन के और करीब ले जाती है, जो जीवन का मूल है। जीवन कोई बाहरी यात्रा नहीं है, जिसे हमें तय करना है। यह एक आंतरिक प्रक्रिया है, जिसे हमें अनुभव करना है। हम जितना अपने भीतर के स्पंदनों को समझते हैं, उतना ही जीवन स्पष्ट होता जाता है। और एक समय ऐसा आता है, जब हम यह अनुभव करते हैं कि जीवन को समझने की आवश्यकता ही नहीं है, उसे केवल महसूस करने की आवश्यकता है। जीवन कोई समस्या नहीं, जिसे हल किया जाए, यह एक संगीत है, जिसे सुना जाए, जिया जाए और पूरी सजगता के साथ रचा जाए। जब हम इस संगीत को सच में सुन लेते हैं, तब हमें यह एहसास होता है, कि हम केवल श्रोता नहीं, बल्कि स्वयं उस अनंत रचना का एक जीवंत स्वर हैं।

दुनिया मेरे आगे

> **जीवन कोई बाहरी यात्रा नहीं है, जिसे हमें तय करना है। यह एक आंतरिक प्रक्रिया है, जिसे हमें अनुभव करना है। हम जितना अपने भीतर के स्पंदनों को समझते हैं, उतना ही जीवन स्पष्ट होता जाता है। और एक समय ऐसा आता है, जब हम यह अनुभव करते हैं कि जीवन को केवल महसूस करने की आवश्यकता है।**

आतंक की आग

पाकिस्तान इन दिनों एक ऐसे दौर से गुजर रहा है, जहां आतंकवाद की आग अब उसके अपने आंगन तक पहुंच चुकी है। हाल ही में पहलगाम हमले की साजिश रचने वाले की हत्या कर दी गई। यह कोई अकेली घटना नहीं है। पिछले दो वर्षों में 16 से अधिक आतंकियों को पाकिस्तान की धरती पर अज्ञात हमलावरों ने चुन-चुन कर मारा है। विडंबना यह है कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जब इन आतंकियों की पाकिस्तान में मौजूदगी उजागर होती है, तब वह उन्हें पहचानने तक से इनकार कर देता है। दूसरी ओर, भीतर ही भीतर वह इस बात से परेशान है कि आखिर उसकी सरजमीं पर बैठे आतंकी एक-एक कर कैसे मारे जा रहे हैं। दरअसल, पाकिस्तान के भीतर सक्रिय विभिन्न आतंकी गुटों के बीच पिछले कुछ वर्षों से वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। सरकारी संरक्षण, धन और सुविधाओं पर कब्जा जमाने के लिए ये संगठन एक-दूसरे को कमजोर करने में जुटे हैं। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अशिक्षित और बेरोजगार युवाओं को हिंसक गतिविधियों में झोंका जा रहा है। पहलगाम हमले के साजिशकर्ता की हत्या को भी इसी अंदरूनी संघर्ष का हिस्सा माना जा रहा है।

– अरविंद रावल, झाबुआ

महाशक्ति की परीक्षा

'संकट के समांतर' (संपादकीय, 18 मई) में वर्तमान वैश्विक जटिलताओं और उनके बहुआयामी प्रभावों को रेखांकित किया गया है। दो मत नहीं है कि जब किसी राष्ट्र या नेतृत्व के दृढ़ इरादों पर आघात होता है, तो परिस्थितियां बहुधा ऐसे वैकल्पिक और विरोधाभासी विचारों को जन्म देती हैं, जिनमें संतुलन साधना चुनौतीपूर्ण बन जाता है। होर्मुज जलमार्ग जैसे संवेदनशील और विवादित समुद्री क्षेत्र में उत्पन्न तनाव केवल क्षेत्रीय समस्या न रह कर वैश्विक स्थिरता को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में उभरता है। आज की वैश्विक व्यवस्था में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध अब केवल पारंपरिक कूटनीति तक सीमित नहीं रहे। ऐसे परिदृश्य में किसी भी महाशक्ति की वास्तविक परीक्षा उसकी दीर्घकालिक दृष्टि, नीति की गुणवत्ता और वैश्विक उत्तरदायित्व के निर्वहन में निहित होती है।

– अशोक, पटना

महंगाई का दंश

पिछले लगभग दो सप्ताह के दौरान डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बार-बार बढ़ोतरी की गई है। पश्चिम एशिया में हो रहे युद्ध की वजह से महंगाई बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन दुनिया भर में महंगाई का सबसे अधिक प्रभाव केवल भारत पर और यहां के आमजन पर पड़े, यह स्वाभाविक बात नहीं हो सकती। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी से कई और अन्य वस्तुओं पर भी महंगाई का असर पड़ना तय है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के कारण भारत में इस समय मुद्रास्फीति चरम पर है। कुछ दिनों से ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता चल रही है, विचार-विमर्श का आदान-प्रदान हो रहा है। मगर कुछ भी हल सामने नहीं आ रहा। अभी जिस तरह की जटिल परिस्थितियां बनी हुई हैं, उससे मुद्रास्फीति नीचे आने का नाम नहीं ले रही। आम जनता को कहीं से कोई राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही। लिहाजा वर्तमान चुनौतियों का समाधान निकालने की जरूरत है। आर्थिक पहलुओं पर चर्चा होनी चाहिए।

– शाहिद हाशमी, जाकिर नगर, दिल्ली

प्रकृति के साथ

प्रारंभिक दौर में मनुष्य का जीवन पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। जैसे-जैसे उसका विकास होता गया, उसने जीवन जीने के स्तर को सुधारा। इसी क्रम में मनुष्य स्वयं को सशक्त बनाने की होड़ में पर्यावरण की ओर ध्यान देना ही भूल गया। इसका अब खमियाजा समय-समय पर भुगतना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा, अकाल, अत्यधिक बारिश और बाढ़ जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। प्राकृतिक आपदाओं ने न केवल मनुष्यों को बल्कि अन्य जीव-जंतुओं को भी क्षति पहुंचाई है। इससे मानव और प्रकृति के बीच संतुलन बिगड़ता चला गया है। दुख इस बात का है कि इन सबके बावजूद मनुष्य पर्यावरण के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहा है। हमें यह समझने की जरूरत है कि बिना प्रकृति के मनुष्य का जीवन संभव नहीं। इसलिए जितना जल्दी हो सके, इसके क्षरण को बंद करना होगा।

– संजू तैनाण, चौबारा, हनुमानगढ़

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

लोकमानस

loksatta@expressindia.com

ठेवींवरील व्याजदर वाढवण्याचा विचार कधी?

''**रिझर्व्ह' कोणासाठी?'** हा अग्रलेख (२५ मे) वाचला. यंदाच्या वर्षी रिझर्व्ह बँक केंद्र सरकारला विक्रमी म्हणजेच दोन लाख ८७ हजार कोटी रुपयांचा डिव्हिडंड देणार आहे, हे वाटीतील ताटात देण्यासारखेच नाही का? इतका मोठा डिव्हिडंड कमवायला रिझर्व्ह बँक व्यापारी, व्यावसायिक बँक आहे का? देशातील प्रत्येक बँक आणि आर्थिक संस्था आपले ताळेबंद पूर्ण झाल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेला लाभांश देत असते, इतके की त्यांच्या-त्यांच्यामध्येच मोठी स्पर्धा लागलेली असते आणि त्याचे फोटोज विविध वर्तमानपत्रांतून प्रसिद्ध होतात? बाकीच्या बँका व्यवसाय करून नफा मिळवत असतात तसे रिझर्व्ह बँकेचे काम बाकीच्या बँकांवर नियंत्रण ठेवणे असते, तरीदेखील रिझर्व्ह बँक केंद्र सरकारला लाभांश देते ही गोष्ट नवल वाटण्याजोगीच. या लाभांशाचा उपयोग केंद्र सरकार कसा करते ही गोष्ट सर्वसामान्य जनतेला कळत नाही?

गेल्या काही वर्षांपासून देशातील ८० हजार लोकांना मोफत धान्यवाटप, लाडक्या बहिणींना महिना रोख रक्कम, रेवडी संस्कृतीसारख्या अनुत्पादक गोष्टींसाठी खर्च करते ही गोष्ट धोकादायक नाही का? रिझर्व्ह बँक वारंवार रेपो रेट्स ठरवण्यासाठी मीटिंग्स घेत असते आणि त्यावरून देशाचा जीडीपी, घाऊक आणि रिटेल महागाई नियंत्रण करत असते. या रेपो रेट्सवरूनच व्यावसायिक बँका, कर्जाचे व्याजदर आणि ठेवीवरील व्याजदर ठरवतात. रिझर्व्ह बँकेने हा लाभांश कर्जाचे कमी व्याजदर आणि बँकेच्या ठेवींवरील व्याजदर, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांच्या ठेवींवरील व्याजदर जास्त ठेवण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांचे जीवन सुखदायक होईल. रिझर्व्ह बँक काही रक्कम हे व्याजदर वाढवण्यासाठी ठेवण्याचा विचार कधी करणार? पूर्वी बँकेतील अधिकाऱ्यांना ठेवी मिळवण्यासाठी अक्षरशः घाम गाळावा लागत होता. आता ते ठेवींबाबत निर्धास्त असतात. कारण त्यांना माहिती आहे की ज्येष्ठ नागरिकांसारखे ग्राहक बँकेकडे स्वतःच येतात. शेतमालाला चांगला दर, महागाई नियंत्रण यासाठी या लाभांशाचा थेट उपयोग झाला तर सर्वसामान्य जनतेचाही दुवा मिळाला असता.

■ **शुभदा गोवर्धन,** ठाणे

केंद्राला हक्काचे पैसे मिळण्यात गैर काय?

''**रिझर्व्ह' कोणासाठी?'** हा अग्रलेख (२५ मे) वाचला. बँकिंगमध्ये रिझर्व्ह फंड अर्थात राखीव निधी किती असावा याचे निकष ठरलेले आहेत. कोणतीही संस्था त्या निकषांकडे दुर्लक्ष करत नाही आणि रिझर्व्ह बँकदेखील ते करूच शकत नाही. जो लाभांश रिझर्व्ह बँकेने केंद्र सरकारकडे वर्ग केला तो झालेल्या नफ्यातून सर्व वैधानिक तरतुदी केल्यानंतर उर्वरित रक्कम लाभांश म्हणून वर्ग झाली आहे आणि हे योग्यच आहे. २०१४ पासून केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधांवर भर दिला असून आजतागायत सरकारवर भ्रष्टाचाराचा आरोप झालेला नाही. तसेच संरक्षण साहित्य खरेदी करून सरकारने देशाची सुरक्षा व्यवस्था मजबूतच केली आहे. ज्या पैशावर केंद्र सरकारचा हक्क आहे तो केंद्राला मिळण्यात गैर काहीही नाही.

■ **उमेश मुंडले,** वसई

काँग्रेसला स्पष्ट भूमिका घ्यावी लागेल

'**शिवसेना-राष्ट्रवादी** काँग्रेसनंतर उरणार कोण?' हा महेश सरलष्कर यांचा लेख वाचला. महाराष्ट्रातील प्रादेशिक पक्ष कमकुवत होतच जातील अशी सध्याची परिस्थिती आहे. यामुळे काँग्रेस पक्षाला विस्तार करण्यासाठी भरपूर वाव आहे. पण पक्षातील मुख्य अडचण म्हणजे हे लोक जय-पराजयाचा सखोल अभ्यास करत नाहीत, असे दिसते. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे बेरोजगारी-महागाईबाबत पक्ष काय भूमिका घेणार, हे जनतेला कळत नाही. नुसते सरकारवर कशीही टीका केल्याने जनता जवळ येत नाही हे पक्षाच्या धुरीणांना कळल्यास बरे होईल.

■ **सां. रा. वाठारकर,** चिंचवड

कसली आलीय काटकसर?

'**न्यायमूर्तींना २० हजार** युनिट वीज मोफत' ही बातमी वाचली. वर्षाला २०००० युनिट मोफत वीज. महिन्याला २०० लिटर पेट्रोल. हे कमी म्हणून की काय स्वतःचा आणि पती/पत्नीचा चष्मा घेण्यासाठी, त्याची निगा राखण्यासाठी ५० हजार रुपये. पन्नास हजारांचा असा कुठला चष्मा असतो आणि एकदा तो घेतला की त्याची अशी कोणती निगा राखावी लागते? या सुविधा बघून जीव भरून आला. सर्वसामान्य माणूस दोनशे-तीन वीज युनिट बिल भरताना मेटाकुटीला येतो. महिन्याला वीस लिटर पेट्रोलसाठी दोन हजार रुपये देतो. (वीस लिटर पेट्रोलमध्ये जवळपास ३००/ ३५० किमी प्रवास होतो. माय लॉर्ड महिन्यात २०० लिटर पेट्रोल भरून कुठे बरे जात असतील?)

काटकसरीचा सल्ला सर्वसामान्यांना देण्यात येतो, पण राज्यातील न्यायमूर्तींना सुविधा खर्च वाढवून देणाऱ्या राज्य सरकारने, माय लॉर्ड मंडळींसाठी कसली आलीय काटकसर, असा विचार केला असावा!

■ **डॉ. संजय पालीमकर,** दहिसर पूर्व, मुंबई

असा विकास आत्मघातकी ठरेल...

'**वृक्षवल्लींना आपण** खरेच सोयरे मानतो का?' हा निवृत्त न्यायमूर्ती अभय ओक यांचा लेख (रविवार विशेष, २४ मे) डोळ्यात अंजन घालणारा आहे. आज विकासाच्या नावाखाली सामान्य जनतेचा विचार न करता, केवळ सिमेंट काँक्रीटचे जंगल उभे केले जात आहे. पण या तथाकथित प्रगतीचा खरोखर कोणाला फायदा होतो? आपण विसरतो की, एक मोठा वृक्ष म्हणजे केवळ लाकूड नाही, तर ती स्वतः एक संपूर्ण 'इकोसिस्टीम' असते. त्यावर शेकडो पक्षी, कीटक आणि जीवजंतूंचे जग अवलंबून असते. झाड तोडताना आपण संपूर्ण जैवविविधता धोक्यात आणतो.

सध्याच्या सरकारची इंधन बचतीची पावले प्रशंसनीय असली तरी दुसरीकडे सुरू असलेली ही 'हरित कत्तल' अत्यंत विरोधाभासी आहे. सुट्टी घालवायला नॉर्थ-ईस्ट किंवा परदेशात जाणाऱ्या आपण, महाराष्ट्राला पाच वर्षांत समृद्ध वनसंपदेने नटवण्याचा आराखडा का नाही आखू शकत? लेखात म्हटल्याप्रमाणे, ठाणे-मुंबईचे तापमान ४५ अंशांच्या पुढे जाण्याची भीती असताना, ते ३५ च्या घरात आणण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न का होत नाहीत? संत तुकारामांनी ज्यांना 'सोयरे' म्हटले, त्यांचाच गळा घोटून होणारा विकास हा आत्मघातकी आहे. आता निव्वळ चर्चा नको, तर ठोस कृतीची गरज आहे!

■ **सीए देवेन्द्र जैन,** अंबरनाथ

शिक्षणात कळपाची मानसिकता धोकादायक

'**तरक्कीतलं तंतरणं**' हा 'अन्यथा' सदरातील लेख (१६ मे) वाचला. मी १९७२ ते २००५ पर्यंत शिक्षण/ संशोधन आणि केमिकल उद्योग क्षेत्रात (सल्लागार) होतो. २००५ डिसेंबरला यूडीसीटी (आताची आयसीटी) मधून केमिकल इंजिनीअरिंगचा विभागप्रमुख म्हणून निवृत्त झालो. लेख वाचून काही लिहावेसे वाटले. ट्रम्प साहेबांच्या दुसऱ्या मुदतीआधी विद्यापीठांना भरपूर निधी मिळत असे. त्यामुळे आमची किमान ४० टक्के मुले शिष्यवृत्तीसह अमेरिकेत जात. आता हे प्रमाण २० टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे आणि तेही डॉक्टरेट करिताच. ज्यांना शिष्यवृत्ती मिळत नाही ते स्वतःच्या खर्चाने जातात. आता अमेरिकेत नोकरीसाठी व्हिसा कठीण झाल्यामुळे काही बदल नक्कीच अपेक्षित आहेत. बरीच मुले नामांकित भारतीय संस्थांमधून एमबीए आणि त्यानंतर लठ्ठ पगाराच्या नोकऱ्या तसेच पण कमी प्रमाणात यूपीएससीकडे वळतात.

इंजिनीअरिंगमध्ये कंत्राटी प्रकार वाढला आहे, पण हा प्रकार फार मोठ्या प्रकल्पांपुरता मर्यादित आहे. उदाहरणार्थ, रिफायनरी, रासायनिक खते, इ. मध्यम आणि लहान प्रकल्पांत प्रोसेस डेव्हलपमेंट आणि अंमलबजावणी एक तर प्रवर्तक स्वतः करतात वा भारतीय कंपन्यांना कंत्राट देतात. भारताची शोधपरंपरा परकीय आक्रमणांनंतर जवळपास संपली. पण आविष्काराबाबत कुठेच कमी नाही. औषध कंपन्यांनी यात बाजी मारली आहे. पेटंट नसलेल्या औषधांची निर्मिती करून निर्यात करण्यात चांगली कामगिरी केली आहे. यात आविष्काराचे योगदान वाखाणण्याजोगे आहे. नोकरीच्या सुरुवातीला पगारातील विरोधाभास जाणवू शकतो, पण चांगला इंजिनीअर काही वर्षांतच आपल्या अक्कलहुशारी आणि अनुभवाच्या जोरावर लाखोपर्यंत पोहोचतो अशी खूप उदाहरणे आहेत.

सगळ्यात नुकसान होते ते कळप मानसिकतेमुळे. गेली २० वर्षे तरी संगणक शाखेकडे ओढा एवढा वाढला आहे की दुसऱ्या बेसिक शाखांच्या सीट पूर्ण भरत नाहीत. आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता आल्यावर अति तेथे माती होईल. इतर शाखांची संख्या रोडावल्यामुळे त्या इंडस्ट्रीजमध्ये मुले मिळत नाहीत. ह्युस्टनसारख्या तेल व नैसर्गिक वायूच्या राजधानीत केमिकल इंजिनीअर्सची वानवा आहे.

■ **विश्वास पांगारकर,** नाशिक

भारताची दशकभरातील प्रगती लक्षवेधक

जगावर वित्तीय मंदीचे सावट पसरले असताना भारताची अर्थव्यवस्था मात्र वेगाने प्रगती करत आहे. पूर्वी अत्यंत दुर्बळ असलेला आपला देश आज जगातील चौथ्या क्रमांकाची सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था ठरला असून तिसऱ्या क्रमांकाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. आपली आर्थिक प्रगतीही सर्वसमावेशक आहे...

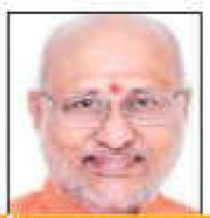

सी. पी. राधाकृष्णन
भारताचे उपराष्ट्रपती

पहिली बाजू

जेव्हा मी तिरुप्पुर इथे एक विद्यार्थी म्हणून शाळेत शिकत होतो, त्या वेळी माझी माझ्या देशाविषयी अनेक स्वप्ने होती. माझ्या मनात सतत प्रश्न येत असतः भारत आपले वैभव पुन्हा केव्हा प्राप्त करेल? जागतिक पटलावर शक्तिमान देश म्हणून भारताचा उदय केव्हा होईल? आपल्या देशातील गरीब आणि वंचित मुलांना प्रतिष्ठेचे आयुष्य कधी जगता येईल? मला आज याचा अत्यंत आनंद आहे, की माझ्या बालपणी केवळ माझ्या मनात येत असलेले विचार आता प्रत्यक्षात उतरत आहेत.

मी स्वतः कायम, स्वामी विवेकानंदांच्या वचनांचे स्मरण स्वतःला करून देतो. ते म्हणत, ''उठा, जागे व्हा आणि आपले उद्दिष्ट साध्य होत नाही, तोपर्यंत थांबू नका''. तमिळनाडूच्या भूमीवरून स्वामी विवेकानंदांनी काढलेल्या या उद्गारांमध्ये देशभक्ती आणि समजाविषयीची कटिबद्धता जागृत करण्याची ताकद आहे. जेव्हा भारताचे संपूर्ण सामर्थ्य जागृत होईल, त्या वेळी आपल्या देशात जगाला मार्गदर्शन करण्याची क्षमता निर्माण होईल. गेल्या दशकात, देश उत्साह आणि दृढनिश्चयाने कार्यरत झाला आहे. संत थिरुवल्लूवर यांनी सांगितलेले सत्य आपल्या डोळ्यांसमोर साकार होताना बघण्याची संधी आज आपल्याला लाभली आहे. ''जे आपल्या दृढनिश्चयात पक्के असतात, त्यांनाच, त्यांनी पाहिलेली स्वप्ने पूर्ण करण्यात यश मिळते,'' गेल्या दशकात, भारताने जगाचे लक्ष वेधणारी प्रगती साध्य केली आहे.

आज जगावर मंदी आणि अनिश्चिततेचे सावट पसरले असताना भारताची अर्थव्यवस्था मात्र, वेगाने प्रगती करत आहे. सरकार आणि जनतेचा उत्साह, हेच या प्रगतीमागचे कारण आहे. एका अत्यंत दुर्बळ अस्थिर अर्थव्यवस्था असलेला आपला देश आज जगातील चौथ्या क्रमांकाची सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था ठरला असून लवकरच तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था ठरण्याच्या मार्गावर आहे. आपली आर्थिक प्रगतीही सर्वसमावेशक आहे.

गेल्या एका दशकात सुमारे २५ कोटी भारतीय गरिबीतून वर आले असून आज ते प्रतिष्ठेचे जीवन जगत आहेत. बेघर लोकांठी चार कोटी घरे बांधण्यात आली आहेत. १२ कोटी लोकांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येतो आहे. आपण भारताला ६० महिन्यांत उघड्यावर शौचाच्या शापातून मुक्त करण्याचा संकल्प केला होता आणि ६० कोटी लोकांनी तो पूर्णही केला. 'पंतप्रधान गरीब कल्याण योजने' अंतर्गत २.३ कोटी रुपये खर्चून ८० कोटी नागरिकांना पाच किलो धान्य मोफत दिले जात आहे.

मी अगदी तरुण वयापासून पाहिले होते, की ग्रामीण भागांत पुरेशा वैद्यकीय सुविधा नसतात. तेथील रुग्णांच्या वेदना पाहून दुःख होत असे. आज आपल्या देशात, 'आयुष्मान भारत योजना' लागू केली जात असून, त्याद्वारे देशातील प्रत्येकाला, आरोग्यविषयक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. परिणामी ४४ कोटी लोकांना आज पीएम-आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत, प्रत्येक पाच लाख रुपयांचा विमा मिळाला आहे. गेल्या केवळ एका वर्षात अडीच कोटी लोकांना, या योजनेअंतर्गत मोफत वैद्यकीय उपचार मिळाले आहेत.

शेतकऱ्यांनी, कठीण परिश्रम करून, देशात ३५० दशलक्ष टन अन्नधान्य उत्पादन केले आहे, ज्यामुळे भारत, जगात अन्नधान्याचा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वांत मोठा उत्पादक ठरला आहे. भारताने जगातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या तांदूळ उत्पादक देश म्हणून स्थान मिळवले आहे. देशातील स्त्री शक्तीला आता देशाच्या प्रगतीत आपले संपूर्ण योगदान देण्याच्या संधी खुल्या झाल्या आहेत. तीन कोटींपेक्षा अधिक महिला आता 'लखपती दीदी' आणि 'नमो ड्रोन दीदी' झाल्या आहेत. कृषी, औषध निर्माण, विज्ञान, तंत्रज्ञान, अंतराळ तंत्रज्ञान अशा सर्वच क्षेत्रांत महिला पुढे येत आहेत. आता सैन्यदलांमध्येही महिलांना कायमस्वरूपी पदे मिळत आहेत, त्या युद्धजन्य कारवायांमध्येही सहभागी होत आहेत. 'नारी शक्ती वंदन अधिनियम' लागू झाल्यामुळे संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये, महिलांचा सहभाग वाढणार आहे. देशभरात सुमारे दोन कोटी एलपीजी गॅस जोडण्या देण्यात आल्या आहेत.

जेव्हा आपण युवा पिढीला उत्साहाने स्टार्टअप्ससाठी पुढे येताना बघतो, त्या वेळी मला राष्ट्रभक्त कवी सुब्रह्मण्यम भारती यांची कविता आठवते- ''या, या, या आणि तुम्ही पाहिलेली स्वप्ने पूर्ण करा; संपूर्ण देश एकोपा आणि समृद्धीसह उदयाला येऊ दे; या, या, या आणि काही भव्यदिव्य साकार करा.'' युवकांसाठी १३ नव्या आयआयटी देशात केवळ गेल्या १० वर्षांत स्थापन झाल्या, त्यामुळे देशातल्या आयआयटीची संख्या २३ पर्यंत पोहोचली आहे. आयआयएम संस्थांची संख्याही, १३ वरून २१ पर्यंत वाढली आहे. तर एम्सची संख्याही तिपटीने वाढून, सातपासून २३ पर्यंत पोहोचली आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या, ३८७वरून ८२३वर आणि वैद्यकीय शिक्षणाच्या जागा ५१ हजार ३४८ वरून एक लाख, २९ हजार ६०३ वर पोहोचल्या आहेत.

आपण आज जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधाही उभारतो आहोत. रेल्वेचे विद्युतीकरण जवळपास ९९ टक्के पूर्ण झाले आहे. देशभरात, १६४ वंदे भारत एक्स्प्रेस गाड्या सुरू झाल्या आहेत. विमानतळांची संख्या ७४ वरून १६३ पर्यंत, म्हणजे दुपटीने वाढली आहे, तसेच 'उडान योजने'मुळे, सर्वसामान्यांना विमानप्रवास करणे शक्य झाले आहे.

तमिळनाडूसाठी एका दशकापूर्वी, रेल्वेची आर्थिक तरतूद ८८० कोटी रुपये इतकी असे, ती आता, वर्ष २०२६-२७ मध्ये, ७,६०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे. तमिळनाडूमध्येच रामेश्वरम आणि पंबन दरम्यान देशातला पहिला व्हर्टिकल लिफ्ट असलेला नवा पंबन पूल साकारला जाणे, ही तिथल्या जनतेसाठी आनंदाची आणि अभिमानाची बाब आहे. हा पूल, आध्यात्मिक पर्यटन आणि आर्थिक विकासाच्या नव्या संधी घेऊन येणारा आहे. मग जम्मू आणि काश्मीरमधला चिनाब पूल असो वा आसामचा बोगीबिल पूल भारत अद्भुत पायाभूत सुविधांची उभारणी करत आहे.

भारतभर जागतिक दर्जाचे महामार्ग उभारण्यात आले असून, अगदी दुर्गम गावांपर्यंतही रस्ते संपर्क मजबूत करण्यात आला आहे. तमिळनाडूमध्ये गेल्या १० वर्षांत चार हजार किलोमीटरहून अधिक लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गांची उभारणी करण्यात आली आहे. तर ईशान्येकडील राज्यांमध्ये गेल्या १० वर्षांत सुमारे ७,२०० किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्गांची निर्मिती झाली आहे. पंतप्रधान स्वतः 'प्रगती' या मंचाअंतर्गत या कामावर बारीक देखरेख ठेवत असल्यानेच ही विकासकामे शक्य झाली आहेत.

पूर्व-माध्यमिक आणि उत्तर-माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजनांचा अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना मोठा लाभ मिळत आहे, तर एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांमुळे अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांना फायदा झाला आहे. सीमावर्ती गावे, जी पूर्वी भारतातील शेवटची गावे मानली जात होती, ती आता भारतातील पहिली गावे ठरली आहेत आणि त्यांचा विकास 'व्हायब्रंट व्हिलेजेस योजने' अंतर्गत केला जात आहे. मला आठवते, पंतप्रधानांनी ईशान्येकडील राज्यांना देशाची 'अष्टलक्ष्मी' म्हणून संबोधले होते. अलीकडेच मी नागालँड, मिझोराम, त्रिपुरा आणि सिक्कीम या राज्यांना भेट दिली असता तिथे वाहतूक सुविधा तसेच पायाभूत सुविधांमध्ये झालेली मोठी प्रगती मला पाहायला मिळाली.

विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष यात देशाने साधलेली प्रगती आपला ऊर अभिमानाने भरून टाकणारी आहे. आज तंत्रज्ञानापासून वैद्यकीय क्षेत्रापर्यंत प्रत्येक क्षेत्र झपाट्याने प्रगती करत आहे. कोविड-१९ साथीच्या काळात भारताने लस विकासाच्या प्रयत्नांमध्ये आघाडी घेतली आणि स्वदेशी लशी विकसित करून त्या अतिशय वेगाने सर्वांना मोफत उपलब्ध करून दिल्या. भारताने मानवतावादी दृष्टिकोनातून जगातील १०० हून अधिक देशांना लशी पुरवल्या- भारताची ही कृती जागतिक इतिहासात नोंदली गेली आहे.

'चांद्रयान-३'च्या यशस्वी प्रक्षेपणामुळे भारताने अवकाश संशोधनाच्या नव्या युगात प्रवेश केला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात जागतिक कंपन्या भारताला आपले केंद्र म्हणून निवडत आहेत, ज्यामुळे गुंतवणुकीत अनेकपटींनी वाढ होत आहे. सेमीकंडक्टर उत्पादन क्षेत्रातही भारत जगासाठी एक आदर्श म्हणून उदयास येत आहे. मोबाइल फोन उत्पादनातही आपण जागतिक स्तरावर दुसरे स्थान मिळवले आहे. एकेकाळी मोबाइल फोन आयात करणारा आपला देश आज ३०० कोटी अमेरिकन डॉलर्स किमतीचे मोबाइल फोन निर्यात करत आहे. ही सर्व यशस्वी कामगिरी पुढच्या पिढीसाठी समृद्ध भविष्याचा मजबूत पाया ठरणार आहे.

अनेक दशकांपासून आपल्या देशासमोर केवळ दहशतवादाचेच नव्हे, तर फुटीरतावादी चळवळी आणि डाव्या विचारसरणीच्या नक्षलवादाचेही आव्हान उभे होते. धाडसी धोरणात्मक निर्णय आणि कायद्याचे प्रभावी पालन यांमुळे आज देशात शांतता प्रस्थापित झाली असून, या हिंसाग्रस्त भागांमध्येही विकासाची दारे खुली झाली आहेत.

स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षापर्यंत आपण विकसित देश म्हणून अग्रगण्य महासत्ता बनावे आणि जगाला दिशा दाखवणाऱ्या स्थानावर पोहोचावे, असे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर निश्चित केले आहे. कठोर परिश्रमाचा हा काळ म्हणजेच 'अमृत काळ' आहे. ज्या प्रकारे त्या वेळी प्रत्येक स्वातंत्र्यसैनिकाच्या हृदयात स्वातंत्र्याची तळमळ होती, त्याचप्रमाणे आजच्या तरुणांच्या मनात देशाच्या विकासाचा विचार दृढ झाला पाहिजे. त्यातून उच्च आदर्श आणि चारित्र्यसंपन्न व्यक्तिमत्त्व म्हणून युवाशक्ती पुढे आली, तर २०४७ मध्ये आपण विकसित भारताचे स्वप्न साकार झालेले पाहू शकू.

या काळात ''माझ्या बंधूंनो, आपण सर्व कठोर परिश्रम करूया. ही निद्राधीन होण्याची वेळ नाही. भारताचे भविष्य आपल्याच प्रयत्नांवर अवलंबून आहे,' हे स्वामी विवेकानंदांचे शब्द-आपल्याला प्रेरणा आणि दिशा दोन्ही देतात. चला, आपण सर्व जण आपल्या कठोर परिश्रमांतून विकसित भारत घडवण्यासाठी एकत्र काम करू या.

कुतूहल

खेळानुसार बुटाचा तळ का बदलतो?

जेव्हा कोणतेही दोन पृष्ठभाग एकमेकांच्या संपर्कात येतात, तेव्हा त्यांच्यात नेहमीच घर्षण होत असतं. त्यातही त्यातला एक किंवा दोन्हीही पृष्ठभाग जर गतिशील असतील तर त्या वेळी हे घर्षणबल नेहमीच गतीच्या विरुद्ध दिशेने कार्यरत असतं.

एखादी वस्तू जेव्हा कोणत्याही पृष्ठभागावर गतिमान होत असते, तेव्हा तिच्या गतीवर घर्षणाचा फार मोठा परिणाम होत असतो. कारण पृष्ठभाग ओबडधोबड असेल तर घर्षणबल जास्त आणि परिणामी गतीला विरोध जास्त! याउलट पृष्ठभाग जेवढा गुळगुळीत तेवढं कमी घर्षण, कमी विरोध आणि म्हणून वस्तूची गती जास्त!

घर्षणामुळे चालताना पायांना जमिनीवर पकड मिळवता येते. जेवढं घर्षण जास्त तेवढा चालण्याचा वेग कमी! कधीही खडबडीत पृष्ठभागावर चालणं हे गुळगुळीत पृष्ठभागावर चालण्यापेक्षा सोपं असतं. गुळगुळीत पृष्ठभागावर फारसं घर्षण नसल्यामुळे वेग वाढून, घसरून पडण्याची शक्यता असते. म्हणून तर केळीच्या गुळगुळीत सालीवरून पाय सरकून आपण सपशेल आडवे होतो.

कोणत्याही खेळात पायांची जमिनीवरची पकड महत्त्वाची असते. मात्र आपण पाहतो की ही पकड पुरवणारे खेळाडूंचे बूट खेळानुसार बदलतात. विशेषतः त्या बुटांचे तळवे!

बुटाचे तळवे हे खेळाच्या आवश्यकतेनुसार घर्षण पुरवण्यासाठी तयार केलेले असतात. क्रिकेट आणि फुटबॉल यांसारखे खेळ थोडाफार पाऊस आला तरी चालू राहतात. अशा वेळेस निसरड्या झालेल्या मैदानावर पायांची पकड सहजी जाऊ नये यासाठी खेळाडूंच्या बुटांच्या तळव्यांना खिळे किंवा छोटे उंचवटे असतात. मात्र टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, बॅडमिंटन यांसारख्या खेळांत खेळाडूंना सपाट आणि तुलनेने गुळगुळीत पृष्ठभागावर चपळ हालचाली कराव्या लागतात. अशा वेळेस खेळाडूंना कमी वेळात करावे लागणारे दिशाबदल आणि वेगातले चढउतार नियंत्रित करण्यासाठी जास्त घर्षणाची गरज असते. म्हणून या खेळांत वापरल्या जाणाऱ्या बुटांचे तळवे सपाट आणि रबरापासून बनवलेले असतात. एखादा खोडरबर काचेसारख्या एखाद्या गुळगुळीत पृष्ठभागावर फिरवून पाहिल्यास आपल्या हे लक्षात येईल.

धावपटूंना मात्र इतकं घर्षण उपद्रवी ठरतं. त्यांना जरी वेगानं धावावं लागत असलं तरी त्यांना आपल्या दिशेत पटापट बदल करावा लागत नाही. त्यामुळे त्यांना वेगाशी तडजोड न करता धावण्याच्या ट्रॅकवरची पकडही सुटणार नाही इतपतच घर्षणाची गरज असते. म्हणून धावपटूंच्या बुटांचे तळवे नक्षीदार रबराचे असतात. थोडक्यात, जिथे जास्त वेग हवा असतो तिथे जमिनीबरोबर कमी घर्षण करणारे बुटांचे तळवे तर जिथे वेग कमी आणि पकड अधिक हवी असेल तिथे खडबडीत म्हणजेच जास्त घर्षण करणारे बुटांचे तळवे वापरणं गरजेचं ठरतं!

– **सुमेध सावंत**
मराठी विज्ञान परिषद
ईमेल : office@mavipa.org
संकेतस्थळ : www.mavipa.org

उलटा चष्मा

गर्दीचे 'शिखर'

शिखर गाठण्याचे *स्वप्न पाहणाऱ्या गिर्यारोहकांनो, सुवर्णसंधी, सुवर्णसंधी, सुवर्णसंधी! तुम्ही सर्व जाणताच की यंदा म्हणजे २२ मे रोजी तब्बल २७४ गिर्यारोहकांनी एकाच वेळी एव्हरेस्ट शिखर सर केले. हा विक्रम आहे. आता दरवर्षी असेच नवनवे विक्रम या शिखरावरील चढाईच्या बाबतीत नोंदवले जाणार याविषयी आमच्या मनात कसलीही शंका नाही. कुठल्याही यशाच्या बाबतीत कायम नाक मुरडणाऱ्या काहींनी यंदा शिखरावर झालेल्या गर्दीवर टीका केली असून याचेही बस स्थानक वा विमानतळ करून टाकले असा टोमणा मारला आहे. या टीका-टोमण्यांकडे दुर्लक्ष करून ध्येयप्राप्तीसाठी झटणाऱ्या गिर्यारोहकांच्या पाठीशी उभे राहणे आमचे कर्तव्य आहे. या वेळी शिखर गाठण्याच्या अंतिम टप्प्यात झालेल्या गर्दीमुळे 'थोडी' चेंगराचेंगरी झाली व त्यात पाच जणांचा मृत्यू झाला. त्यातले दोघे भारतीय होते.*

हे शिखर सर करताना आठ हजार मीटर उंचीवर 'डेथ झोन' सुरू होतो. प्राणवायूच्या कमतरतेमुळे इथे जास्त काळ राहणे कठीण असते. त्यामुळे या झोनपासूनचा पुढचा ८४९ मीटरचा टप्पा लवकर पूर्ण करून खाली येणे गरजेचे असते. अरुंद वाट, त्यात गर्दी व प्राणवायूच्या कमतरतेमुळे अनेकांना हे अंतर लवकर पार करता आले नाही. त्यामुळे काहींचा श्वास कोंडला तर दोघांचा मृत्यू झाला. या मृतांबद्दल पूर्णपणे संवेदना व्यक्त करून नव्यानेच स्थापन झालेल्या आमच्या संस्थेने 'गर्दीत शिखर कसे गाठायचे' असा प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू केला आहे. दर नाममात्र आहेत. इच्छुकांनी यात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन आम्ही या माध्यमातून करत आहोत. गिर्यारोहणाचा सराव केलेल्यांनी यात सहभागी व्हावे अशी संस्थेची इच्छा आहे. सहभागींना देशातील गर्दीच्या ठिकाणी प्रशिक्षण देण्यात येईल. मुंबईची लोकल, बस स्थानक, विमानतळावरील गर्दीची वेळ बघून त्यात कसे शिरायचे, इतरांना धक्के देत समोर कसे जायचे, इच्छित ठिकाण सर्वांत आधी कसे गाठायचे, असे या प्रशिक्षणाचे स्वरूप असेल. अशा ठिकाणी प्राणवायू मिळतो पण कमी प्रमाणात. त्यामुळे इच्छुकांना त्याचीही सवय होईल. एव्हरेस्टवरील चढाईची वाट कमालीची अरुंद आहे. अशा वाटेवर कधी खांद्याने धक्का देत तर कधी पाय अडकवत इतरांना मागे ढकलून समोर कसे जायचे हेही यात शिकवले जाईल. महाभारतातील पांडव व द्रौपदी राजसंन्यास घेतल्यावर हिमालयाच्या मार्गाने स्वर्गाकडे प्रस्थान करते झाले. ते जसे वर जाऊ लागले तसे मृत्युमुखी पडू लागले. टिकले फक्त युधिष्ठिर! या माध्यमातून प्रत्येक गिर्यारोहकाला आधुनिक युधिष्ठिर बनवण्याचे आमचे स्वप्न आहे. हिमालयात तेव्हाही प्राणवायूची कमतरता असावी व आताही आहे. फक्त वाढली ती गर्दी! त्यावर कशी मात करायची हेच आम्ही या माध्यमातून शिकवणार आहोत. शेर्पांनासुद्धा आम्ही प्रशिक्षण देणार आहोत. त्यासाठी नेपाळमधून नोंदणीसुद्धा करून घेतलेली आहे.

गर्दीतून वाट काढत इच्छित ध्येय गाठणे हे किमान भारतात तरी अत्यावश्यक झाले आहे. त्यामुळे शिखर सर केल्यावरही नंतरच्या आयुष्यात तुम्हाला याचा फायदाच होईल याविषयी आमच्या मनात तिळमात्र शंका नाही. एकाच दगडात अनेक एव्हरेस्ट गाठण्याच्या या संधींचा सर्व गिर्यारोहकांनी लाभ घ्यावा व पुढील वर्षीच्या मे महिन्यात एव्हरेस्टवर मोठ्या संख्येने गर्दी करून नवा विक्रम नोंदवावा, असे आवाहन संस्थेतर्फे सर्वांना करण्यात येत आहे.

राजवाडे विचारविश्व

प्रागतिकता आणि सर्वसमावेशकता

'**समाजाच्या चरित्रातील** गत गोष्टींची जी हकीकत ती इतिहास होय. मग ती गोष्ट होऊन एक दिवस झालेला असो किंवा हजार वर्षे झालेली असोत. मानवसमाजाचे अखिल चरित्र हा इतिहासाचा विषय व वर्तमान क्षणाच्या पाठीमागील सर्व गतकाल हा त्याचा प्रांत... राजकीय उलाढाली घ्यावयाच्या व सामाजिक सोडावयाच्या किंवा हजार वर्षांपलीकडील हकीकत द्यावयाची व पाच वर्षा-अलीकडील टाकावयाची, असा संकुचित भेदभाव राहात नाही' हे स्पष्ट झाल्यावर राजवाड्यांनी दुसरी बाब चर्चेसाठी आणली. ती बाब होती स्थलविषयक.

त्या संदर्भातील इतिहासकारांचा कोटिक्रम कसा असतो, हे स्पष्ट करताना त्यांनी लिहिले, 'एकंदर मानवसमाजाचे वसतिस्थान ही विस्तीर्ण पृथ्वी आहे. तेव्हा त्याच्या इतिहासाच्या कक्षेत पृथ्वीवरील सर्व समाज आले पाहिजेत; मग ते समाज पूर्वेकडील असोत किंवा पश्चिमेकडील असोत. तत्त्वतः हे विधान सर्व इतिहासकारांस मान्य असते. परंतु कृतीत फारच फरक दिसतो. जगाचा इतिहास लिहिताना अथवा इतिहासाच्या तत्त्वांचे स्पष्टीकरणासह विवेचन करताना पौर्वात्य व पाश्चात्त्य असे समाज जमेत घेण्याचा आव हे इतिहासकार आणतात आणि साक्षात् कृतीत पाहावे, तर जुन्या व नव्या दहा पाच पाश्चात्त्य राष्ट्रांच्या इतिहासापलीकडे जात नाहीत. पूर्वेकडचे समाज स्थाणू (स्थिर) आहेत, त्यांना इतिहासच नाही, त्यामुळे त्यांना प्रागतिक देशांच्या इतिहासात गणता येत नाही, असा या लोकांनी लढवलेला कोटिक्रम असतो.'

त्यांनी स्पष्टीकरण दिले. 'गति दोन प्रकारची असते - अधम किंवा उत्तम. पैकी जी गति उत्तम तिला प्रगति म्हणतात. समाजाची उत्तम गति म्हणजे आत्यंतिक नीतिमत्तेकडे, आत्यंतिक बुद्धिमत्तेकडे व आत्यंतिक संपन्नतेकडे समाजाची जी प्रवृत्ति ती. या तीन मत्तांकडे जो समाज जात असतो, तो समाज प्रागतिक व जो जात नाही, तो अप्रागतिक. प्रागतिक अवस्था संपादन करण्याला मुख्य साधने पाश्चात्त्य समाजात दोन मानिली जातात - एक युयुत्सुता (=युद्धसज्जता) व दुसरे सुयंत्र राज्यव्यवस्था. ही दोन साधने ज्या समाजाने संपादिली नाहीत, त्या समाजाला प्रगतीच्या मार्गाला लागता येत नाही, अर्थात त्याला प्रागतिक म्हणताही येत नाही.'

पाश्चिमात्य इतिहासकारांनी केलेली 'ही व्याख्या भारतवर्षातील लोकांना काही अश्रुतपूर्व (पूर्वी कधी न ऐकलेली) नाही', असे सांगून राजवाड्यांनी पुढे लिहिले, 'राज्ययंत्र उत्तमोत्तम ठेवून व सैन्याच्या जोरावर अंतःस्थ व बहिःस्थ शत्रूंचा नाश करून धर्म, न्याय, नीती व स्वास्थ्य यांचा लाभ करून घेण्याकरता भारतीय आर्यांनी चातुर्वर्ण्याची पद्धत काढली, हे सुप्रसिद्ध आहे. क्षत्रियांनी व ब्राह्मणांनी सैन्याच्या जोरावर अंतःस्थ व बहिःस्थ शत्रूंचा नाश करून राज्ययंत्र काही काळ इतके सुव्यवस्थित ठेवले होते की सर्व शास्त्रांत गहन विचार करणारे तत्त्ववेत्ते आणि अखिल प्राणिमात्राला समबुद्धीने लेखणारे स्थितप्रज्ञ या पवित्र भूमीत उत्पन्न होऊन ऋद्धि व सिद्धि साक्षात अवतीर्ण झाल्या. समबुद्धीचा प्रकर्ष आर्यभूमीत त्या काळापासून इतका झाला की, शत्रू व मित्र यांच्याशी एकसारखे वागण्याचे वळण देशातील सर्व लोकांना लागले. त्यामुळे अपरिमित नुकसान झाले... परंतु सर्पाला दूध पाजून थोर नीतिमत्तेचा, अचाट बुद्धिमत्तेचा व अपार संपन्नतेचा घात होत आहे, असे अनुभवास आल्यावर कृतघ्न सर्पाचे दात पाडावयालाही आर्यांनी कमी केले नाही.'

सारांश सांगत मग राजवाड्यांनी लिहिले, 'उत्तम गतीकडे म्हणजे प्रगतीकडे जाण्याचे पाश्चात्त्य लोकांचे जे आधुनिक मार्ग आहेत, त्यांहून बरेच निराळे परंतु अत्यंत उदात्त मार्ग पूर्वेकडील भारतीयांचे फार पुरातन कालापासूनच आहेत. बौद्ध संस्कृती अंगात भिनलेल्या जपानी लोकांनी तर युरोपीय लोकांच्या लष्करवादी प्रगतीचा मार्ग अलीकडे फारच सुधारलेला आहे. अशा स्थितीत या पौर्वात्य देशांतील इतिहासाची गणना केल्याशिवाय इतिहासशास्त्राला संपूर्णता येणार नाही व इतिहासाचे समग्र तत्त्वदर्शनही होणार नाही.'

– **आनंद हर्डीकर**
anand47.hardikar@gmail.com

कार्य सिद्धीस नेण्यास...

अमेरिकी ‘ग्रीन कार्ड’साठीचा अर्ज आपापल्या देशांतून करण्याचा विचित्र आदेश दिल्यावर हे रुबियो भारताचे पाहुणे म्हणून आले आणि परस्पर काही घोषणा करते झाले...

सर्वसाधारण प्रथा अशी की आपल्या देशात येणारा परदेशीय मंत्री प्रथम त्या खात्याच्या भारतीय मंत्र्यांस भेटतो. उभयतांत चर्चा होते. आणि नंतर आवश्यकता असल्यास आलेला पाहुणा पंतप्रधानांसमोर सादर होतो. तथापि लोकशाहीत सर्व समान असले तरी ज्याप्रमाणे काही अधिक समान असतात त्याप्रमाणे पाहुण्यांबाबतही होत असावे. त्यामुळे अमेरिकेचे भारतभेटीवर आलेले परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो हे आल्या आल्या प्रथम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांस भेटले आणि नंतर दुसऱ्या दिवशी त्यांची समकक्ष मंत्री परराष्ट्र खात्याचे सुब्रमण्यम जयशंकर यांच्याशी चर्चा झाली. पाहुण्या परराष्ट्रमंत्र्याने भारतभेटीत आधी आपल्या परराष्ट्र मंत्र्यांस न भेटता थेट पंतप्रधानांना भेटणे हे काही राजनैतिक संकेतांस धरून झाले असे म्हणता येणार नाही. हा कालमहिमा. सगळ्यांनी सगळेच संकेत सोडणे सर्रास सुरू असताना एकटे रुबियो तरी त्यास कसे अपवाद ठरणार? एरवी याकडे दुर्लक्ष करता आले असते. पण हा संकेतभंग इतक्यापुरताच नाही.

मुद्दा रुबियो यांनी आधी आपल्या परराष्ट्र मंत्र्यांस टाळून थेट पंतप्रधानांची भेट घेतली आणि पंतप्रधानांनीही मनाचा मोकळेपणा दाखवत ती दिली इतकाच नाही. तर व्हेनेझुएलाच्या हंगामी अध्यक्षा डेल्सी रॉड्रिक्स या लवकरच भारतभेटीवर येणार असल्याची चुकीची सुवार्ता याच रुबियो यांनी परस्पर जाहीर करून टाकली. नंतर भारत हा आगामी काळात अमेरिकेकडून ५०,००० कोटी डॉलर इतक्या रकमेची विविध उत्पादने खरेदी करणार असल्याचेही भारतवासीयांस या पाहुण्याकडूनच कळाले. व्हेनेझुएलाच्या अध्यक्षा भारतभेटीवर येणार असत्या, त्यांच्या भेटीचे नियोजन उभय देशांकडून निश्चित झाले असते तर शिष्टाचार असा की त्याबाबतची अधिकृत घोषणा त्या देशांकडून व्हायला हवी होती. या संदर्भात ना भारताने काही वाच्यता केलेली आहे, ना व्हेनेझुएलाने. याचे कारण, ही संभाव्य भेट याआधीच रद्द झालेली आहे. पण भारताच्या भूमीवर येऊन हे रुबियो मात्र तिसऱ्या देशाचा प्रमुख लवकरच आपला पाहुणा होणार असल्याची चुकीची माहिती परस्पर देऊन टाकतात, हे अजब. याआधी व्हेनेझुएलाकडून भारत अधिक तेल खरेदी करणार असल्याची, आपल्या रिलायन्स समूहाकडून अमेरिकेत गुंतवणूक केली जाणार असल्याची इत्यादी घोषणा अमेरिकेने परस्पर करून टाकण्याचा इतिहास आहेच. त्यात या दोन गोष्टींची भर. या सगळ्याउप्पर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील युद्ध थांबल्याची, या दोन देशांत शस्त्रसंधी होत असल्याची घोषणाही अमेरिकेने या दोन देशांना न सांगता केली होती, ही बाब आहेच. भारत-पाक युद्ध आपण थांबवल्याचा दावा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आतापर्यंत किती वेळा केला याचे स्मरण या प्रसंगी अनावश्यक. पण ट्रम्प यांस नाही तरी त्यांच्या मंत्र्यांस आपल्याविषयी आपल्या अपरोक्ष अशा घोषणा करण्याबाबत आपल्या राज्यकर्त्यांनी काही कानपिचक्या दिल्या असत्या तर ते आपल्या राज्यकर्त्यांस आणि भारताच्या ‘ताकदी’स शोभून दिसले असते. पण तसे काही झाल्याची नोंद नाही. अमेरिकेस त्या देशाची जागा दाखवून देण्याची आणखी एक संधी आपण सोडली, इतकेच. यानंतर जयशंकर आणि रुबियो यांची संयुक्त पत्रकार परिषद झाली खरी. पण तो सर्व राजनैतिक देखावा. उभयतांत सर्व काही आलबेल असल्याचा आभास निर्माण करणारा. राजनैतिकता या असल्या आभासांवर चालत असते.

नपेक्षा भारताच्या भूमीवर पाय ठेवण्याआधी अमेरिकेतील भारतीयांस सर्वाधिक फटका बसेल असा निर्णय रुबियो यांचे मंत्रालय घेते ना. त्या देशाचे औद्धत्य असे की अमेरिकेतील ‘ग्रीन कार्ड’इच्छुकांस अमेरिका सोडण्याचा आदेश दिला आणि हे रुबियो भारताचे पाहुणे म्हणून आले. या ‘ग्रीन कार्ड’ निर्णयाचा सर्वात मोठा फटका अमेरिकावासी भारतीयांस बसणार हे उघड आहे. या निर्णयामुळे त्यांना अमेरिकेतील वास्तव्यासाठी अर्ज करण्यासाठी पुन्हा मायदेशी यावे लागणार असून त्यानंतर नव्याने परवानगी मिळाली तर(च) त्यांना परत अमेरिकेत जाता येईल. अर्थात अमेरिकेतील देशभक्त भारतीयांस याचा आनंदच झाला असणार. ‘ने मजसि ने परत मातृभूमीला’ अशी याचना करत अमेरिकेतील अनेक भारतीयांचा प्राण भारतमातेच्या सेवेसाठी तळमळत होता. त्यांची ती भावना लक्षात घेऊन त्या सगळ्यांना हाकलून देण्याचा निर्णय ट्रम्प यांनी घेतला त्याचे स्वागतच राष्ट्रप्रेमी करतील. त्यास पर्यायही नाही. तथापि अमेरिकेने ज्या रीतीने हा निर्णय घेतला ती पद्धत सभ्य आहे असे म्हणता येणार नाही. याही आधी आपले पंतप्रधान अमेरिकेत असताना तेथे बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्यांच्या मुसक्या बांधून भारताकडे रवाना करण्याचे औद्धत्य अमेरिकेने दाखवले होते. त्याही वेळी सभ्यतेचे संकेत पाळत आपण मौन बाळगले. आताही भारतात येण्याआधी अमेरिकेने घेतलेल्या या निर्णयाबाबतही आपण अशीच सभ्यता बाळगली असणार. त्यामुळेच हे रुबियो महाशय ‘अमेरिका स्वागतशील आहे... पण काही मूर्ख त्या देशात आहेत’, असे विधान करते झाले. तेव्हा रुबियो यांच्या भारतभेटीत आग्रा भेट, तेथे जोडीने छायाचित्रे घेणे इत्यादी इत्यादींच्या बरोबरीने आपल्याबाबत नक्की काय घडले यापेक्षा अधिक महत्त्व आहे ते पाकिस्तान वा चीनबाबत काय घडले यालादेखील.

रुबियो यांनी भारतात येण्याआधी आपल्या शेजारी आणि कट्टर वैरी पाकिस्तानवर स्तुतिसुमनांचा वर्षाव केला आणि अमेरिकेसाठी तो देश इराण युद्धाबाबत किती महत्त्वाची मध्यस्थाची भूमिका बजावत आहे त्याचे गोडवे गायले. वास्तविक दहशतवादी कृत्यांत स्वतः आकंठ बुडालेल्या पाकिस्तानची मदत जगभरातील दहशतवाद्यांस सोयीनुसार पोसणाऱ्या अमेरिकेस लागावी यापेक्षा अधिक मोठा विनोद नाही. त्यातही अमेरिकेस ही मदत गरजेची वाटते ती इराणबाबत. न्यूयॉर्क टाइम्सने अलीकडेच एका शोधवृत्तांतात इराणचे माजी राष्ट्राध्यक्ष मेहमूद अहमदीनेजाद यांना त्या सर्वोच्च सत्तापदी बसवण्याचा डाव अमेरिका आणि इस्रायल यांनी कसा आखला होता याचा गौप्यस्फोट केला. गेल्या वर्षीही इस्रायलचे पंतप्रधान नरसंहारी नेतान्याहू यांच्या नादी लागून अमेरिकेने इराणच्या अणुभट्ट्यांवर हल्ले केले होते. या अशा देशास इराणबाबत मध्यस्थीसाठी पाकिस्तानची गरज वाटावी यातच त्या देशाच्या नेतृत्वाचे नाकर्तेपण ठसठशीतपणे दिसून येते. वर ही मध्यस्थी अमेरिकेचे नेतृत्व जाहीरपणे मिरवते हा खरा कहर! सगळ्यांनी ओवाळून टाकलेल्या दांडगेश्वराची ‘मदत’ गावातील कोणा इनामदारांस लागावी तसेच हे. याबाबत बोलताना ‘‘अमेरिका-पाकिस्तान संबंध हे भारत-अमेरिका संबंधांच्या आड येणार नाहीत’’, अशी काही पोपटपंची रुबियो करतात. पण त्यात किती अर्थ असतो हे सगळेच जाणतात. एरवी भारताची लोकशाही, देदीप्यमान इतिहास वगैरे सर्व तोंडी लावण्यापुरते!

हे असे का झाले याचा विचार आपण प्रामाणिकपणे करायला हवा. अमेरिकेच्या भारताबाबतच्या या बदलत्या भूमिकेचा संबंध आपल्या आर्थिक क्षमतेशी आहे किंवा काय याचा विचार या अंगाने होणे गरजेचे. कारण चीनच्या वाढत्या प्रभावास आळा घालण्यात भारताचा मोठा वाटा असेल असे जोपर्यंत अमेरिकेस वाटत होते तोपर्यंत आपल्यासाठी अमेरिका पूर्ण अनुकूल होती. पण आपल्या आर्थिक क्षमतेचा जसजसा संकोच होत गेला तसतसा अमेरिकेचा आपल्याविषयीचा दृष्टिकोन बदलत गेला, असे मानण्यास जागा आहे. अमेरिका दोनच मुद्द्यांची दखल घेते. एक त्या देशास आव्हान देण्याची क्षमता अथवा पूर्ण मांडलिकत्व. अनुक्रमे चीन आणि पाकिस्तान ही या वास्तवाची प्रतीके. आपल्या धुरीणांनी याचा विचार करावा. अन्यथा अमेरिकेचा आपल्याविषयीचा दृष्टिकोन ‘कार्य सिद्धीस नेण्यास श्री समर्थ आहे’ या पारंपरिक विधानामागील ‘तुम्ही आलात किंवा नाही आलात तरी काहीही अडणार नाही’ या अ-कथित सत्यासारखा असेल.

‘भारत अमेरिकेकडून ५० हजार कोटी डॉलरची खरेदी करणार’ किंवा ‘व्हेनेझुएलाच्या हंगामी अध्यक्षा भारतात येणार’ यासारख्या घोषणांवर काहीही प्रतिसाद न देणे, याला भारताचे संकेतपालन म्हणावे की बोटचेपेपण?

‘महासत्ते’च्या वाटेवर... की ‘अविद्ये’च्या अनर्थाकडे?

लेख

डॉ. मनोज महाजन
सहयोगी प्राध्यापक,
मु. जे. महाविद्यालय, जळगाव
mahajanmanoj2009@gmail.com

देशातील लाखभर सरकारी शाळा गेल्या दहा वर्षांत बंद झाल्या; याच दशकभरात शिक्षणाचे खासगीकरण अतोनात वाढले. एकीकडे ‘लाडक्या’ योजना, मोफत शिधा... तर दुसरीकडे शिक्षण महाग करण्याचे हे धोरण आपल्या देशाला कुठे नेणार आहे?

मानवी उत्क्रांतीच्या प्रवासात आदिम अवस्थेपासून ते आजच्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगापर्यंत मानवाने जी झेप घेतली आहे, त्यामागे ‘शिक्षण’ हेच सर्वात प्रभावी इंधन राहिले आहे. ज्या राष्ट्रांनी आपल्या मानवी संसाधनाला दर्जेदार शिक्षणाची जोड दिली, तीच राष्ट्रे आज प्रगत म्हणून ओळखली जातात. मानवी विकास निर्देशांक सुधारण्यापासून ते अर्थव्यवस्थेला गती देण्यापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर शिक्षणाचे योगदान महत्त्वपूर्ण ठरते. जेव्हा एखादा समाज सुशिक्षित होतो, तेव्हा तो केवळ स्वतःचा विकास करत नाही, तर आपल्या कल्पकता आणि कौशल्याच्या जोरावर देशाला जागतिक पटलावर सन्मानाचे स्थान मिळवून देतो. म्हणूनच, भारताला जर खऱ्या अर्थाने भविष्यातील महासत्ता व्हायचे असेल, तर आपल्या शिक्षण व्यवस्थेतील सद्यःस्थिती आणि त्यातील आव्हाने यांचा वेध घेणे अनिवार्य ठरते. या पार्श्वभूमीवर आपल्या देशातील शिक्षणाची स्थिती आज कशी आहे? उच्चशिक्षणाचे खासगीकरण, त्यात परकीय गुंतवणूक आदी वेगाने होत आहे. त्याहीपेक्षा, ‘दशकभरात लाखभर शाळा बंद’सारख्या बातम्या अस्वस्थ करणाऱ्या ठरत आहेत.

या बातमीची पूर्वपीठिका अशी की, सीकर (राजस्थान) येथील माकपचे खासदार अमरा राम यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री जयंत चौधरी यांनी (२ फेब्रुवारी २०२६) लोकसभेत सांगितले : गेल्या १० वर्षांत देशभरात ९३,००० पेक्षा अधिक शाळा बंद झाल्या आहेत, यापैकी बहुतेक शाळा पहिल्या सहा वर्षांत बंद झाल्या.

आज जेव्हा सरकारी आकडेवारी ९३,००० शाळा बंद झाल्याचे सांगते, तेव्हा समाजाचा एक मोठा घटक पुन्हा एकदा ‘अविद्ये’च्या अंधारात ढकलला जाण्याची भीती आहे. संसदेत सरकारनेच दिलेल्या लेखी उत्तरानुसार, २०१४-१५ ते २०१९-२० या काळात ७०,००० हून अधिक शाळा बंद झाल्या हा आतापर्यंतचा सर्वाधिक आकडा आहे. त्यानंतर २०२०-२१ ते २०२४-२५ या कालावधीत आणखी १८,७२७ शाळा बंद झाल्या.

‘कल्याणकारी राज्या’चे प्राधान्यक्रम काय?

सरकारच्या मते, शाळा बंद होण्यामागे विद्यार्थ्यांची कमी पटसंख्या, ग्रामीण भागातून शहरांकडे होणारे स्थलांतर आणि संसाधनांचा प्रभावी वापर करण्यासाठी केलेले ‘शाळांचे विलीनीकरण’ ही प्रमुख कारणे आहेत. सरकारचा दावा आहे की, जवळपासच्या शाळा एकत्र केल्यामुळे पायाभूत सुविधा आणि शिक्षकांची उपलब्धता अधिक दर्जेदार होईल. मात्र, हा युक्तिवाद वरकरणी योग्य वाटत असला तरी तो ‘कल्याणकारी राज्या’च्या मूलभूत संकल्पनेला हरताळ फासणारा आहे.

‘सुसूत्रीकरण’ किंवा ‘पटसंख्ये’च्या नावाखाली एखादी शाळा बंद होते, तेव्हा त्या परिसरातील वंचित घटक, गरीब मुले आणि विशेषतः मुलींच्या शिक्षणाची दारे कायमची बंद होतात. वाहतुकीच्या साधनांचा अभाव आणि आर्थिक ओढाताण यामुळे अशा विलीनीकरणानंतर गळतीचे प्रमाण वाढण्याची मोठी भीती शिक्षण तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. थोडक्यात, प्रशासकीय सोय पाहताना विद्यार्थ्यांच्या ‘शिक्षण हक्का’चा बळी दिला जात आहे, असेच चित्र सध्या दिसते.

सोबतचा तक्ता केंद्र सरकारनेच दिलेल्या आकडेवारीचा आहे. देशभरातून डिसेंबर २०२५ अखेरपर्यंत ९३,२५८ सरकारी शाळा गायब झाल्या; त्यापैकी सर्वाधिक उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या राज्यांतील आहेत (एकूण घटीपैकी ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाटा). देशभर शाळा बंद होण्याचा हा वेग २०१४ ते २०२० या पहिल्या सहा वर्षांत सर्वाधिक (७४,५३१ शाळा) होता, तो आजही थांबलेला नाही. मात्र एकट्या उत्तर प्रदेशात १९,३०५ खासगी शाळांची वाढ झाली. देशातील खासगी शाळांच्या एकूण ४२,९४४ वाढीपैकी ४४.९ टक्के वाटा उत्तर प्रदेशचा आहे.

राज्य / केंद्रशासित प्रदेश	२०१४-१५ सुरू असलेल्या शाळा	२०१९-२० सुरू असलेल्या शाळा	२०१४-२० बंद शाळा	२०२०-२१ सुरू असलेल्या शाळा	२०२४-२५ सुरू असलेल्या शाळा	२०२०-२५ बंद शाळा
भारत (एकूण)	**११,०७,१०१**	**१०,३२,५७०**	**७४,५३१**	**१०,३२,०४**	**१०,१३,३२२**	**१८,७२७**
उत्तर प्रदेश	१,६२,२२८	१,३७,६३८	२४,५९०	–	–	–
मध्य प्रदेश	१,२१,८४९	९९,४११	२२,४३८	९९,१५२	९२,२५०	६,९०२
ओडिशा	५८,६९७	५३,२६०	५,४३७	५०,२५६	४८,६२५	१,६३१
पश्चिम बंगाल	८२,४५४	८३,४५६	१,००२	८३,३७९	८२,१५४	१,२२५
झारखंड	४१,३२२	३५,९३१	५,३९१	–	–	–
महाराष्ट्र	**६७,७१७**	**६५,८८६**	**१,८३१**	**६५,७३४**	**६४,८८४**	**८५०**
बिहार	७४,२९१	७२,६१०	१,६८१	–	–	–
राजस्थान	७०,२१०	६७,६६०	२,५५०	–	–	–
पंजाब	२०,७७२	१९,३७७	१,३९५	–	–	–
उत्तराखंड	१७,७५३	१६,७४१	१,०१२	–	–	–
जम्मू -काश्मीर	–	–	–	३,१६७	१८,७८५	४,३८२
हिमाचल प्रदेश	–	–	–	१५,३९१	१४,७२५	६६६

खासगी शाळांची वाढ किती?

शासकीय शाळा मागील १० वर्षांत आठ टक्क्यांनी घटल्या, तर खासगी शाळा १४.९ टक्क्यांनी वाढल्या. खासगी शाळांची संख्या २०१४-१५ मधील २,८८,१६४ वरून २०२३-२४ मध्ये ३,३१,१०८ इतकी वाढली असून, एकूण ४२,९४४ शाळांची वाढ झाली आहे. यातही १० राज्यांनी खासगी शाळांच्या वाढीच्या १४.९ टक्के या देशभरच्या सरासरीपेक्षा अधिक वाढ नोंदवली आहे. बिहारमधील खासगी शाळा २०१४-१५ मध्ये ३,२८४ होत्या, त्या २०२३-२४ मध्ये ९,१६७ झाल्या म्हणजेच १७९.१४ टक्के वाढ!

युनेस्कोचा ‘ग्लोबल एज्युकेशन मॉनिटरिंग’ अहवाल (२०२२) हा सार्वजनिक शिक्षणाची अपुरी उपलब्धता आणि दर्जा, तसेच पालकांच्या अपेक्षा, यांमुळे भारतात खासगी शिक्षणाची वाढ झाल्याचे नोंदवतो. या अहवालानुसार, प्राथमिक शिक्षणात खासगी शाळांचा सरासरी जागतिक वाटा केवळ १९ टक्के आहे, तर भारतात तो ४५ टक्के! उच्च शिक्षणात तर, भारताचा ५७ टक्के वाटा खासगी संस्थांकडे आहे. साहजिकच, उच्च शिक्षण आवाक्याबाहेर असून केवळ ‘आर्थिक सक्षमता’ असलेला वर्गच उच्च पदांपर्यंत पोहोचू शकतो. माध्यमिक स्तरावर भारतात ५१ टक्के खासगीकरण आहे. नेपाळ (२४ टक्के) व पाकिस्तान (३४ टक्के) सारख्या देशांनीही माध्यमिक स्तरावर भारतापेक्षा जास्त सरकारी गुंतवणूक राखली आहे.

ज्या देशात सुमारे ८१.३५ कोटी लोकांना ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजने’तून मोफत शिधा दिला जातो, तिथे शिक्षणाची ही अवस्था. खरे तर, या वंचित घटकांसाठी शाळा म्हणजे केवळ चार भिंती नसून, तिथे मिळणारे ‘मध्यान्ह भोजन’ ही पोषणाची हमी असते. ‘मोफत पाठ्यपुस्तके’ हा स्वप्नांना मिळणारा आधार असतो. शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करणे ही शासनाची घटनात्मक जबाबदारी आहे. परंतु, जर गरिबांच्या शाळाच बंद होणार असतील, तर सामाजिक समता कशी प्रस्थापित होणार?

देशात २०१४ पासून स्थापन झालेल्या ९७,००० नव्या शाळांपैकी तब्बल ६७,००० शाळा या खासगी आणि विनाअनुदानित आहेत. याचाच अर्थ, शिक्षणाची जबाबदारी शासन आता हळूहळू ‘नफेखोरी’ करणाऱ्या घटकांच्या हाती सोपवत आहे. एका सर्वेक्षणानुसार, भारतातील ७३ टक्के पालकांनी केवळ गुणवत्ता/ दर्जा नसल्यामुळे सरकारी शाळांकडे पाठ फिरवून खासगी शाळांची निवड केली. यापैकी १२ टक्के पालकांना आपल्या मुलांनी इंग्रजी शिकावे असे वाटते, तर १० टक्के पालकांच्या परिसरात सरकारी शाळाच उपलब्ध नाहीत. धक्कादायक बाब म्हणजे, आज भारतात कोणतीही अधिकृत मान्यता नसलेल्या सुमारे २९,६०० शाळा असून त्यात ३८ लाख मुले शिक्षण घेत आहेत. यात ४,१३९ अप्रमाणित मदरशांचाही (पाच लाख विद्यार्थी) समावेश आहे. शिक्षणाचे हे असंघटित आणि अनियंत्रित विस्तारणे भविष्यात ‘शैक्षणिक विषमता’ निर्माण करणारे ठरेल.

हा लोकशाहीचाही संकोच

गरिबांच्या मुलांसाठी खासगी शाळांत असणारा २५ टक्के राखीव जागांचा हक्काचा (राइट टु एज्युकेशन-‘आरटीई’) मार्गही आता नवनवे नियम आणून संकुचित केला जात आहे. ‘लाडक्या’ योजनांसाठी तिजोरी रिकामी होत असताना, त्याचा फटका मात्र अशा शैक्षणिक योजनांना बसतो. खासगी स्वयं-अर्थसाहाय्यित शाळा व्यवस्थापन संघटनांचा दावा आहे की, राज्य सरकारकडे गेल्या दहा वर्षांपासून आरटीई शुल्काची सुमारे २,५०० कोटी रुपयांची प्रतिपूर्ती प्रलंबित आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षी राज्यात आरटीई प्रवेशासाठी ८,८६३ शाळांनी नोंदणी केली, तर यंदा हा आकडा घटून ८,४९० वर आला. आरटीई प्रवेश प्रक्रिया आपणांस लागू होऊ नये म्हणून ‘अल्पसंख्याक दर्जा’ मिळवण्याचा मार्ग अनेक शाळा व्यवस्थापने शोधत आहेत. केवळ या सुटकेसाठी गेल्या पाच वर्षांत मुंबईतील सुमारे ४०, तर राज्यभरात सुमारे १२० शाळांनी अल्पसंख्याक दर्जा मिळवला आहे.

केवळ मूठभर लोकांकडे ज्ञानाची आणि सत्तेची मक्तेदारी असणे, हे लोकशाहीचे लक्षण नव्हे. जर प्रगतीचा महामार्ग केवळ श्रीमंतांसाठीच मोकळा राहणार असेल आणि गरिबांच्या वाटा (सरकारी शाळा) बंद होणार असतील, तर आपण कोणत्या महासत्तेच्या दिशेने निघालो आहोत, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.

अन्वयार्थ

जसा भाजप; तशी काँग्रेस!

केंद्रात भाजपचे सरकार सत्तेत आले त्याला सोमवारी १२ वर्षे पूर्ण होत असताना, या तपभरात भाजप आणि काँग्रेसने परस्परांवर आरोप केले नाहीत, असा एकही दिवस गेला नसावा. दोन्ही पक्षांच्या गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंतच्या नेत्यांनी काही विधाने वा आरोप झाल्यास तात्काळ त्याला उभय बाजूंनी प्रत्युत्तर दिले जाते. उभय बाजू परस्परांवर टपूनच बसलेल्या असतात. राजकीय कारणांवरून आरोप-प्रत्यारोप होणे समजू शकते. सध्या पश्चिम बंगाल आणि केरळ या दोन राज्यांमधील प्रशासकीय नियुक्त्यांवरून भाजप आणि काँग्रेसमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. या दोन राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर होऊन नवीन सरकारे स्थापन झाली तरी या दोन्ही राज्यांमधील राजकीय कवित्व अद्याप कायम आहे. या दोन्ही राज्यांमध्ये सत्तांतर होऊन पश्चिम बंगालमध्ये भाजप तर केरळात काँग्रेस सत्तेत आला. नवीन सरकार सत्तेत आल्यावर प्रशासकीय खांदेपालट केला जातो. त्यात काही वावगेही नसते. तरीही बंगाल आणि केरळमध्ये नवीन मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या नियुक्त्या वादाचा विषय ठरल्या आहेत.

पश्चिम बंगालमध्ये सत्तेत येताच भाजप सरकारने, विधानसभा निवडणूक ज्यांच्या आधिपत्याखाली झाली ते राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी मनोज कुमार अगरवाल यांचीच मुख्य सचिवपदी नियुक्ती केली. त्यावरून लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आरोपांची राळ उठवली. केरळमध्ये सत्तेत आलेल्या काँग्रेसने काही वेगळे दिवे लावले नाहीत. तिथे मुख्य निवडणूक अधिकारी रथन केळकर यांचीच आता मुख्यमंत्र्यांचे सचिव या पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. केंद्रात सत्ता असलेल्या भाजपला पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता मिळाल्यावर, त्या राज्यात निवडणुका घेण्याची जबाबदारी असलेल्या मुख्य निवडणूक अधिकारी अगरवाल यांची मुख्य सचिवपदी नियुक्ती केल्याबद्दल काँग्रेसने कठोर शब्दांत टीका केली होती. ‘भाजप आणि निवडणूक आयोगाच्या चोरबाजारात मोठी चोरी करणाऱ्याला मोठे बक्षीस’ असा थेट हल्ला राहुल गांधी यांनी अगरवाल यांच्या नियुक्तीवरून केला होता. सत्तांतर होऊन काँग्रेसची सद्दी सुरू झालेल्या केरळमध्ये मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याची मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आल्यावर राहुल गांधी टीका करणार का? पश्चिम बंगालला जो न्याय तोच न्याय केरळला का नाही, याचे उत्तर राहुल गांधी यांना द्यावे लागेल. नाही तर ती दुटप्पी भूमिका ठरेल.

पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राबवण्यात आलेल्या एसआयआर मोहिमेत ९१ लाख नावे मतदार याद्यांमधून वगळण्यात आली. यावरून मुख्य निवडणूक अधिकारी म्हणून मनोज अगरवाल हे लक्ष्य झाले होते. अगरवाल हे भाजपचे हस्तक असल्याचा आरोप तेव्हाही ममता बॅनर्जी यांनी केला होता. सत्तेत येताच भाजप सरकारने अगरवाल यांची मुख्य सचिवपदी तेही निवृत्तीला अडीच महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असताना नियुक्ती केल्याने चर्चेला वाव मिळाला. केरळमध्ये असाच प्रकार झाला. मूळचे महाराष्ट्राचे असलेल्या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील केरळ तुकडीचे अधिकारी केळकर यांची थेट मुख्यमंत्री कार्यालयात सचिवपदी नियुक्ती झाली. भाजप सरकारने अशी नियुक्ती केल्यावर विरोधक तुटून पडले. केरळमध्ये काँग्रेसने मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याची नियुक्ती करताच भाजप व तेथील माजी सत्ताधारी डाव्या पक्षांनी आरोप केले आहेत. बंगालमध्ये काँग्रेसने आरोप केल्यावर केरळमध्ये नियुक्तीत खबरदारी घेणे आवश्यक होते. आता ‘पश्चिम बंगालमध्ये मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यावर ९१ लाख नावे वगळण्यावरून गंभीर आरोप झाला होता. केरळमध्ये असा काही प्रकार झाला नाही. केळकर यांच्यावर कोणत्याही राजकीय पक्षाने आरोप केले नव्हते’, असा युक्तिवाद तेथील मुख्यमंत्री सतीशन यांनी केला आहे. पण मग पश्चिम बंगालमधील नियुक्तीवर आरोप करण्याचा काँग्रेसला नैतिक अधिकार राहत नाही. राहुल गांधी यांनी पश्चिम बंगालात भाजप आणि निवडणूक आयोगाचा उल्लेख ‘चोरबाजार’ असा केला, मग केरळमध्ये काँग्रेसचा कोणता ‘बाजार’ हा प्रश्नही उपस्थित होतो.

खरे तर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांमध्ये राजकारण आड येता कामा नये. पण एका बाजूने राजकीय रंग देण्यात आल्यावर दुसऱ्या बाजूने प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविकच. शेवटी भाजप आणि काँग्रेस एकाच माळेचे मणी असल्याचे चित्र यातून पुढे आले.

‘नीट’ पेपरफुटीनंतर लातूरच्या गुणवत्ता-प्रारूपाचे काय?

विश्लेषण

सुहास सरदेशमुख
suhas.sardeshmukh@expressindia.com

देशातील २३ लाख विद्यार्थ्यांना पुन्हा ‘नीट’ची परीक्षा द्यावी लागत असल्याने आता, शिकवणी वर्ग चालक आणि लातूरची गुणवत्ता निर्भेळ असल्याचे कोणी म्हणू शकणार नाही...

लातूर प्रारूपाला आधीपासूनच तडा?

लातूरच्या गुणवत्तेच्या प्रारूपाला हा पहिला तडा नाही. लातूरमध्ये काही ‘स्टेप बाय स्टेप’ नावाचा शिकवणी वर्ग होता. त्याचे संचालक होते अविनाश चव्हाण. २६ जुलै २०१८ रोजी चव्हाण यांची गोळी मारून हत्या करण्यात आली. ‘कुमार मॅथ्स’ नावाच्या शिकवणी वर्गाचे चालक चंदनकुमार यांनी २० लाख रुपयांत सुपारी देऊन चव्हाण यांची हत्या केल्याचा आरोप होता. बिहारहून आलेल्या चंदनच्या ‘कुमार मॅथ्स’मध्ये फक्त सात विद्यार्थी होते. चंदन यांच्या शिकवणीमध्ये विद्यार्थी आणण्याचे काम अविनाश चव्हाण यांनी करायचे आणि चंदन यांनी फक्त शिकवायचे असा व्यवहार ठरला होता. या व्यवहारात पुढे वाद होऊन चव्हाण यांची हत्या झाली. गुणवत्तेच्या भोवती असे गुन्हेगारीकरण सुरूच होते. कुमार मॅथ्समुळे लातूरचे गणित बिघडले होते. आता ‘नीट’ पेपरफुटीमुळे गुणवत्तेचे ‘रसायन’च बिघडले आहे.

लातूरच्या गुणवत्तेविषयी वाढता संशय?

लातूरच्या शिकवणी वर्ग परिसरात सतत गुणवत्तेची चर्चा कायम ठेवण्यात लातूरकरांना यश मिळाले. त्यामुळे बाजारपेठ आणि त्यातील दोष सहसा कोणी मांडत नसे. अगदी काही भूगोल, इतिहास आणि भाषा विषय शिकविणाऱ्यांनीही मग विज्ञान विषयाच्या शिकवणीचे ‘क्लास’मध्ये रूपांतर केले. आता लातूरमध्ये उत्तर प्रदेश, बिहारमधील अध्यापकांची मोठी चलती आहे. औद्योगिक वसाहतीमध्ये भरणाऱ्या एका शिकवणी वर्गात किमान २५० हून अधिक मुले असतात. या मुलांकडून खूप प्रश्नपत्रिका सोडवून घेतल्या जातात. वर्षभरात ३० ते ३५ हजार प्रश्न सोडवून घेतल्यानंतर त्यातील प्रश्न ‘नीट’मध्ये येईलच, असा दावा असतो. तो अमान्यही करण्याचे कारण नाही. मात्र एवढ्या प्रश्नांपैकी नेमके ४६ प्रश्न हस्ताक्षरात समाजमाध्यमांत बाहेर पडले. काही वेळा ही संख्या ८० होती तर कधी त्यापेक्षा जास्त. ‘नीट’ परीक्षेतील हा योगायोग संशय वाढवणारा ठरला. प्रश्नपत्रिका फोडणारा आणि ते विकत घेणारे हे सारे लातूर परिसरातच निघाले. खरे तर प्रश्नपत्रिका फुटण्याची पहिली तक्रार लातूर पोलिसांना मिळाली होती. त्याची चौकशी सुरू असतानाच केंद्रीय अन्वेषण विभागाने चौकशी सुरू केली. यात पहिल्यांदा पकडले गेले ते पी. व्ही कुलकर्णी. हे गृहस्थ दयानंद महाविद्यालयात रसायनशास्त्र शिकवायचे. ते सेवानिवृत्त झाले. ‘नीट’ प्रश्नपत्रिका तयार करण्याच्या प्रक्रियेत ते होते. ते आणि मोटेगावकर रसायनशास्त्र शिकवत. यातून आलेल्या संबंधातून प्रश्नपत्रिका फुटली असावी, असा अंदाज असून तपासाअंती दोषारोपपत्र सादर झाल्यानंतर पेपरफुटीची कार्यपद्धती कशी होती हे समजेल. मात्र, मोटेगावकरांनी ज्यांना प्रश्न पाठवले किंवा फुटलेली प्रश्नपत्रिका दिली अशा चार डॉक्टरांची सध्या चौकशी सुरू आहे. मोटेगावकर डॉक्टर पालकांच्या मुलासाठी स्वतंत्र वर्ग घेत; त्याला ‘फोटॉन’ असे नाव होते. जेवढा नामांकित डॉक्टर आणि मुलाचे गुण कमी तेवढे ‘आरसीसी’मध्ये शुल्क अधिक. या सर्व प्रकरणात प्रश्नपत्रिका विकत घेणाऱ्या काहींची चौकशी अजून सुरू आहे. अंबाजोगाई येथेही एका डॉक्टरची चौकशी सुरू असल्याने लातूरच्या अवगुणवत्तेची मुळे खोलवर रुजलेली असू शकतात. या प्रकरणात एका डॉक्टरने माफीचा साक्षीदार होण्यास मान्यता दिल्याने शिकवणी चालक, पैसा आणि वैद्यकीय व्यवसाय संशयाच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत.

‘लातूर पॅटर्न’ टिकेल?

राज्यात ११ व १२ वी विज्ञान शाखेचे विद्यार्थी एखाद्या महाविद्यालयात परीक्षा नोंदणीसाठी आवश्यक असते म्हणून नाव नोंदवतात. अध्ययन - अध्यापनाची सर्व प्रक्रिया पूर्णतः खासगी शिकवणींवर अवलंबून आहे. मात्र असे असतानाही लातूरमधील राजर्षी शाहू महाविद्यालयात सर्व वर्ग भरतात. विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी अन्य प्रांतांतील मंडळी आहेत. शैक्षणिक सत्र सुरू होण्यापूर्वीपासून सुरू होणारा अभ्यासक्रम ऑक्टोबरपर्यंत संपवला जातो. मग फक्त सराव परीक्षा घेतल्या जातात. ज्या महाविद्यालयात हे घडते, तिथे ओढा कायम राहील. पण शिकवणी वर्ग चालक आणि लातूरची गुणवत्ता आता निर्भेळ आहे, असे कोणी म्हणू शकणार नाही. कारण देशातील २३ लाख विद्यार्थ्यांना पुन्हा ‘नीट’ची परीक्षा द्यावी लागत आहे. हा मनस्ताप लातूरच्या शिकवणी चालकांमुळे झाला आहे, हे कोणी सहजासहजी विसरणार नाही.

संपादकीय

पाकच्या बुडाखाली भडका; पण..

पाकिस्तानातील बलुचिस्तान प्रांताची राजधानी क्वेट्टाजवळ रविवारी एका प्रवासी रेल्वे गाडीवर झालेल्या आत्मघाती हल्ल्यात किमान ३० निरपराध जीव गेले. या हल्ल्याची जबाबदारी बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मीने (बीएलए) घेतली आहे. हा हल्ला म्हणजे पाकिस्तानच्या सात दशकांच्या अपयशाचा स्फोट आहे. कठपुतळी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि खरे सत्ताधारी फील्ड मार्शल आसीम मुनीर यांचे लक्ष मात्र अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धात मध्यस्थ म्हणून मिरवण्यात गुंतले आहे. बलुचिस्तानमधील असंतोषाची मुळे १९४७ सालापर्यंत जातात. फाळणीच्या वेळी कलात संस्थानाने स्वातंत्र्याची घोषणा केली होती; परंतु जिनांच्या दबावाखाली १९४८ मध्ये ते पाकिस्तानात बळजबरीने विलीन करण्यात आले. तेव्हापासून बलुच जनतेच्या मनात उद्रेकाचे निखारे धुमसत आहेत. बलुचिस्तानने १९५४, १९५८, १९६३ आणि १९७३ असे चार मोठे उठाव पाहिले; परंतु सर्वात निर्णायक वळण आले ते २००६ मध्ये, जेव्हा पाकिस्तानी लष्कराने बलुच राजकारणाचे प्रतीक ठरलेले नवाब अकबर बुगटी यांना ठार मारले. त्यानंतर 'बीएलए'सारख्या संघटना अधिक आक्रमक झाल्या. पाकिस्तानचा ४४ टक्के भूभाग व्यापलेला बलुचिस्तान खनिज संपत्तीने समृद्ध आहे आणि तरीही ७० टक्के बलुच बहुआयामी दारिद्र्यात खितपत पडले आहेत. 'रेको दिक'सारख्या जगातील सर्वात मोठ्या सोने-तांबे खाणीत अव्याहत उत्खनन सुरू असताना, स्थानिक बलुच तरुण मात्र बेरोजगार आहेत. त्यांचा संताप रक्तरंजित बंडखोरीत परावर्तित होत आहे. खैबर पख्तूनख्वा या पाकच्या अन्य एक प्रांतातील परिस्थिती वेगळी, पण तितकीच स्फोटक आहे. तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) या संघटनेने पुन्हा डोके वर काढले आहे. अफगाणिस्तानात तालिबानची सत्ता आल्यापासून पाकिस्तानच्या सरहद्दीवरील हे दुखणे अधिक चिघळले आहे. पाकिस्तानी लष्करानेच अशा संघटनांना कधी काळी पोसले, त्यांचा वापर केला. आता त्याचेच चटके पाकला सोसावे लागत आहेत. पाकिस्तानची आर्थिक अवस्थाही या अराजकाइतकीच चिंताजनक आहे. पाकिस्तानने १९५८ पासून आजपर्यंत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे तब्बल २४ वेळा कर्जासाठी हात पसरला आहे. सप्टेंबर २०२४ मध्ये सात अब्ज डॉलरचे कर्ज मंजूर झाले आणि त्यासाठी वीज दरवाढ, करवाढ, इंधन अनुदान कपात अशा जनताविरोधी अटी मान्य कराव्या लागल्या. अशा दिवाळखोर देशाचे पंतप्रधान आणि लष्करप्रमुख उठसुठ भिकेची थाळी घेऊन जगभर फिरत असतात; पण स्वप्ने मात्र जगाचा शांतिदूत बनण्याची बघतात! थोडक्यात, पाकच्या स्वत:च्या बुडाखाली भडका उडाला आहे; पण त्यांना दुसऱ्यांच्या घरातील आग विझवायची आहे. हे केवळ विसंगतच नाही, तर हास्यास्पदही आहे. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हवाई हल्ले सुरू केले, तेव्हा पाकिस्तानने मध्यस्थाची भूमिका पटकावली. मुनीर यांनी स्वत: इराणला भेट दिली; परंतु नव्या आयआरजीसी नेतृत्वाने त्यांना भाव दिला नाही. संसद अध्यक्ष गालीबाफ आणि परराष्ट्रमंत्री अराघची त्यांना भेटले; पण जे खरे निर्णय घेतात ते त्यांच्यासमोर आलेच नाहीत. पाकिस्तानने एप्रिल २०२६ मध्ये एक तात्पुरता युद्धविराम घडवून आणला आणि इस्लामाबादमध्ये ऐतिहासिक चर्चा आयोजित केली. ती अमेरिका व इराण यांच्यातील १९७९ नंतरची सर्वोच्च पातळीवरील पहिली थेट बैठक होती. त्यामुळे पाकिस्तान क्षणभर जागतिक प्रसारमाध्यमांत झळकला खरा; परंतु ते यश क्षणिकच ठरले. इस्लामाबाद चर्चा २१ तासांच्या मॅरेथॉन बैठकीनंतर अपयशी ठरली. त्यानंतर अमेरिकेने इराणच्या बंदरांची नौदल नाकेबंदी जाहीर केली. शाहबाज शरीफ हे पाकिस्तानी लष्कराचे बाहुले आहेत, हे सर्वश्रुत आहे. इम्रान खान यांना खटल्यांच्या जाळ्यात अडकवून तुरुंगात टाकणाऱ्या मुनीर यांनी लोकशाहीचा मुखवटाही शिल्लक ठेवला नाही. 'ह्यूमन राईट्स वॉच'नुसार, २०२५ मध्ये पाकिस्तान सरकारने माध्यम स्वातंत्र्य, राजकीय विरोध आणि नागरी समाज यांची पुरती गळचेपी केली. 'ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल'च्या अहवालानुसार, २०११ पासून आजवर बलुचिस्तानमध्ये दहा हजारांहून अधिक बलुच व्यक्ती 'बेपत्ता' झाल्या आहेत. हे सत्य जगापुढे आले आहे, पण शरीफ आणि मुनीर यांना त्याची लाज नाही. त्यांना खरोखर पाकिस्तानची मान उंचवायची असेल, तर वॉशिंग्टन किंवा तेहरानकडे नव्हे, तर बलुचिस्तानमधील झोपड्यांकडे, खैबर पख्तूनख्वामधील बेरोजगार तरुणांकडे नजर वळवावी लागेल; परंतु त्यासाठी अंगी इच्छाशक्ती, प्रामाणिकपणा आणि विनम्रता असावी लागते. सत्ता व लष्करी शक्तीच्या नशेत बुडालेल्या शरीफ-मुनीर जोडगोळीकडे ती नाही. जनतेने अशा नेत्यांना कधीच माफ केले नाही, हा इतिहास आहे; पण नशेत बुडालेल्यांना तेवढे भान असूच शकत नाही!

वाघ शहरात घुसल्यावर सरकारला जाग येणार आहे?

वाघ पाहण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांच्या मनोरंजनासाठी विदर्भाच्या जंगलातल्या गरिबांच्या रक्तमांसाचा खुराक वाघांना दिला जात आहे का?

श्रीमंत माने
संपादक, लोकमत, नागपूर

महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या गेल्या हिवाळी अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी विदर्भात वाघांनी घेतलेल्या शंभरच्या आसपास बळींचे भयावह चित्र 'लोकमत'ने छायाचित्रासह मांडले. सरकार व मंत्र्यांना झोंबतील असे काही प्रश्न विचारले - मुंबई, पुणे ही महानगरे किंवा अगदी परदेशातून वाघ पाहण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांच्या मनोरंजनासाठी विदर्भाच्या जंगलातल्या गरिबांच्या रक्तमांसाचा खुराक वाघांना दिला जात आहे का? वनखाते किंवा एकूणच सरकार या मुक्या माणसांच्या जिवांबद्दल इतके बेफिकीर का? या वृत्तांताने आमदार हळहळले. काहींनी विधिमंडळात मुद्दा उचलला. सरकारचे उत्तर अगदी सरकारी छापाचे होते. त्यात एआयचा उल्लेख होता. तसाही मानव-वन्यप्राणी संघर्ष हा सरकारी कचेऱ्यांमध्ये एअर कंडिशनरची थंड हवा खात चघळायचा विषय बनला आहेच. त्यात आता एआयची भर पडलीय.

...आणि तरीही अगतिक बायाबापड्यांचे बळी जातच आहेत. गेल्या शुक्रवारी सिंदेवाहीजवळ गुंजेवाही जंगलात जेमतेम चाळिशीतल्या चार महिलांचा वाघीण व तिच्या बछड्यांनी जीव घेतला. आणखी तिघी थोड्या अंतरावर असल्यामुळे वाचल्या. तिथेच गेल्यावर्षी मे महिन्यात तिघींचा बळी गेला होता. या बायका सकाळी-सकाळी तेंदूपत्ता जमा करण्यासाठी जंगलात गेल्या होत्या. त्यांना वाघ किंवा त्याची भीती नवी नाही. परिसरात वाघ असतो हे माहिती असतेच. तरीदेखील जीव धोक्यात घालतात. कारण पोट. एप्रिल, मे महिना तेंदूपत्ता संकलनाचा असतो. वनविभाग कंत्राटदारांना टापू वाटून देतात. अल्पभूधारक शेतकरी व भूमिहीनांच्या घरातल्या महिला एकेक पान जमा करून त्याच्या गड्ड्या बांधतात. चार पैसे कमावण्याचा प्रयत्न करतात. त्याचवेळी कधीतरी झुडपातून येऊन वाघ झडप घालतो. अरण्यात किंकाळ्या घुमतात. रक्तमांसाचा चिखल होतो. क्षणात सारे शांत होते. असाच धोका शेती करताना व जनावरे चारताना. मान खाली घालून शेतीची कामे करतानाही आजूबाजूला लक्ष ठेवावे लागते. नाहीतर बांधावरून वाघ झडप घालतो. गायी-म्हैशी चरायला नेताना गुराखी शक्यतो जनावरांच्या कळपात राहतात. कारण, वाघ म्हशींच्या शिंगांना वचकून असतो. पण, केव्हातरी ते संरक्षण थिटे पडते. अचानक अंगावर आलेला वाघ नरडीचा घोट घेतो.

चंद्रपूर, गडचिरोली, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, भंडारा किंवा अमरावतीच्या मेळघाटच्या जंगलात, कुठे ना कुठे दर दोन-चार दिवसांत असा बळी जातो. ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प या प्रेक्षणीय अभयारण्याचा अभिमान बाळगणाऱ्या चंद्रपूर जिल्ह्यात गेल्या पाच वर्षांत दोनशेवर बळी गेले. साडेआठशे जखमी झाले. जवळपास अकरा हजार पाळीव प्राणी मारले गेले. पण, अरण्यातल्या माणसांच्या किंकाळ्या, जनावरांचे हंबरडे सरकार नावाच्या बधिर व्यवस्थेला ऐकू येत नाहीत. आताही

एकावेळी चौघींचा जीव गेला तरी शहरी वातावरणात रमलेल्या वनमंत्र्यांकडून साधी संवेदना व्यक्त झाली नाही. त्यांनी बहुतेक जंगल अधिकाऱ्यांकडे सोपविले आहे. ते जंगलाचे मालक बनले आहेत आणि जीव गेला की काही लाख देऊन जबाबदारी झटकायची, हा त्यांचा खाक्या आहे. तशी या नुकसानभरपाईची रडकथाच होती. मृतांच्या नातेवाइकांची लाख-दोन लाखांत बोळवण व्हायची. सुधीर मुनगंटीवार वनमंत्री असताना ही रक्कम पंचवीस लाखांवर न्यायचा प्रयत्न झाला तेव्हा वित्तखात्याने आडदांडा टाकला. मुनगंटीवार खमके निघाले. तेव्हा कुठे दीडशे कोटींची तरतूद झाली.

वाघांच्या बळीकडे खरे तर ही आर्थिक मदत किंवा तंत्रज्ञानाच्या वापरापलीकडे पाहायला हवे आणि यात वनखात्याचा आधुनिक कारभार हीच मोठी समस्या आहे. गुंजेवाहीच्या जंगलात वाघिणीने बछड्यांना जन्म दिला हे माहिती होते तर वनखात्याने आजूबाजूच्या गावात तशी दवंडी पिटून लोकांना सावध केले होते का? तसे केल्यानंतरही महिला जंगलात गेल्या असत्या तर चूक त्यांची होती. सकाळी सात-साडेसातला वाढत्या उन्हामुळे वाघीण बिथरली वगैरे ज्ञान पाजळण्यामागे हेच कारण नाही ना? जंगलात राहणाऱ्या माणसांना जंगल नवे नाही आणि वाघ, बिबट, अस्वल, तरस ही श्वापदेही नवी नाहीत. त्यांचे हल्ले नवे नाहीत. वर्षानुवर्षे, शतकानुशतके ते सोबतच राहात आले आहेत. मेळघाटातील कोरकू वाघाला कुलामामा म्हणतात, इतकी ही घनिष्ठता आहे. तज्ज्ञ ज्यांना 'हॅबिटॅट' म्हणतात ती एकमेकांची दैनंदिनी, सवयी त्यांना माहिती आहेत. हे परंपरागत साहचर्य सध्या राहिलेले नाही. वाघांचे बळी रोखण्यासाठी आधी ते जपायला हवे. तथापि, वनाधिकाऱ्यांना जंगल कारभारात तिथल्या रहिवाशांचा सहभाग नको आहे. त्यांनी जंगलाची मालकी हिसकावून घेतल्यामुळे आता माणसांना जंगलाबद्दल आत्मीयता नाही. म्हणूनच वारंवार वनवणवे लागतात आणि पूर्वीप्रमाणे ते विझवायला आदिवासी माणूस जेवत्या ताटावरून उठून धाव घेत नाही. वणवा विझविण्यासाठी मजूर लावावे लागतात.

जंगलात राहणाऱ्या माणसांना रोजगार देण्यातही वनखाते अपयशी ठरले आहे. कुपतोडीची कामे, रोपवाटिका, जंगलरस्ते, पाणवठे यातून पूर्वी चांगला रोजगार मिळायचा. जाचक वनकायद्यांमुळे तो कमी झाला आहे. पोटाची खळगी भरण्यासाठी लोकांना जीव धोक्यात घालून जंगलात जावे लागते. त्यामुळेच 'तुम्हाला आमच्याऐवजी वाघच सांभाळायचे असतील तर खुशाल सांभाळा, आम्ही घरात बसून राहतो, आमचे पालनपोषण करा,' अशी निर्वाणीची भाषा ही भ्यालेली माणसे वापरताहेत. या भाषेतील संताप सरकार जितक्या लवकर समजून घेईल तितके बरे, अन्यथा मोठी शहरेदेखील जंगलापासून दूर नाहीत. आज ना उद्या वाघ-वाघीण व बछड्यांना जंगल अपुरे पडू लागेल व ते शहरात घुसतील. कदाचित तेव्हा सरकार जागे होईल. परंतु, तोवर जंगलात राहणारे शेकडो दुबळे जीव या जगात नसतील.

shrimant.mane@lokmat.com

अन्वयार्थ

डॉ. मनोज शिरुरे, नीट आणि 'माफीचा साक्षीदार'!

नीट पेपरफुटीच्या प्रकरणात लातूर येथील डॉ. मनोज शिरुरे सीबीआयच्या ताब्यात असून, ते 'माफीचा साक्षीदार' होणार असल्याची चर्चा आहे. त्यानिमित्त..

डॉ. खुशालचंद बाहेती
निवृत्त सहायक पोलिस आयुक्त व महाव्यवस्थापक- जनसंपर्क लोकमत

फौजदारी न्यायव्यवस्थेत गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी साक्षीदारांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. साक्षीदार म्हणजे गुन्ह्याच्या तथ्यांशी परिचित असणारी व्यक्ती. कलम १८० भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) अंतर्गत पोलिस अशा व्यक्तीची चौकशी करू शकतात. तपासात सत्य माहिती देणे साक्षीदारावर कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. याला अपवाद म्हणजे ज्या माहितीमुळे साक्षीदार स्वतःच गुन्ह्यात अडकणार असेल अशी माहिती देण्याची साक्षीदारावर सक्ती नाही. साक्षीदाराने सांगितलेली माहिती पोलिस लिहून घेऊ शकतात. ती साक्षीदाराने स्वतःच्या हस्ताक्षरात लिहून देण्याची गरज नाही. पोलिसांनी लिहून घेतलेल्या जवाबावर पोलिसांनी साक्षीदारांची सही घेऊ नये असा कायदा आहे. (पोलिस सर्रास सह्या घेतात हे कायद्याला मान्य नाही.) बीएनएसएसमध्ये साक्षीदाराचे जवाब ऑडिओ-व्हिडीओ माध्यमातून नोंदवण्याची तरतूद आहे. कायद्यात साक्षीदारांचे स्वतंत्र वर्गीकरण नसले तरी साधारणपणे साक्षीदारांचे वर्गीकरण पुढीलप्रमाणे करता येईल.

प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार (ज्याने घटना प्रत्यक्ष पाहिली), परिस्थितिजन्य साक्षीदार (गुन्ह्याशी संबंधित परिस्थिती सांगणारा), स्वतंत्र साक्षीदार (कोणत्याही पक्षाशी संबंध नसलेला तटस्थ), हितसंबंधित साक्षीदार (आरोपी किंवा फिर्यादीशी संबंध असलेला), योगायोगाने उपस्थित साक्षीदार (अपघाताने घटनास्थळी उपस्थित असलेला), बाल साक्षीदार (समजण्याची क्षमता असलेला अल्पवयीन साक्षीदार), तज्ज्ञ साक्षीदार (डॉक्टर, फॉरेन्सिक तज्ज्ञ, हस्ताक्षरतज्ज्ञ इ.), पोलिस साक्षीदार (तपासात सहभागी पोलिस अधिकारी), औपचारिक साक्षीदार (नोंदी, प्रमाणपत्रे किंवा दस्तऐवज सिद्ध करणारा), माफीचा साक्षीदार (अनेक वेळा तपास यंत्रणेकडे थेट पुरावे नसतात. अशावेळी आतल्या व्यक्तीची माहिती मिळवण्यासाठी माफीच्या साक्षीदाराची संकल्पना वापरली जाते.)

गुन्ह्यात सहभागी असलेल्यांपैकी एखादी व्यक्ती न्यायालयाकडून माफी मिळवून इतर आरोपींविरुद्ध साक्ष देण्यास तयार होते, अशा आरोपीला 'माफीचा साक्षीदार' म्हटले जाते. ही संकल्पना विशेषतः कट-कारस्थान, संघटित गुन्हेगारी, भ्रष्टाचार आणि आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये महत्त्वाची ठरते. अन्य साक्षीदार व माफीचा साक्षीदार यात महत्त्वाचा फरक म्हणजे माफीचा साक्षीदार हा स्वतः गुन्ह्यातील आरोपी असतो. अन्य प्रकारचे साक्षीदार तपास यंत्रणा ठरवते तर माफीचा साक्षीदार बनविण्याची प्रक्रिया न्यायालयीन नियंत्रणाखाली होते. साधारणतः ७ वर्षापेक्षा जास्त शिक्षेच्या गंभीर गुन्ह्यांत आवश्यकतेनुसार माफीचा साक्षीदार बनवण्यात येतो.

यासाठी तपास यंत्रणा ज्याचा गुन्ह्यांत किमान सहभाग आहे पण त्याला गुन्ह्याची सर्व माहिती आहे, अशा आरोपीची निवड करते. तो गुन्ह्याचे नियोजन, कट-कारस्थान, इतर आरोपींची भूमिका आणि गुन्ह्यामागील संपूर्ण सत्य उघड करण्यास मदत करू शकणार असेल तर त्याला माफी देण्याची विनंती न्यायालयाला सरकार पक्ष करतो. गुन्ह्याचे स्वरूप, पुराव्यांची स्थिती आणि आरोपीची साक्ष किती आवश्यक आहे याचा विचार करून न्यायालय आरोपीस माफीची ऑफर देते. माफीचा साक्षीदार हा बहुतांश वेळा अटकेत असतो. न्यायालयीन कोठडीत ठेवून त्याचा जबाब नोंदविल्यास तो स्वेच्छेने दिलेला आहे का, याची खात्री करणे कोर्टाला सोपे जाते. पोलिस दबावाचे आरोप टाळता येतात. माफी मिळवून खोटी माहिती दिली, तथ्य लपवले किंवा न्यायालयाच्या अटींचे उल्लंघन केले, तर माफी रद्द होऊ शकते. अशा परिस्थितीत त्याच्यावर पुन्हा मूळ गुन्ह्यासाठी खटला चालवता येतो.

माफीचा साक्षीदार वगळता अन्य कोणत्याही आरोपीने पोलिसांच्या समोर दिलेली गुन्ह्याची कबुली न्यायालयात वैध पुरावा नाही. अपवादात्मक परिस्थितीत गुन्हयाची कबुली देऊन महत्त्वाचे भौतिक पुरावे आरोपीने काढून दिले तर ते पुरावे मात्र न्यायालयात ग्राह्य धरता येतात. फौजदारी तपास प्रक्रियेतील साक्षीदारांची जबाबदारी, अधिकार व संरक्षण समजले तर साक्षीदार निर्भयपणे स्वतः पुढे येतील. यासाठी तपास यंत्रणांनी जनजागृती करण्याची गरज आहे. प्रत्येकाने पोलिस तपासात सहकार्य करणे गरजेचे असते. कारण तपासाचे लक्ष 'सदरक्षणाय खलनीग्रहणाय' हेच असते.

जगभर

मॅक्रॉन भडकले, थेट मंचावरूनच लोकांना सुनावलं !

फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि त्यांची पत्नी ब्रिजिट मॅक्रॉन यांच्याबद्दलची चर्चा बहुतेकदा त्यांच्या वयातील अंतरामुळे होते. त्यांच्या वयात साधारण २४-२५ वर्षांचं अंतर आहे. ब्रिजिट या इमॅन्युएल यांच्या शिक्षिका होत्या, पुढे दोघांनी २००७ मध्ये लग्न केलं. त्यांच्या वयाच्या अंतरावरून सोशल मीडियावर, राजकीय टीकाकारांकडून आणि विनोदी कार्यक्रमांतून अनेकदा शेरेबाजी होते, पण मॅक्रॉन यांची त्यावरची प्रतिक्रिया अतिशय संयमित असते. त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर किंवा पत्नीबद्दलच्या टीकेवर ते सहसा सार्वजनिकरीत्या तीव्र वैयक्तिक प्रतिहल्ला करत नाहीत; उलट विनोद, स्पष्टीकरण किंवा वेगळ्या विषयाला स्पर्श करून वातावरण हलकं करतात. २०२५ मध्ये व्हिएतनाम दौऱ्यात पत्नीने त्यांना ढकलल्यासारखा दिसणारा व्हिडीओ व्हायरल झाला, तेव्हाही त्यांनी त्याला 'आमच्यातील मजा/खेळकर क्षण' असं संबोधून संयमानंच ते प्रकरण हाताळलं होतं.

कधीही फारसे न चिडणारे, प्रसन्नचित्त असणारे आणि कामात मग्न असणारे इमॅन्युएल नुकतेच अचानक चिडल्यामुळे सध्या त्यांची सर्वत्र चर्चा होत आहे. इमॅन्युएल इतके चिडले कुठे आणि कोणावर? - तर नैरोबीत आणि तिथल्या लोकांवर. त्यांचं असं रूप अनेकांनी पहिल्यांदाच पाहिलं.

फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इम्यॅन्युएल मॅक्रॉन केनियाची राजधानी नैरोबीमध्ये एका कार्यक्रमादरम्यान लोकांवर भडकले आणि सभागृहात बसलेल्या लोकांना त्यांनी जोरदार सुनावलं. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होतो आहे.

त्याचं झालं असं... इम्यॅन्युएल मॅक्रॉन नुकतेच

नैरोबीमध्ये आयोजित आफ्रिका फॉरवर्ड शिखर परिषदेत सहभागी झाले होते. यावेळी युवकांवर केंद्रित एका सत्राचं आयोजन सुरू होतं. वक्ते मंचावर उभं राहून कार्यक्रम सादर करत होते, पण कार्यक्रमात उपस्थित लोक आपापसांत गप्पा मारत होते. यामुळे कार्यक्रमात व्यत्यय येत होता. इमॅन्युएल मॅक्रॉन हा कार्यक्रम लक्ष देऊन ऐकत होते. पण, लोकांच्या गडबड-गोंधळामुळे त्यांना कार्यक्रम नीट ऐकता येत नव्हता. त्यामुळे प्रेक्षकांमध्ये बसलेले इम्यॅन्युएल मॅक्रॉन प्रचंड नाराज झाले.

कार्यक्रम सुरू असतानाच अचानक आपल्या जागेवरून ते उठले आणि थेट मंचावर गेले. एका वक्त्याकडून त्यांनी माईक घेतला आणि आपला राग व्यक्त केला. ते म्हणाले, 'माफ करा मित्रांनो, पण इतक्या गोंधळात संस्कृतीवर चर्चा करणं अशक्य आहे. वक्त्यांचा, कार्यक्रम सादर करणाऱ्यांचा हा सरळसरळ अनादर आहे. माझा तुम्हाला सल्ला आहे, जर तुम्हाला एखाद्या मुद्द्यावर चर्चा करायची असेल, गप्पा मारायच्या असतील, तर आपापल्या खोल्यांमध्ये जाऊन करा किंवा इथून बाहेर पडा. जर तुम्हाला इथे थांबायचं असेल, तर या लोकांचं म्हणणं तुम्हाला शांतपणे ऐकावंच लागेल. उपस्थित लोकांनाही मॅक्रॉन यांच्या या अचानक कृतीचं आश्चर्य वाटलं. अनेकांनी त्यांचं कौतुक केलं. अर्थात, मॅक्रॉन यांनी अशा प्रकारे लोकांना जाहीरपणे सुनावल्याबद्दल काहींनी त्यांच्यावर टीकाही केली आहे. विशेषत: केनियन लोकांना हे खूपच झोंबलं..

जनमन

फुकटच्या गोष्टींना लांबच ठेवा !

आज 'मोफत'च्या नावाखाली जे राजकारण सुरू आहे ते समाजाला आत्मसन्मानापासून दूर नेणारं आहे. आपण आज सरकारी योजनांच्या तुकड्यांवर समाधान मानत आहोत, पण याची मोठी किंमत उद्या आपली मुलं मोजणार आहेत. जेव्हा कष्टाची ऊर्मी संपते आणि माणूस केवळ मदतीवर अवलंबून राहतो तेव्हा त्याची प्रश्न विचारण्याची हिंमतही मरते. ही मानसिकताच लोकशाहीत अप्रत्यक्ष गुलामगिरीला जन्म देते.

आपण आपल्या पुढच्या पिढीला वारसा म्हणून काय देत आहोत? स्वाभिमानाने जगण्याचं बळ की केवळ रांगेत उभं राहून हात पसरण्याची सवय? शिक्षण आणि हक्काचा रोजगार मागण्याऐवजी जर आपण फुकटच्या सवलतींमध्येच धन्यता मानली तर उद्याचा काळ आपल्या मुलांसाठी केवळ अंधार घेऊन येईल. ज्या हातांनी नवनिर्मिती करायला हवी होती ते हात आज सत्तेच्या दातृत्वाखाली दबले जात आहेत.

आता तरी जागे व्हा. कष्टाच्या भाकरीची चव ही मोफतच्या पक्वान्नापेक्षा कितीतरी श्रेष्ठ असते. स्वतःच्या मेहनतीवर आणि मनगटावर विश्वास ठेवा. सत्तेच्या दारात लाचारी पत्करण्यापेक्षा ताठ मानेनं जगणं कधीही उत्तम. जर आज आपण ही 'घेण्याची' वृत्ती सोडली नाही तर इतिहास आपल्याला अशी पिढी म्हणून ओळखेल जिने तात्पुरत्या सुखासाठी आपल्या मुलांचं भविष्य विकलं. अशी वेळ येऊ द्यायची नसेल, तर आजच आत्मसन्मानाचा मार्ग पत्करा. फुकटच्या गोष्टींना आपल्यापासून लांबच ठेवा, नाहीतर आपण कळसुत्री बाहुल्या बनू.

- मंगेश मुरलीधर दौंडकर, भोसरी, पुणे

समकालीन महत्त्वाचे मुद्दे मांडणारी, नवी चर्चा सुरू करणारी वाचक-पत्रे या स्तंभामध्ये प्रसिद्ध केली जातील. आपली पत्रे येथे पाठवा : **janman@lokmat.com**

शहर नोंदी

'तथाकथित' विकास आपल्याच सुखाच्या मुळावर येऊ लागलाय का?

आपल्याच शहरातली कांदळवनं, पुरातन वृक्षराजी, जॉगर्स पार्क्स, राष्ट्रीय उद्यानं राखण्यासाठी आपल्याला आंदोलनं करावी लागतायत, ती कशासाठी?

मेघना भुस्कुटे
ब्लॉगर, भाषांतरकार

शहरं म्हणजे धूळ, धुरे, सिमेंट, गर्दी, आवाज, धकाधकी-धांदल... हा समज आज-आत्ताचा नाही. नागर जीवनाच्या सुरुवातीपासून माणसांना त्यांच्या निसर्गाशी बांधलेल्या आणि आता विस्मृतीत गेलेल्या गतायुष्यांची आठवण कातर करत आलेली आहे. आजही 'गावाकडची ज्वारी ! लागती का नई भाकर ग्वाड?' म्हटल्यावर भाकरीचा तोच घास आपल्याला जरा जास्त गोड लागतो. त्याची कारणं या आदिम स्मृतीत आहेत. पण माणसांना निसर्गाची कितीही ओढ लागली, तरी नागर जीवन हाही सुरक्षिततेच्या आदिम शोधाचाच भाग आहे. त्यामुळे 'गड्या आपुला गाव बरा..' हेही खरं नि 'कशासाठी, पोटासाठी..' हेही!

माणसं आपल्या खटपट्या स्वभावानुसार या द्वंद्वावरही उत्तरं शोधत आलीयत. एबेंझर हॉवर्ड नामक इंग्लिश माणसानं एकोणिसाव्या शतकात बागा असलेली नियोजित शहरं वसवण्याची कल्पना मांडली. विशिष्ट भूभागावर मर्यादित घरांचं नियोजन असं करायचं, की सगळ्या शहरी सोयी उपलब्ध असतील; पण सगळ्यांना खासगी आणि सामाईक बागा उपभोगायला जागाही असेल. खूप लोकप्रिय झालेली ही कल्पना तेव्हापासून ते आजतागाईत जगभर सगळीकडे कमी-अधिक फरकानं राबवली जात असते. लंडनची फुफ्फुसं मानली जाणारी, शहराच्या मध्यभागी वसवलेली भली-मोठी उद्यानं तर प्रसिद्ध आहेतच. पण इतिहासाच्या एका टप्प्यावर झाडांना कुरूप मानून एकाही झाडाशिवायचे रस्ते नि इमारती वसवणारं पॅरिसही गेल्या काही वर्षांत कंबर कसून शहर हिरवंगार करण्याच्या मागे लागलंय. सिंगापूरसारख्या आशियाई शहरातही उपलब्ध जागा कसोशीनं वापरून घेत आडव्या नि उभ्या बागा राखलेल्या दिसतात. अमेरिकेत मुद्दाम राखलेली, निगुतीनं जोपासलेली थोडीथोडकी नव्हेत, त्रे-स-ष्ठ राष्ट्रीय उद्यानं आहेत. भारतात मुघलांनी कितीतरी

बागा कल्पकपणे निर्मिल्या नि राखल्या. आपण ती परंपरा पुढे चालू ठेवली. आजही दिल्लीत, बंगळुरात आणि मुंबईतही मुद्दाम राखलेल्या मोठाल्या हिरव्यागार बागा आणि जलाशय आहेत.

अशा जागांमध्ये स्थानिक झाडंझुडपं आणि वृक्षसंपदा फोफावतात, त्यावर जगणाऱ्या प्राण्यांच्या नि कीटकांच्या परिसंस्था नांदतात, दूरदेशची पाखरं दरसाल येऊन विसावतात. एरवी आपल्या जगण्यातून अधिकाधिक हरपत चाललेला निसर्ग अनुभवण्याची संधी तिथे मिळते. परागीभवन करणाऱ्या माश्या, फुलपाखरं, अळ्या, वटवाघळं यांना थोडा निरामय अवकाश मिळतो. भटके प्राणी आणि कष्टकरी लोक सावली बघून घटकाभर माथा टेकतात. माणसांना घरापासून जरा लांब; पण माणसांच्यात राहून पाय मोकळे करायचे असतात, चार माणसांना भेटून सुखदुःखाचं बोलायचं असतं, मोकळी हवा खायची असते, थोडं गॉसिप-थोडा व्यायाम-थोडं चिंतन करायचं असतं. शहरी आयुष्यात हे सगळं करायला लागणारा स्थलावकाश बागा आणि तळी देऊ करतात.

लंडनच्या हाइड पार्कमधल्या 'स्पीकिंग कॉर्नर'मध्ये कुणालाही जाहीरपणे आपलं मत व्यक्त करता येतं. काहीही बोललं तरी बोलणाऱ्याला त्याबद्दल शिक्षा करण्याचा प्रघात नाही. तिथे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला अभय दिलेलं असतं. खदखदत्या असंतोषाची वाफ दवडण्याची - आणि मोकळं होऊन पुन्हा आपल्या व्यग्र आयुष्यात धावू लागण्याची सर्वतोपरी संधी - बागा देतात, शहरांना शब्दशः थोडा श्वास घेऊ देतात. या सगळ्याशी तुम्ही आम्ही असहमत असण्याचं कारणच नाही, इतकं हे साधं-सरळ-सोपं-सोयीस्कर आहे. मग अडचण होते कुठे? आपल्याच शहरातली कांदळवनं, पुरातन वृक्षराजी, जॉगर्स पार्क्स, राष्ट्रीय उद्यानं राखण्यासाठी आपल्याला आंदोलनं करावी लागतायत, ती कशासाठी? कुणाच्या विरोधात? आपल्याला हवा असलेला 'तथाकथित' विकास आपल्याच सुखाच्या मुळावर येऊ लागलाय, असं तर नाही?

meghana.bhuskute@gmail.com

तिरकस आणि चौकस

गजानन घोंगडे

हे पत्र लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेडच्या वतीने मुद्रक व प्रकाशक **बालाजी मुळे** यांनी प्लॉट नं. ए - ८१८ इंडस्ट्रियल एरिया, एम.आय.डी.सी., महापे, नवी मुंबई येथे मुद्रित करून 'लोकमत', पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई कार्यालय - ४००७०५ येथून प्रसिद्ध केले. ● दूरध्वनी क्र : ०२२ ४६०४१७८४
● **मुंबई कार्यालय :** लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेड, तिसरा मजला, पारिजात हाउस, प्लॉट नं. १०७६, आपटे इंडस्ट्रियल इस्टेट, लक्ष्मीनरसिंग पपन मार्ग, डॉ. ई मोझेस रोडसमोर, गांधीनगर, वरळी, मुंबई, ४०००१८. ● दूरध्वनी क्र : ०२२- ४६०३५९३०, ०२२- ४७५०७९४६ ● **ठाणे कार्यालय :** वेस्टर्न व्ह्यू, श्री गजानन महाराज चौक, वारकरी भवनाजवळ, ठाणे, फोन : २५४४१९०५, २५३८१७७४ ● **नवी मुंबई कार्यालय :** पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई ४००७०५. फोन : ०२२ ४६०४१७८४ ● संस्थापक संपादक : **स्व. जवाहरलाल दर्डा** ● मानद संपादिका : **श्रीमती उषाताई दर्डा** ● चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड : **डॉ. विजय दर्डा** ● एडिटर इन चिफ : **राजेंद्र दर्डा** ● समूह संपादक : **विजय बाविस्कर**
● संपादक : **अतुल कुलकर्णी*** (*पी. आर. बी. कायद्यानुसार संपादकीय जबाबदारी यांची आहे.) 'लोकमत'मधील लेखांचे हक्क राखून ठेवले आहेत. लोकमत ® हे चिन्ह लोकमत मीडिया प्रायव्हेट लि. चे. व्यापारचिन्ह आहे.

चिंतन

अब अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा दबाव

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक अनिश्चितताओं का असर अब भारतीय अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दो सप्ताह में करीब 7 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। यह इस बात का संकेत है कि सरकार भी अब दबाव महसूस कर रही है। हालांकि सरकार लगातार यह कोशिश कर रही है कि आम जनता पर बोझ सीमित रहे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों ने आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियां बढ़ा दी हैं। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है। ऐसे में पश्चिम एशिया में किसी भी तरह का तनाव सीधे तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी टकराव तथा युद्ध की आशंका ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता पैदा कर दी है। सोमवार को युद्ध समाप्ति की उम्मीद में शेयर बाजार में तेजी जरूर देखने को मिली, लेकिन रुपये पर दबाव अभी भी बना हुआ है। डॉलर की मजबूती और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी केवल वाहन चलाने की लागत तक सीमित नहीं रहती। इसका असर पूरे आर्थिक तंत्र पर पड़ता है। परिवहन महंगा होने से खाद्यान्न, सब्जियां, दूध और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ना स्वाभाविक है। यानी महंगाई का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। मध्यम वर्ग और गरीब तबका सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि उनकी आय सीमित होती है, जबकि खर्च लगातार बढ़ते जाते हैं। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह आर्थिक संतुलन बनाए रखे और जनता के असंतोष को भी नियंत्रित करे। यही कारण है कि केंद्र सरकार फूंक-फूंक कर कदम उठा रही है। यदि तेल कंपनियों को लगातार घाटे में चलने दिया जाए तो आर्थिक बोझ बढ़ेगा, जबकि कीमतें बढ़ाने से जनता में नाराजगी का खतरा रहता है। इससे खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित होने और कीमतें बढ़ने की आशंका रहती है। सप्लाई चेन बाधित होने की स्थिति में जरूरी वस्तुओं की कमी भी पैदा हो सकती है। इन परिस्थितियों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने '3 एफ' यानी ईंधन (फ्यूल), उर्वरक (फर्टिलाइजर) और विदेशी मुद्रा भंडार (फॉरेक्स) के रणनीतिक प्रबंधन पर जोर दिया है। उनका कहना है कि सरकार की प्राथमिकता विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत बनाए रखना और नागरिकों के हितों की रक्षा करना है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 688 अरब अमेरिकी डॉलर के पार पहुंचना निश्चित रूप से एक सकारात्मक संकेत है। असली चुनौती यह है कि वैश्विक अस्थिरता के बीच आर्थिक विकास की रफ्तार को कैसे बनाए रखा जाए। यदि कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रहती हैं तो सरकार की कई विकास योजनाओं पर असर पड़ सकता है। कुछ परियोजनाएं धीमी पड़ सकती हैं और कुछ में देरी होना स्वाभाविक है। निजी निवेश पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि उद्योग जगत अनिश्चित माहौल में निवेश को लेकर सतर्क हो जाता है। खाड़ी संकट जल्द नहीं सुलझा तो जरूरी वस्तुओं की कमी हो सकती है और सप्लाई चेन बाधित हो सकती है। ऐसे में सरकार पूरी सावधानी के साथ कदम उठा रही है। देखा जाए तो देश में अभी तक कीमतें और उपलब्धता काफी हद तक नियंत्रण में हैं। लेकिन यह आगे नहीं बढ़ेंगी इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि खाड़ी संकट जल्द दूर होगा, अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होगा और आमजन को महंगाई से कुछ राहत मिलेगी।

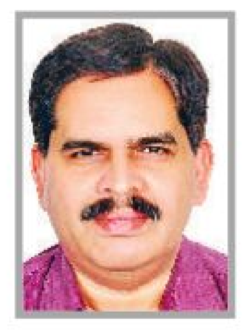

मुद्दा
डॉ. अश्विनी महाजन

आत्मनिर्भरता से मजबूत होगा रुपया

जब 10 मई, को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से पेट्रोल और डीजल बचाने की अपील की, जिसके लिए उन्होंने अनावश्यक पेट्रोल-डीजल से चलने वाले वाहनों का इस्तेमाल कम करने, विदेश यात्रा में कटौती करने, घर से काम करने और ऑनलाइन बैठकें करने का सुझाव दिया तो असल में यह नागरिकों से विदेशी मुद्रा बचाकर भारतीय रुपये की रक्षा करने की अपील ही थी। इसी संदर्भ में, प्रधानमंत्री की नागरिकों से सोने की खरीद से बचने, खाना पकाने के तेल की खपत कम करने, विदेशी ब्रांड के सामान न खरीदने और स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करने और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने की अपील का उद्देश्य विदेशी देशों पर निर्भरता कम करना और कीमती विदेशी मुद्रा बचाना है।

भारतीय रुपया लंबे समय से कमजोर हो रहा है, लेकिन अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के ढाई महीने के बहुत कम समय में रुपये के मूल्य में आई हालिया गिरावट नीति निर्माताओं के लिए चिंता का बड़ा कारण है। हालांकि, भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट का सीधे तौर पर जिक्र नहीं किया गया, लेकिन यह कोई भी समझ सकता है कि जब 10 मई, 2026 को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से पेट्रोल और डीजल बचाने की अपील की, जिसके लिए उन्होंने अनावश्यक पेट्रोल-डीजल से चलने वाले वाहनों का इस्तेमाल कम करने, विदेश यात्रा में कटौती करने, घर से काम करने और ऑनलाइन बैठकें करने का सुझाव दिया तो असल में यह नागरिकों से विदेशी मुद्रा बचाकर भारतीय रुपये की रक्षा करने की अपील ही थी। इसी संदर्भ में, प्रधानमंत्री की नागरिकों से सोने की खरीद से बचने, खाना पकाने के तेल की खपत कम करने, विदेशी ब्रांड के सामान न खरीदने और स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करने और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने की अपील का उद्देश्य विदेशी देशों पर निर्भरता कम करना और कीमती विदेशी मुद्रा बचाना है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि खाड़ी युद्ध की इस अवधि के दौरान, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 38 अरब अमेरिकी डॉलर कम हो गया है, और हमारा भंडार 27 फरवरी को 728.5 अरब अमेरिकी डॉलर से घटकर 12 मई, 2026 तक 690.7 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया है।

आम तौर पर, रुपये की स्थिरता के बारे में दो तरह के विचार हैं। एक वर्ग मानता है कि विनिमय दर, बाजार द्वारा निर्धारित एक मूल्य से ज़्यादा कुछ नहीं है; और अगर मुद्रा का मूल्य गिरता भी है, तो भी किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आयात और निर्यात विनिमय दर के अनुसार अपने आप समायोजित हो जाएंगे। उनका मानना है कि घरेलू मुद्रा के मूल्य में गिरावट आयात को हतोत्साहित और निर्यात को प्रोत्साहित कर सकती है। भारतीय रुपये के बारे में, कभी-कभी उनका मानना होता है कि इसका मूल्य ज़रूरत से ज़्यादा है, और इसलिए यदि रिज़र्व बैंक रुपये में किसी भी गिरावट को रोकने के लिए हस्तक्षेप करता है, तो इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, क्योंकि ऐसा करने से आयात को बढ़ावा मिलेगा और निर्यात हतोत्साहित होगा। दूसरा वर्ग एक मज़बूत रुपये में विश्वास रखता है। उन्हें लगता है कि केवल एक मज़बूत रुपया ही मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है, और ऋण सेवाओं (मूलधन और ब्याज की अदायगी), लाभांश, रॉयल्टी, वेतन और अन्य आय हस्तांतरणों के कारण होने वाले विदेशी मुद्रा के बहिर्प्रवाह को नियंत्रण में रख सकता है। सत्ता की बागडोर संभालने से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह तर्क देते रहे हैं कि पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण ही रुपये में गिरावट आई है, और इसलिए केवल सही नीतियों द्वारा ही समूह ही रुपये के अवमूल्यन को रोका जा सकता है। हालांकि, रुपये का मूल्य हमेशा से चर्चा का विषय रहा है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि सरकार चाहे कितनी भी मज़बूत क्यों न हो, वह कृत्रिम रूप से विनिमय दर तय नहीं कर सकती और न ही इसे बढ़ाने में मदद कर सकती

है। विनिमय दर विदेशी मुद्राओं (जैसे डॉलर) की मांग और आपूर्ति द्वारा तय होती है। जहां विदेशी मुद्रा की मांग वस्तुओं और सेवाओं के आयात, ऋण चुकाने (अतीत में लिए गए ऋणों के मूलधन और ब्याज की वापसी), लाभांश, रॉयल्टी, तकनीकी शुल्क, वेतन और अन्य आय हस्तांतरण के कारण होती है; वहीं विदेशी मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के शुद्ध प्रवाह, और विदेशों से प्राप्त विदेशी पोर्टफोलियो निवेश आदि से होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कभी-कभी भारतीय रिज़र्व बैंक बाज़ार में हस्तक्षेप करता है और बाज़ार में विदेशी मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाकर रुपए में अल्पकालिक उतार-चढ़ाव को रोकने की कोशिश करता है; लेकिन यदि चालू खाते पर भुगतान संतुलन में लगातार घाटे के कारण रुपए का मूल्य गिरता है, तो लंबे समय में इस प्रकार के हस्तक्षेप का प्रभाव बहुत सीमित होता है। रुपये के मूल्य को कृत्रिम रूप से बनाए रखने के लिए आरबीआई को अपने विदेशी मुद्रा भंडार से लगातार अधिक से अधिक डॉलर बाज़ार में डालने पड़ते हैं। इसलिए, यह खतरा बना रहता है कि यदि रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा बाज़ार में हस्तक्षेप करना जारी रखता है, तो उसका विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हो सकता है। अतः, रुपए का मूल्य सुधारने के लिए, हमें इस घाटे के लिए ज़िम्मेदार मूल कारणों को ठीक करने की आवश्यकता है। हाल के वर्षों में भारत में रुपये के मूल्य पर विचार करें, तो हम पाते हैं कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच रुपए का मूल्य अपेक्षाकृत स्थिर रहा और इस अवधि के दौरान इसमें मात्र 2.3 प्रतिशत की गिरावट आई। लेकिन 1 अप्रैल 2025 से अब तक, एक साल से कुछ अधिक समय में ही रुपये का मूल्य 11.7 प्रतिशत गिर गया है। इस अवधि के दौरान सबसे बड़ी गिरावट 27 फरवरी 2026 को युद्ध शुरू होने से लेकर 13 मई 2026 तक के समय में हुई। मात्र ढाई महीने की छोटी सी अवधि में ही रुपए का मूल्य काफी गिर गया 4.4 प्रतिशत की गिरावट के साथ, यह 91.1 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर से गिरकर 95.5 रुपए प्रति अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया। इससे नीति निर्माताओं में बड़ी चिंता व्याप्त है।

हम समझते हैं कि रुपये की कीमत में गिरावट का मुख्य कारण कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें हैं, जिससे व्यापार घाटा तेज़ी से बढ़ रहा है, और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा शेयर बाज़ारों में भारी बिकवाली भी जारी है। भुगतान संतुलन का पहला हिस्सा वस्तुओं के व्यापार संतुलन से आता है। हम देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में, वस्तुओं के आयात में बढ़ोतरी और निर्यात में सुस्ती का रुझान काफी बढ़ा है। लेकिन साल 2025-26 के दौरान, आयात में अचानक तेज़ी देखी गई, जबकि निर्यात लगभग स्थिर रहा; इसके परिणामस्वरूप वस्तु व्यापार घाटा 50 अरब अमेरिकी डॉलर बढ़ गया, और 2024-25 के 283.5 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2025-26 में 333.2 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। हालांकि, घाटे में हुई इस भारी बढ़ोतरी की कुछ हद तक भरपाई सेवाओं के व्यापार में हुए अतिरिक्त अतिरेक से हो गई; यह अतिरेक 2024-25 के 188.8 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2025-26 में 213.9 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, यानी इसमें 25 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई। अगर हम भारत द्वारा आयात किए जाने वाले मुख्य सामानों पर नज़र डालें, तो उनमें पेट्रोलियम उत्पाद, सोना, खाने का तेल, रासायनिक उर्वरक आदि शामिल हैं। वैश्विक संघर्षों, बाधित मूल्य श्रृंखलाओं और हमारे विदेशी मुद्रा भंडार के खत्म होने के खतरे के कारण लगातार गिरते रुपये की समस्या की गंभीरता को देखते हुए, देश के हितों की रक्षा के लिए राष्ट्र को संकीर्ण राजनीतिक विमर्शों से ऊपर उठकर तेजी से कदम उठाने होंगे।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

मंथन

विवेक मिश्रा

साझा परिवहन जैसे प्रयोगों से ही होगी ईंधन की बचत

वैश्विक अर्थव्यवस्था को दलदल में घसीट रहे, पश्चिम एशिया के संघर्ष से, भारत जैसे प्रगतिशील देश अछूते रह सकें, यह संभव नहीं है। ऊर्जा की नश्वर तैलीय तमन्नाओं के उन्माद ने तरक्की पसंद मुल्कों की सरल राहों को रोका है। अतिवाद और तेलीयकरण के परिवेश में शांति प्रयासों की कोई सुबह होती नहीं दिख रही है, बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल की कीमतें इस वास्तविकता की पुष्टि कर रहीं हैं। ऐसे संकटकाल में प्रधानमंत्री की देशवासियों से उपयोग व उपभोग में संयम बरतने की अपील, धैर्य की सभी कसौटियों को कसने के बाद ही की गई होगी, हम यह मानकर चलें। राजनीतिक दृष्टि से इस अपील की गहन गवेषणा की जा सकती है। इस एवज में कि हम अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 85% विदेशों से आयात करते है, जिसमें फारस की खाड़ी वाले मार्ग का हिस्सा 35% है। चीन के बाद गोल्ड का सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत है और यह भी आयात पर ही निर्भर है। इस तरह ईंधन और स्वर्ण आभूषण से दबी भारतीय अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय मुद्रा डॉलर पर बहुत निर्भर करती है, जंग से निर्मित हालातों में बढ़ती कीमतों और हमारी मांगों से विदेशी मुद्रा भंडार के तेजी से कम होने का खतरा बढ़ रहा है, जनवरी की तुलना में मई 2026 में यह लगभग 723 बिलियन डॉलर से 690 बिलियन डॉलर पर आ चुका है। इन परिस्थितियों में संयम के संयुक्त प्रयत्नों से ही हम भारत के प्रगति पथ को निर्बाध संचालित रख सकते हैं। संयुक्त प्रयास इसलिए महत्वपूर्ण है , क्योंकि यह हम 140 करोड़ भारतीयों के दैनंदिन व्यवहार और बरतने की आदतों से जुड़ा विषय है। प्रयासों के इस क्रम में नेतृत्व कर्ताओं द्वारा अपने काफिलों से कमोबेश पचास प्रतिशत वाहन कम करने की बात कही गई है, जिसकी पालना फिलहाल कई माननीयों के द्वारा सड़कों पर किए गए वाहन शक्ति प्रदर्शन में देखने को नहीं मिल सकी, हालांकि केंद्रीय व शीर्ष नेतृत्व सराहनीय रूप से प्रयास कर रहे हैं । निजी क्षेत्र जरूर अपने सशक्त तकनीकी ढांचे के दम पर वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्था को तुरंत मूर्तरूप दे सकते हैं। सरकारी कार्यालयों में भी अधिकारियों-कर्मचारियों के आवागमन को सार्वजनिक व साझा परिवहन से जोड़कर इच्छित परिणाम हासिल किए जा सकते है। अधिकांशतः सभी सरकारी दफ्तर सप्ताह में पांच दिन संचालित किए जाते हैं, लेकिन देशभर में स्कूल प्रायः सप्ताह में छह दिन लगाए जा रहे हैं। ग्रीष्मकालीन अवकाशों की अवधि भी 1980 से 2010 तक 2 माह तक हुआ करती थी , यह अधिकांश राज्यों में अब 30 से 45 दिन तक सिमट चुकी है। आने वाले 1 वर्ष के लिए यदि 5 दिवसीय व्यवस्था और ग्रीष्मकालीन अवकाश को बढ़ाने का निर्णय लिया जाता है, तो कुछ चमत्कृत परिणाम हासिल हो सकते है। एक प्रयोग मॉडल के तरह हम इस पर विमर्श कर सकते हैं:- इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के हिसाब से देशभर के 10 लाख सरकारी स्कूलों में 51 लाख सरकारी शिक्षक कार्यरत हैं। यदि यह सभी शिक्षक बाइक साझा कर अपने अपने घरों से स्कूल आने जाने के लिए कम से कम 10 किलोमीटर का सफर भी तय करते हैं, तो एक मोटरसाइकिल से दो शिक्षकों को 200 एम.एल. पेट्रोल की जरूरत होती है। वहीं देशभर के शिक्षकों के साथ ईंधन की यह खपत 510000 लीटर /प्रतिदिन हो जाती है। पेट्रोल की इस खपत को यदि अगले एक वर्ष के लिए फाइव डे वर्किंग मॉडल और 2 महीने के ग्रीष्मकालीन अवकाश से जोड़ दें (मौजूदा 1 माह के अवकाश से 30 दिन अधिक) तो कुल 39,780,000 लीटर पेट्रोल की बचत की जा सकती है। इतने मात्रा के पेट्रोल को परिष्कृत करने में लगने वाले कच्चे तेल की तादाद 86,478,261 लीटर या 77,698 मीट्रिक टन हो जाती है। (1 लीटर कच्चे तेल से लगभग 450 एम.अल. पेट्रोल का उत्पादन होता है।) आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 478 करोड़ रुपये होगी। हालांकि यह तथ्य भी स्पष्ट करना जरूरी है, कि भारत में कच्चे तेल की प्रतिदिन खपत 7,50,000 मीट्रिक टन है,अर्थात वर्षभर किए गए इन तमाम प्रयासों के बाद भी हम एक दिन की खपत का केवल 10% प्रतिशत ही कच्चा तेल बचा सकेंगे, जो देश में मात्र ढाई घंटे की आपूर्ति को पूरा करेगा। प्रथम दृष्टया इस प्रयोग का सीमित प्रभाव क्षेत्र हमें हताशा से भर सकता है, किंतु यह ध्यान रखना होगा कि यह 51 लाख सरकारी शिक्षकों के साथ किया गया प्रयोग है और यह भारत की कुल जनसंख्या का मात्र 0.36% प्रतिशत है। इस मॉडल को स्कूलों में पढ़ने वाले 25 करोड़ विद्यार्थियों की संख्या के अनुपालन से और प्रधानमंत्री के 140 करोड़ भारतीयों से किए गए आग्रह के अनुशासन से जोड़ दिया जाए, तो अगले एक वर्ष में जो परिणाम हम हासिल करेंगे, वह प्रत्येक भारतीय को राष्ट्रभावना के अप्रतिम रोमांच से भर देगा।

(लेखक शिक्षाविद हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

शिवत्व की साधना

संकलित
दर्शन

हर कर्म का आरंभ संकल्प से होता है। बातों को बनाने, बिगाड़ने व संभालने का आधार भी हमारा सोच रूपी कर्म है। अच्छे या बुरे सोच के कारण हमारे कर्म और कर्मफल सुखदायी व दुखदायी होते हैं। इसलिए कहते हैं, परमात्मा शिव अपनी शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्पों से सोच को परिष्कृत कर दुनिया को परिवर्तित कर देते हैं। उनका प्रत्येक संकल्प मानवता का कल्याण व सद्ज्ञान है, जिसकी वर्षा से प्रकृति में शांति, संतुलन, सद्भावना व प्रसन्नता का वातावरण निर्मित होता है। मानव जीवन व संसार से विकार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, दुख, कष्ट व हिंसा के ताप समाप्त होते हैं। परमात्मा के इस सृष्टि परिवर्तन या उद्धार कार्य से कृतज्ञ होकर हम श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा-अर्चना और व्रत-उपवास करते हैं। शिव की महिमा स्मरण, गायन, पूजन व श्रवण से श्रावण मास शिवमय हो जाता है। कहते हैं, चातुर्मास के आरंभ में भगवान विष्णु जब शयन में चले जाते हैं, तब परमात्मा शिव संसार की बागडोर संभालते हैं। शिव निराकार ज्योति स्वरूप हैं। वे शिव ज्ञान व योग सिखाकर मनुष्यों में सतयुगी दिव्य गुण व दैवी संस्कारों को पुनः विकसित करते हैं। जब भगवान विष्णु योगनिद्रा में चले जाते हैं, तब सृष्टि को बचाने एवं भक्तों की शुद्ध भावनाओं और कामनाओं का फल देने हेतु शिव अदृश्य रूप में संसार का कार्यभार संभालते हैं। ज्ञान सूर्य ज्योति स्वरूप शिव अपने ईश्वरीय ज्ञान व शिक्षा के प्रकाश द्वारा मनुष्यों के आसुरी अवगुणों को सद्गुण, दैवी चरित्र व दैवी संस्कारों में बदलते हैं।

सेवा का समर्पण भाव

संकलित
प्रेरणा

एक बार एक राजा भोजन कर रहा था, अचानक खाना परोस रहे सेवक के हाथ से थोड़ी सी सब्जी राजा के कपड़ों पर छलक गई। राजा की त्यौरियां चढ़ गयीं। जब सेवक ने यह देखा तो वह थोड़ा घबराया, लेकिन कुछ सोचकर उसने प्याले की बची सारी सब्जी भी राजा के कपड़ों पर उड़ेल दी। अब तो राजा के क्रोध की सीमा न रही। उसने सेवक से पूछा, तुमने ऐसा करने का दुस्साहस कैसे किया? सेवक ने अत्यंत शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज! पहले आपका गुस्सा देखकर मैनें समझ लिया था कि अब जान नहीं बचेगी। लेकिन फिर सोचा कि लोग कहेंगे की राजा ने छोटी सी गलती पर एक बेगुनाह को मौत की सजा दी। ऐसे में आपकी बदनामी होती। तब मैनें सोचा कि सारी सब्जी ही उड़ेल दूं। ताकि दुनिया आपको बदनाम न करे। और मुझे ही अपराधी समझे। राजा को उसके जबाव में एक गंभीर संदेश के दर्शन हुए और पता चला कि सेवक भाव कितना कठिन है। जो समर्पित भाव से सेवा करता है उससे कभी गलती भी हो सकती है फिर चाहे वह सेवक हो, मित्र हो, या परिवार का कोई सदस्य, ऐसे समर्पित लोगों की गलतियों पर नाराज न होकर उनके प्रेम व समर्पण का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि ये ही लोग हमारे सच्चे हितैषी और सेवक होते हैं।

अंतर्मन

आज की पाती

आस्था, मोक्ष व मानवता का महापर्व गंगा दशहरा

भारतीय संस्कृति में नदियों को केवल जलधारा नहीं बल्कि जीवन, चेतना और मोक्ष का स्रोत माना गया है। इनमें भी मां गंगा का स्थान सर्वोच्च है। करोड़ों भारतीयों की आस्था का केंद्र गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि सनातन सभ्यता की आत्मा हैं। हिमालय की गोद से निकलकर मैदानों को जीवन देने वाली गंगा सदियों से भारतीय संस्कृति, अध्यात्म, कृषि, साहित्य और लोकजीवन की धुरी रही है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मनाया जाने वाला गंगा दशहरा दिव्य चेतना और गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का महापर्व है। मान्यता है कि इसी दिन मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इस बार यह पर्व अत्यंत शुभ और दुर्लभ संयोगों में आया है। यह आस्था, मोक्ष व मानवता का महापर्व है। – *विवेक पटेरिया, राजनांदगांव*

करंट अफेयर

श्रीलंका में कानून-व्यवस्था बनाने भारत ने दिए 134 पुलिस वाहन

भारत ने सोमवार को कोलंबो में राष्ट्रपति भवन परिसर में आयोजित समारोह में श्रीलंका को 134 पुलिस वाहन सौंपे, जिसे दोनों देशों के बीच 'बहुआयामी विकास साझेदारी' में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। इस सौदे से जुड़े समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर दिसंबर 2024 में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके की नयी दिल्ली यात्रा के दौरान हस्ताक्षर हुए थे। भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, 'राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके की गरिमामयी उपस्थिति में श्रीलंका पुलिस को 30 करोड़ श्रीलंकाई रुपये से खरीदे गए 134 वाहन सौंपे गए।' उन्होंने बताया कि श्रीलंका पुलिस के अनुरोध पर की गई यह पहल सड़क सुरक्षा, नागरिकों को समय पर मदद पहुंचाने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक होगी। भारतीय उच्चायोग ने एक बयान में कहा कि इस बेड़े की सुपुर्दगी भारत और श्रीलंका के बीच सभी प्रमुख क्षेत्रों में जारी बहुआयामी विकास साझेदारी में एक और महत्वपूर्ण अध्याय है। राष्ट्रपति दिसानायके के अलावा श्रीलंका के सुरक्षा मंत्री आनंद विजेपाल और पुलिस महानिरीक्षक प्रियंत वीरसुरिया भी समारोह में मौजूद थे।

ऑफ बीट

विटामिन बी3 सप्लीमेंट से त्वचा कैंसर के खतरे कम

त्वचा कैंसर दुनिया का सबसे आम प्रकार का कैंसर है। इस कैंसर का कारण लगातार धूप में रहने, गोरी त्वचा और उम्र बढ़ने से जुड़ा है। रोकथाम की मौजूदा रणनीतियां पराबैंगनी (यूवी) किरणों से बचाव और 'सनस्क्रीन लोशन' के इस्तेमाल पर केंद्रित हैं। यह भी देखने में आया है कि एक बार त्वचा कैंसर का पता चलने पर कई बार रोगियों को इसकी पुनरावृत्ति का सामना करना पड़ता है। निकोटिनामाइड एक सस्ता और व्यापक रूप से उपलब्ध सप्लीमेंट है, जिसका इस्तेमाल त्वचा कैंसर से बचाव के लिए किया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि विटामिन बी3 का यह रूप पराबैंगनी किरणों से होने वाली क्षति के बाद त्वचा की प्राकृतिक मरम्मत प्रणालियों को मजबूत करता है, सूजन कम करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को असामान्य कोशिकाओं का पता लगाने तथा उन्हें हटाने में मदद करता है। नये अध्ययन में 12,000 से अधिक रोगियों, जिन्होंने एक महीने से अधिक समय तक प्रतिदिन दो बार 500 मिलीग्राम निकोटिनामाइड लेना शुरू किया, की तुलना 21,000 से अधिक रोगियों से की गई, जिन्होंने इसे नहीं लिया। निकोटिनामाइड लेने वालों में फिर से त्वचा कैंसर के विकास का जोखिम 14 प्रतिशत कम देखा गया।

X ट्रेंड

बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाएं

भीषण गर्मी को देखते हुए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया अपने राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में नीट परीक्षा आयोजित करने वाले जिले के अधिकारियों व सभी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में जरूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उचित निर्देश जारी करें। -**धर्मेंद्र प्रधान**, केंद्रीय शिक्षा मंत्री

देश में इबोला का केस नहीं

सभी अधिकारी देश भर में हवाई अड्डों, बंदरगाहों और भूमि सीमा पार करने सहित देश के सभी प्रवेश बिंदुओं पर इबोला स्क्रीनिंग व्यवस्था को पूरी तरह से सतर्क और मजबूत रखें। अभी देश में इबोला का कोई केस नहीं है यह राहत वाली बात है। -**जेपी नड्डा**, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री

एक और संस्था धांधली का प्रतीक

मोदी-प्रधान की जोड़ी ने एक और संस्था को धांधली का प्रतीक बना दिया। दशकों में पहली बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर इतने गंभीर सवाल उठे हैं। 18.5 लाख बच्चों ने परीक्षा दी और एक हफ्ते से ओएसएम गलत मार्किंग और जांच की गड़बड़ी की शिकायतें अनसुनी पड़ी हैं और शिक्षा मंत्री अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं। -**राहुल गांधी**, नेता विपक्ष

भारत में कम बढ़ोतरी

नेता विपक्ष राहुल गांधी देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया भर में तेल और डीजल की कीमतों में भारी उछाल आया है, हालांकि, इसकी तुलना में भारत में कीमतों में हुई बढ़ोतरी मामूली रही है, विशेष रूप से तब जब इसे अमेरिका, ब्रिटेन और खाड़ी देशों में हुई वृद्धि के साथ देखा जाए। -**गौरव भाटिया**, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

दैनिक जागरण
ऊर्जा का अपव्यय पतन की ओर ले जाता है

विकसित भारत के निर्माण की राह

सीपी राधाकृष्णन

निरंतर विकास का युग बनाने के लिए सरकार और जनता, दोनों का साझा उत्साह ही देश की प्रगति का कारण है

जब मैं तिरुप्पुर के स्कूल में पढ़ता था, तब मेरे मन में अक्सर ये सवाल उठते थे कि भारत अपनी महानता कब वापस पाएगा? हमारे गरीब और वंचित भाई-बहनों को सम्मानजनक जीवन कब मिलेगा? मुझे खुशी है कि किशोरावस्था में मेरे मन में जो विचार थे, वे अब साकार हो रहे हैं। मैं अक्सर खुद को स्वामी विवेकानंद के इन शब्दों की याद दिलाता था, 'उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको।' स्वामीजी के ये उद्गार हर व्यक्ति में देशभक्ति और समर्पण की भावना जगाने की अपार शक्ति रखते हैं। मेरा हमेशा यह विश्वास रहा कि जब भारत अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ेगा, तब वह पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला राष्ट्र बनकर उभरेगा। अब हमें अपनी आंखों के सामने तिरुवल्लुवर के इन शब्दों की सच्चाई देखने का अवसर मिल रहा है- 'जो अपने संकल्प में अडिग रहते हैं, वे ठीक वही हासिल करते हैं, जिसकी उन्होंने कल्पना की होती है।' पिछले एक दशक में मुझे यह देखकर खुशी होती है कि हमारा देश जबरदस्त ऊर्जा और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।

आज जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी और अनिश्चितताओं से जूझ रही है, तब भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती और तेजी से आगे बढ़ रही है। इस दौर को निरंतर विकास का युग बनाने के लिए सरकार और जनता दोनों का साझा उत्साह ही इस प्रगति का कारण है। एक समय कमजोर अर्थव्यवस्था माने जाने वाला हमारा देश आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जल्द ही तीसरी बड़ी आर्थिकी बनने की दिशा में अग्रसर है। हमारा आर्थिक विकास समावेशी रहा है। पिछले एक दशक में लगभग 25 करोड़ भारतवासी अत्यधिक गरीबी से बाहर निकलकर सम्मानपूर्ण जीवन जीने में सक्षम हुए हैं। अब तक भारत में गरीब और बेघर लोगों के लिए लगभग चार करोड़ पक्के घर बनाए जा चुके हैं। 12 करोड़ से अधिक लोगों को पाइप से पीने के पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न मुफ्त दिया जा रहा है, जिस पर 2.3 लाख करोड़ रुपये का खर्च किया जा रहा है। मैंने गांवों में लोगों को इलाज की सुविधा न मिलने के कारण परेशान होते देखा है। उनके परिवारों की पीड़ा देखकर मुझे दुख होता था। आज देश इस संकल्प के साथ आयुष्मान भारत योजना चला रहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं हर व्यक्ति तक पहुंचें। इसी का परिणाम है कि अब 44 करोड़ से अधिक लोगों को पीएम आयुष्मान भारत योजना के तहत पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिल रहा है। केवल पिछले एक वर्ष में ही 2.5 करोड़ लोगों ने इस योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज प्राप्त किया है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक चार लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जा चुकी है। तीन करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी और नमो ड्रोन दीदी बनकर अपना जीवन संवार चुकी हैं। महिलाओं के दैनिक जीवन को आसान बनाने और उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए लगभग दो करोड़ नए एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद और राज्य विधानसभाओं में आधी आबादी की भागीदारी को और सशक्त बनाएगा।

प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं तथा एकलव्य माडल आवासीय विद्यालयों ने क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को बहुत लाभ पहुंचाया है। युवा शक्ति के लिए पिछले दस वर्षों में ही 13 नए आइआइटी स्थापित किए गए हैं। आइआइएम की संख्या 13 से बढ़कर 21 हो गई है। एम्स की संख्या सात से बढ़कर 23 हो चुकी है। मेडिकल कालेजों की संख्या भी बढ़कर 823 हो गई है। यह गर्व की बात है कि मेडिकल छात्रों के लिए सीटों की संख्या 51,348 से बढ़कर 1,29,603 हो गई है। हम विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय रेलवे का लगभग 99 प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है। वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों की संख्या बढ़ रही है। हवाई अड्डों की संख्या भी 74 से बढ़कर 163 हो गई है और उड़ान योजना के तहत आम लोगों के लिए हवाई यात्रा सुलभ हुई है। नए पंबन ब्रिज से लेकर चिनाब ब्रिज हो या बोगीबील पुल, भारत अब आधुनिक बुनियादी ढांचे के नए आयाम स्थापित कर रहा है। जो सीमावर्ती गांव कभी भारत के अंतिम गांव माने जाते थे, वे अब देश के प्रथम गांव बन चुके हैं और वाइब्रेंट विलेज स्कीम के माध्यम से उनका विकास किया जा रहा है।

अवधेश राजपूत

चंद्रयान-3 की सफल लांचिंग ने भारत को उन्नत अंतरिक्ष अनुसंधान के नए युग में पहुंचा दिया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआइ के क्षेत्र में वैश्विक कंपनियां भारत को अपना केंद्र बना रही हैं, जिससे निवेश में कई गुना वृद्धि हुई है। भारत अब सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में दुनिया के लिए एक माडल बनकर उभर रहा है। मोबाइल फोन उत्पादन में भी हमने विश्व में दूसरा स्थान हासिल किया है। जो भारत कभी मोबाइल फोन आयात करता था, वही आज 300 करोड़ डालर के मोबाइल फोन निर्यात करने वाला देश बन चुका है। ये सभी उपलब्धियां आने वाली पीढ़ियों के समृद्ध भविष्य की मजबूत नींव बनेंगी। कई दशकों तक देश ने केवल आतंकवाद ही नहीं, बल्कि उग्रवाद और वामपंथी चरमपंथ जैसी चुनौतियों का भी सामना किया है।

हमने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2047 तक यानी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक, भारत एक अग्रणी वैश्विक शक्ति बने और दुनिया का मार्गदर्शन करने की स्थिति में पहुंचे। कठिन परिश्रम का यह दौर ही अमृतकाल है। जिस प्रकार स्वतंत्रता सेनानियों के हृदय में आजादी की प्यास थी, उसी तरह आज के युवाओं के मन में राष्ट्र विकास का संकल्प होना चाहिए। इस अमृतकाल में यदि युवाओं के विचार और प्रयास देशभक्ति, उच्च आदर्शों और श्रेष्ठ चरित्र के साथ आगे बढ़ेंगे, तब हम 2047 में एक विकसित भारत का सपना साकार होते देख सकेंगे।

(लेखक भारत के उपराष्ट्रपति हैं)
response@jagran.com

चुनौती भरे दिन

बीते चंद दिनों के अंदर चौथी बार पेट्रोल-डीजल के मूल्यों में वृद्धि यही बताती है कि तेल कंपनियों के लिए उनके दाम स्थिर रखना संभव नहीं रह गया है। पेट्रोल-डीजल के साथ गैस के दाम इसीलिए बढ़ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका-ईरान के बीच टकराव के चलते वह होर्मुज समुद्री मार्ग बाधित है, जहां से विश्व के पांचवें हिस्से की ऊर्जा आपूर्ति होती है। चूंकि भारत अपनी आवश्यकता का 85 प्रतिशत से अधिक ईंधन आयात करता है, इसलिए उसके सामने पेट्रोल-डीजल-गैस के दाम बढ़ाने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। जो मजबूरी भारत के समक्ष आ खड़ी हुई है, वही विश्व के अन्य देशों के सामने भी है। इसकी अनदेखी न की जाए कि भारत ने अन्य देशों की तुलना में कहीं बाद में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ाए। पेट्रोल-डीजल और गैस के बढ़ते दामों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिस तरह यह कहा कि तेल, उर्वरकों और विदेशी मुद्रा पर कड़ी निगाह रखने की जरूरत है, उसकी पूर्ति तो सरकार को स्वयं ही करनी होगी। आम जनता इतना अवश्य कर सकती है और उसे करना भी चाहिए कि किफायत बरतने के उन उपायों पर ध्यान दे, जो सरकार और विशेष रूप से प्रधानमंत्री की ओर से सुझाए गए हैं। लोगों को यथासंभव इसके प्रति सतर्क रहना चाहिए कि उनके क्रियाकलापों से विदेशी मुद्रा पर बोझ न बढ़े। वे इसे अनदेखा नहीं कर सकते कि वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि ईंधन के साथ उर्वरकों की कीमतें अकल्पनीय रूप से बढ़ रही हैं और सोने के दाम भी चुनौती बन गए हैं। इसका अर्थ है कि आने वाले दिन और अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। यह वित्त मंत्री के इस कथन से और भी स्पष्ट होता है कि पश्चिम एशिया संकट का असर जियो-पालिटिक्स से कहीं आगे तक जाता है और कारोबारियों एवं आम लोगों के लिए इसका मतलब हो सकता है- ईंधन की ज्यादा कीमत, कार्गो में देरी, शिपिंग का महंगा होना, इनपुट की अधिक लागत और निर्यात आर्डर में अनिश्चितता। उन्होंने यह भी कहा कि जरा सोचिए, जब ये सभी चीजें एक साथ सामने आए जाएं, तो क्या होगा? निःसंदेह अच्छा नहीं होगा, लेकिन उनकी इस बात का विपक्षी दलों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला कि कुछ लोग डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें ऐसा करने की बजाय लोगों में विश्वास जगाना चाहिए। जब विपक्षी नेता पहले से ही यह माहौल बना रहे हैं कि जानबूझकर महंगाई बढ़ाने वाले काम किए जा रहे हैं, तब यह जिम्मेदारी सरकार की ही है कि वह लोगों को वस्तुस्थिति से अवगत कराए और उनमें यह भरोसा पैदा करे कि तमाम बाहरी चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है। उसके लिए यह भी जरूरी है कि चुनौतियों से पार पाने के लिए जो जरूरी फैसले लेने हैं, उनमें देर न की जाए।

बेकाबू आवारा आतंक

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जिस तरह एक बच्ची आवारा आतंक का शिकार हुई, वह केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि नगर निगम प्रशासन की संवेदना पर शर्मनाक और सवालिया निशान है। मात्र दस वर्षीय बच्ची आवारा कुत्तों के झुंड के सामने बेबस होकर तड़पती रही और इस हृदयविदारक घटना में उसकी जान चली गई। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद हिंसक आवारा कुत्तों को नियंत्रित करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पहले भी कुत्तों के काटने से लोगों की जान जा चुकी है, फिर भी प्रशासन की नींद नहीं टूटी। बच्ची की मौत के बाद टीमें दौड़ाई गईं और कुछ कुत्ते पकड़े गए। क्या एक मासूम बच्ची की मौत के बाद ही प्रशासन जागता है? यह समस्या केवल शाहजहांपुर की नहीं है। समूचे उत्तर प्रदेश में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। हालांकि यह कहना अधिक उचित होगा कि समूचे देश में यह समस्या बढ़ रही है। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सबसे अधिक असुरक्षित हैं। यदि तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो ऐसे हादसे रोजमर्रा की बात बन जाएंगे। नगर निगम प्रशासन को अब बहाने नहीं, जवाबदेही दिखानी होगी। एनीमल बर्थ कंट्रोल कार्यक्रम को सख्ती से लागू करना होगा। बिना बधियाकरण के कुत्तों को छोड़ना बंद करना होगा। चिह्नित स्थानों पर फीडिंग प्वाइंट बनाकर नियमित निगरानी करनी होगी। नगर आयुक्त और संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह बनाना होगा, तभी ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रुक सकेगी।

सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद हिंसक आवारा कुत्तों को नियंत्रित करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया

गैर इस्लामी है सड़क पर नमाज

फिरोज बख्त अहमद

अगर मस्जिद में जगह कम है तो दो या तीन बार जमातें की जा सकती हैं। नमाज घरों या छतों पर भी हो सकती है

पहले से ही 45-50 डिग्री में धधक रहे भारत में बंगाल के एक भड़काऊ नेता हुमायूं कबीर ने यह कहकर सियासी पारा और बढ़ा दिया है कि आने वाली बकरीद को मुस्लिम सड़कों पर ही नमाज पढ़ेंगे, जबकि यह गैर-इस्लामी, गैर-कानूनी और गैर-इंसानी कृत्य है। विडंबना यह है कि भोले भाले आम मुस्लिम ऐसे ही लोगों को अपना नेता समझ लेते हैं। सड़क पर नमाज पढ़ने की जिद शायद बंगाल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के सड़कों पर नमाज न पढ़ने के आदेश के चलते की जा रही है। इस्लाम के बारे में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की राय रखे, यह उसका निजी अधिकार है, मगर इसमें तीन बढ़िया बातें अवश्य हैं। प्रथम तो इस्लाम कहता है, 'लकुम दीनोकुम वले यदीन,' अर्थात तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, हमें हमारा! दूसरी बात है 'हुकूक-उल-इबाद' अर्थात बिना किसी फर्क के दूसरों के जायज अधिकारों की मान्यता और तीसरा है, 'फमैयांमल मिस्काला जर्रातिन खैरईंयरा/वमैयांमल मिस्काला जर्रातिन शररईंयरा' अर्थात यदि कोई भी मुस्लिम कितनी ही मामूली अच्छाई किसी के साथ भी करेगा तो उसे उसका बदल यानी फल मिलेगा। यदि किसी मुस्लिम ने किसी के साथ कोई बुराई की तो उसे उसका भी वैसा ही बदल यानी फल मिलेगा। इन्हीं सब कारणों से भी सड़क पर नमाज पढ़ना गैर-इस्लामी है।

हदीस-ओ-कुरान की रोशनी में हजरत मोहम्मद (स.) के अनुसार सात स्थानों पर नमाज पढ़ने की स्वीकृति नहीं है, जिनमें सड़क भी शामिल है। जो आम रास्ता हो, वहां पर नमाज की तो बिल्कुल मनाही है। यह ध्यान रहे कि अरब देशों में सड़कों पर नमाज की इजाजत नहीं है। हजरत मोहम्मद ने अपने हाथों से एक ऐसी निर्माणाधीन मस्जिद की दीवार को गिरा दिया था, जिसे कुछ जोशीले मुस्लिम सहाबा किसी गैर मुस्लिम की जमीन पर कब्जा कर वहां मस्जिद बना कर दीन की खिदमत करना चाह रहे थे, मगर क्या औसत मुस्लिम उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं? इस संदर्भ में एक जुमला चल निकला है, 'हम हजरत मोहम्मद साहब को तो मानते हैं, मगर उनकी बात नहीं!'

साझा जिम्मेदारी है सामाजिक सौहार्द बनाए रखना। फाइल

मुस्लिमों की भी जायज शिकायत है, जिससे कुछ हिंदू भी सहमत हैं कि जब कांवड़ यात्राएं लाउडस्पीकरों के साथ निकलती हैं और विभिन्न अवसरों पर शोभा यात्राएं निकलती हैं तो उससे भी लोगों को समस्या होती है। इसका तर्क यह दिया जाता है कि ये सब कार्य तो वर्ष में एक बार ही होते हैं और मुस्लिम तो हर हफ्ते सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं। अब इसमें सरकारें यह कर सकती हैं कि मात्र ईद, बकरीद और जुमातुल विदा को 25 से 30 मिनट तक के लिए नमाज की अनुमति दे सकती हैं। वैसे अगर मस्जिद में जगह कम है तो दो या तीन बार जमातें की जा सकती हैं। नमाज घरों या छतों पर भी हो सकती है। कई जगहों पर होती भी है। आम मुसलमानों के साथ समस्या यह है कि वे स्वयं ही न तो अपने मजहब को अच्छी तरह समझते हैं और न ही दूसरों को समझा पा रहे हैं। अल्लाह केवल मुस्लिमों का नहीं, सभी का है। इसी कारण उसे रब्बुल आलमीन कहा जाता है यानी सभी का ईश्वर।

इस्लाम को एक फुटबाल की तरह इधर-उधर भटकाया जाता रहा है। इसमें हमारे अपने ही कुछ उलमा, सियासी नेता और बौद्धिक वर्ग के लोग शामिल हैं। हुमायूं कबीर धमका रहे हैं कि लोग सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे और बकरीद पर गायों की कुर्बानी भी देंगे। ऐसे ही लोगों के कारण तनाव फैलता है। अच्छी बात यह है कि कौम को गलत रास्ते पर डालने वाले ऐसे लोगों का विरोध करने वाले भी मुस्लिम समाज में मौजूद हैं, जैसे 'इंटर फेथ हार्मनी फाउंडेशन आफ इंडिया' के अध्यक्ष ख्वाजा इफ्तिखार अहमद। उन्होंने उन बंगाली मुसलमानों को मुबारकबाद दी, जिन्होंने बकरीद पर गाय की कुर्बानी न करने का निर्णय लिया। शायद आम मुस्लिम यह भूल गए हैं कि मोहम्मद साहब ने कहा है कि गाय का दूध रहमत है और गोश्त जहमत (जहर)! गाय के बचाव में इससे अधिक क्या कहा जा सकता है।

यह ध्यान में रखते हुए कि हिंदू समाज गाय का आदर करता और उसे पूजता है, मुसलमान न के बराबर ही गाय को काटते हैं। अपने दौर में शहंशाह बहादुर शाह जफर ने भी फतवा दिया था कि बकरीद पर गाय की कुर्बानी न दी जाए। इसी प्रकार से दारुल उलूम देवबंद की ओर से भी फतवा जारी किया जा चुका है कि गाय का वध न करें, क्योंकि हम साझा विरासत के पैरोकार हैं और ऐसा कोई कार्य न करें कि जिससे किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस लगे। यह बात सभी मजहबों के लोगों पर लागू होती है। एक-दूसरे की भावनाओं का आदर करना चाहिए।

भारत के मुसलमान भलीभांति समझते हैं कि कुरान उनका धार्मिक संविधान है तो बाबा साहेब भीमराम आंबेडकर का लिखा कानून उनका राष्ट्रीय संविधान। जब किसी भी आस्था, मजहब को मानने वाला सड़क पर आता है तो वह भारतीय पहले होता है और हिंदू, मुस्लिम बाद में। अब समय है कि हम न तो हिंदू कार्ड खेलें, न मुस्लिम कार्ड, बल्कि भारत कार्ड अपने हाथ में मिलकर थामें, ताकि जगत गुरु बनने की राह पर स्पीड ब्रेकरों से पार पाते हुए सफलता से निकल सकें और देश को विकसित बना सकें।

(लेखक पूर्व कुलाधिपति और समाजसेवी हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

आंतरिक विजय

मनुष्य का शरीर एक रथ के समान है, जिसमें इंद्रियों को उन अश्वों की संज्ञा दी जा सकती है, जो हमें सांसारिक विषयों की ओर उन्मुख करते हैं। यदि इन अश्वों की लगाम ढीली छोड़ दी जाए, तो रथ का मार्ग से भटकना और जीवन का अनियंत्रित होना निश्चित है। आज के उपभोक्तावादी युग में हमारी इंद्रियां बाहरी आकर्षणों के पीछे कहीं अधिक रफ्तार से भाग रही हैं, जिससे मानसिक अशांति और असंतोष भी उसी अनुपात में बढ़ रहा है।

सुख की खोज भी हम अक्सर बाहरी वस्तुओं में करते हैं, लेकिन वास्तविक सुख इंद्रियों के दमन में नहीं, अपितु उनके संयम में छिपा है। जब आंखें केवल शुभ देखती हैं, कान केवल कल्याणकारी सुनते हैं और वाणी केवल सत्य बोलती है, तब मनुष्य के भीतर एक असीम ऊर्जा का संचार होता है। हमारे मनीषियों ने अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर कहा है कि अनियंत्रित इंद्रियां हमारी संकल्प शक्ति को क्षीण कर देती हैं, जबकि संयमित इंद्रियां एकाग्रता और आत्मबल का आधार बनती हैं। गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने भी इंद्रिय नियंत्रण के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा कि-हे अर्जुन! तुम सबसे पहले इंद्रियों को वश में करो, क्योंकि ये ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी का रूप धारण करने वाले काम या वासना को मारने के लिए अनिवार्य है।

इंद्रियों पर विजय प्राप्ति का सबसे सुलभ मार्ग सजगता है। जब हम अपने प्रत्येक कर्म के प्रति जागरूक हो जाते हैं, तो इंद्रियां स्वतः अनुशासित होने लगती हैं। आहार, आचार, विचार और व्यवहार में संतुलन ही वह कुंजी है, जो हमें विषयों के दासत्व से मुक्त कर स्वयं का स्वामी बनाती है। जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, उसने समस्त संसार को जीत लिया, क्योंकि आंतरिक विजय ही वास्तविक सफलता है।

लवली आनंद

गूगल मैप पर बढ़ती निर्भरता के दुष्प्रभाव

रेणु जैन

गूगल मैप ने यात्रा को सुविधाजनक बनाया है, परंतु इस पर बढ़ती अतिनिर्भरता सही नहीं है

एक समय था जब सफर केवल मंजिल तक पहुंचने का जरिया नहीं, बल्कि अनुभवों और यादों का हिस्सा होता था। लोग रास्तों को याद रखते थे, गलियों की पहचान जानते थे और पेड़, मंदिर, कुएं या दुकानों को निशान बनाकर दिशा तय करते थे। 'पीपल के पेड़ से बाएं मुड़ना' या 'मंदिर वाली गली से सीधे जाना' जैसी बातें केवल रास्ता बताने का तरीका नहीं थीं, बल्कि हमारी स्मृति, समझ और सामाजिक जुड़ाव का हिस्सा थीं, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। जेब से मोबाइल निकला, स्क्रीन पर नीली लाइन चमकी और इंसान बिना सोचे-समझे उसी के पीछे चल पड़ा। गूगल मैप ने जिंदगी को आसान जरूर बनाया है, पर एक क्या यह सुविधा हमारे दिमाग की दिशा नहीं छीन रही है? ऐसा अनेक लोगों के साथ हो रहा है कि कई बार उसी राह से गुजरने के बावजूद बिना गूगल मैप के वहां से सहजता से सफर करना मुश्किल सा होता है। वैज्ञानिक शोध भी इस चिंता को गंभीर मानते हैं।

यूनिवर्सिटी कालेज लंदन के न्यूरोसाइंटिस्टों के अनुसार, जब इंसान स्वयं रास्ता खोजता है, तब दिमाग का 'हिप्पोकैंपस' और 'प्रीफ्रंटल कार्टेक्स' सक्रिय रहते हैं। यही हिस्से स्मृति, निर्णय क्षमता और दिशा ज्ञान को नियंत्रित करते हैं। लेकिन जब व्यक्ति केवल जीपीएस के निर्देशों का पालन करता है- '200 मीटर बाद दाएं मुड़ें' तो दिमाग अपेक्षाकृत कम सक्रिय रहता है। लगातार जीपीएस पर निर्भर रहने का असर हमारी 'काग्निटिव मैपिंग' क्षमता पर भी पड़ रहा है। सरल शब्दों में कहें तो इंसान अपने दिमाग में रास्तों का नक्शा बनाना छोड़ देता है। यही कारण है कि आज कई लोग अपने ही शहर में बिना मैप के निकलने से घबराने लगे हैं। हालांकि तकनीक को पूरी तरह दोष देना भी सही नहीं होगा।

गूगल मैप ने यात्रा को सुरक्षित, तेज और सुविधाजनक बनाया है। अनजान शहरों में रास्ता ढूंढना, आपातकाल में अस्पताल पहुंचना, टैक्सी और डिलीवरी सेवाएं- इन सबमें इसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। समस्या तकनीक नहीं, बल्कि उस पर बढ़ती अतिनिर्भरता है। दिमाग को सक्रिय रखने के लिए कभी-कभी बिना जीपीएस के भी यात्रा करनी चाहिए। परिचित रास्तों को याद रखने की कोशिश करें, संकेतों पर ध्यान दें और दिमाग में मानसिक नक्शा बनाएं। यह दिमाग के लिए वैसा ही व्यायाम है, जैसा शरीर के लिए दौड़ना या योग।

तकनीक इंसान की मदद के लिए बनी है, उसकी सोचने की क्षमता छीनने के लिए नहीं। गूगल मैप रास्ता दिखा सकता है, लेकिन दिशा समझने की ताकत इंसानी दिमाग में ही है। इसलिए जरूरत तकनीक छोड़ने की नहीं, उसके साथ संतुलन बनाने की है। कभी-कभी मोबाइल जेब में रखकर भी रास्ता तय कीजिए- हो सकता है सफर थोड़ा लंबा लगे, लेकिन दिमाग की दिशा जरूर मजबूत होगी।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

धरातल पर उतारनी होगी योजना

'घुसपैठियों की वापसी' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में उचित ही रेखांकित किया गया है कि बंगाल की सुरक्षा और सीमाओं को मजबूत करने की भारत सरकार की दृढ़ नीति अत्यंत सराहनीय है। ममता बनर्जी के 15 साल के कुशासन और वोट बैंक की राजनीति के चलते राज्य की स्थिति पटरी से उतर चुकी थी, जिसे सुधारने के लिए नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की भाजपा सरकार पहले दिन से ही ठोस फैसले ले रही है। परिणामस्वरूप भारत-बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ पर करीब-करीब विराम तो लग गया है, लेकिन असली समस्या लाखों बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने में आएगी। इस नीति की वास्तविक सफलता पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगी कि जमीनी स्तर पर इसका क्रियान्वयन कितना सटीक और सुचारु रहता है। चूंकि ये अवैध घुसपैठिए फर्जी दस्तावेजों के सहारे मतदाता बन चुके हैं, इसलिए जमीनी स्तर पर उनकी पहचान करना और उन्हें सभी जिलों में बन रहे हिरासत केंद्र तक पहुंचाना एक अत्यंत जटिल प्रशासनिक चुनौती होगी। इसके लिए स्थानीय प्रशासन को अत्याधुनिक डिजिटल टूल्स और अचूक डाटा सत्यापन भी करना होगा। यह प्रक्रिया इतनी पारदर्शी होनी चाहिए कि किसी भी वास्तविक भारतीय नागरिक को कोई कष्ट न उठाना पड़े। संक्षेप में, सरकार की सही नीतियों ने दिशा तो तय कर दी है, पर इस राष्ट्रीय संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का पूरा दारोमदार जमीनी तंत्र की कुशलता पर निर्भर होगा।

प्रमोद कुमार गोयल, मेरठ

मेलबाक्स

गिरते रुपये के प्रति चिंता

गिरते रुपये के प्रति चिंता वैश्विक थपेड़ों से जूझता रुपया- शीर्षक लेख में शिवकांत शर्मा ने रुपये की गिरती कीमत को संभालने के लिए कुछ उपाय बताए। यह चिंता भरी खबर है कि हमारे देश के रुपये की कीमत में भारी गिरावट आई। हालांकि सरकार और आरबीआइ इससे निपटने के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यह देश के लिए चिंता की बात है। यह देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए ही नहीं, बल्कि रोजगार और महंगाई के लिए भी टेंशन बढ़ाने वाली हैं। अमेरिकी डालर के मुकाबले हमारे देश के रुपये के गिरने का सिलसिला मोदी सरकार में ही नहीं, बल्कि जाने माने अर्थशास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के राज में भी था। हमारा देश जो कभी सोने की चिड़िया था, उसको पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने और अब अपने ही देश के कुछ स्वार्थी लोगों और सरकारों की गलत नीतियों ने आर्थिक रूप से कुछ कमजोर करके सोने की चिड़िया नहीं छोड़ा। जब तक देश में आर्थिक भ्रष्टाचार रहेगा, वोट बैंक के लिए मुफ्तखोरी की प्रथा रहेगी, तब तक गिरता हुआ रुपया कभी भी नहीं संभलेगा। यहां तो यह विचार करने योग्य है कि सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश की करेंसी डालर के मुकाबले क्यों फिसलती जा रही है? मोदी सरकार भी इस फिसलन को रोकने में नाकामयाब क्यों है? मनमोहन सिंह के राज में भी भारत के रुपये और अमेरिकी डालर में जमीन-आसमान का अंतर क्यों रहा? आमजन जब तक ईमानदारी से टैक्स सरकारी खजाने में जमा नहीं करेंगे और शासन-प्रशासन जब तक उस टैक्स को जनहित के कामों में नहीं लगाएगा, तब तक आर्थिक माहौल कभी भी नहीं बन सकता, चाहे इसके लिए कितने भी उपाय क्यों न सुझाए जाएं या विचार प्रकट किए जाएं। अर्थव्यवस्था की गति को तेज करने के लिए भारत के उद्योगों को मजबूत किया जाए, भारत के व्यापार को दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंचाने की राह को आसान किया जाए, भारत में आयात पर टैक्स बढ़ाए जाएं। चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए देश में कृषि का विस्तार या व्यापक सुधार करके भी देश में आर्थिक माहौल बनाया जा सकता है। अगर रुपये की फिसलने के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई गई तो भारत भारी भरकम कर्जे के नीचे दब जाएगा, जो देश के विकास में भी बाधा बनेगा। इसलिए समय रहते हमें इसके प्रति सतर्क हो जाना चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर।

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

950 महिलाएं हैं बंगाल में प्रत्येक एक हजार पुरुषों की आबादी की तुलना में, वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार। हालांकि वर्ष 2001 में यह आंकड़ा 934 ही था, जो यह दर्शाता है कि आनुपातिक रूप से यहां महिलाओं की संख्या बढ़ी है।

आजकल

कूटनीति में मिठास घोलने का प्रयास

बीते सप्ताह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इटली की यात्रा पर थे। वहां की प्रधानमंत्री जार्जिया मेलोनी से मुलाकात के दौरान उन्होंने जो वस्तु भेंट में दी, वह चर्चा का विषय बन चुकी है। वस्तुत: टाफी के माध्यम से मोदी ने मेलोनी के साथ ही समूचे विश्व को रिश्तों में मिठास घोलने का एक अनूठा संदेश भी दिया। कहा जा सकता है कि 'मेलोडी डिप्लोमेसी' केवल एक टाफी की कहानी नहीं है, यह उस नए दौर की कहानी है, जहां इंटरनेट संस्कृति और साफ्ट पावर मिलकर वैश्विक राजनीति का नया व्याकरण लिख रहे हैं

डा. संजय वर्मा
एसोसिएट प्रोफेसर, बेनेट यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा

पिछले सप्ताह इटली यात्रा के दौरान वहां की प्रधानमंत्री जार्जिया मेलोनी से मिलते भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। फाइल

राजनय या कहें कि कूटनीति, इसकी दुनिया आमतौर पर बेहद गंभीर मानी जाती है। इसमें शब्दों का चयन तौला जाता है, मुस्कानें रणनीति का हिस्सा होती हैं और हाथ मिलाने, आंखें चुराने और किसी देश के दौरे पर गए शीर्ष नेता को मिले तोहफों को एयरपोर्ट की डस्टबिन में फेंक दिए जाने के पीछे भी भू-राजनीतिक संकेत छिपे होते हैं। लेकिन कभी-कभी अंतरराष्ट्रीय संबंधों की यही कठोर दुनिया अचानक बेहद मानवीय और भावनात्मक हो उठती है। तब कोई क्रिकेट मैच देशों के बीच पुल बन जाता है, कोई फिल्म सांस्कृतिक दूरी कम कर देती है।

हाल ही में, इटली की प्रधानमंत्री जार्जिया मेलोनी को भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 'मेलोडी' टाफी भेंट किए जाने की घटना पहली नजर में हल्की-फुल्की और मनोरंजक लग सकती है। लेकिन यह घटना आधुनिक कूटनीति के एक गहरे बदलाव की ओर संकेत करती है। यह बताती है कि 21वीं सदी में केवल सैन्य शक्ति व आर्थिक ताकत ही नहीं, संस्कृति, स्मृतियां, भावनाएं व लोकप्रिय उपभोक्ता प्रतीक भी संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं।

जब मीम बन गया कूटनीतिक प्रतीक : दरअसल, 'मेलोडी' शब्द अरसा पहले इंटरनेट मीडिया पर एक मीम के रूप में उभरा था। तब भारत और इटली के प्रधानमंत्रियों की सार्वजनिक मुलाकातों और तस्वीरों के बाद इंटरनेट उपयोगकर्ताओं (यूजर्स) ने दोनों नेताओं के नामों को मिलाकर यह शब्द गढ़ा था। यह मीम इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ था। आमतौर पर राजनीतिक मीम कुछ दिनों में गायब हो जाते हैं, लेकिन 'मेलोडी' इसलिए जीवित रहा, क्योंकि दोनों नेताओं ने खुद इसे स्वीकारा और आगे बढ़ाया था। बीते सप्ताह ही रोम में हुई मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मेलोनी को 'मेलोडी' टाफी का एक पैकेट भेंट किया। यह क्षण इंटरनेट संस्कृति और औपचारिक कूटनीति के विलय का प्रतीक बन गया। अचानक एक सस्ती भारतीय टाफी वैश्विक मीडिया की सुर्खियों में आ गई।

ट्रैक-2 डिप्लोमेसी : अंतरराष्ट्रीय संबंधों में 'ट्रैक-2 डिप्लोमेसी' एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। ट्रैक-1 डिप्लोमेसी वह होती है जिसमें सरकारें, राजनयिक और औपचारिक वार्ताएं शामिल होती हैं। इसके विपरीत ट्रैक-2 डिप्लोमेसी में संवाद का माध्यम संस्कृति, खेल, शिक्षा, साहित्य, धार्मिक संपर्क, व्यावसायिक रिश्ते या जन-भावनाएं बनती हैं। इसका उद्देश्य किसी विवाद का तत्काल समाधान निकालना नहीं होता, बल्कि विश्वास पैदा करना, तनाव कम करना और संवाद के लिए सकारात्मक माहौल तैयार करना होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच 'क्रिकेट डिप्लोमेसी' इसका उदाहरण रही है।

इसी तरह अमेरिका और चीन के बीच 1971 की 'पिंग-पोंग डिप्लोमेसी' ने दोनों देशों के संबंधों में ऐतिहासिक बदलाव की शुरुआत की थी। टेबल टेनिस खिलाड़ियों के आदान-प्रदान ने वह रास्ता खोला, जो आगे चलकर अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की चीन यात्रा तक पहुंचा था। दक्षिण और उत्तर कोरिया के बीच ओलिंपिक खेलों में संयुक्त मार्च भी इसी ट्रैक-2 डिप्लोमेसी का हिस्सा था। यह ऐतिहासिक अवसर 2018 में दक्षिण कोरिया में आयोजित शीतकालीन ओलिंपिक के दौरान आया था, जब दोनों देशों के एथलीटों ने 'यूनाइटेड कोरिया' के एक साझा झंडे के नीचे मार्च किया था।

सीमाएं भी हैं ट्रैक-2 की : यह मान लेना गलत होगा कि आम और टाफियों का आदान-प्रदान, रेल-बस सेवाओं की शुरुआत और क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन भू-राजनीतिक समस्याओं का समाधान दे सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच आमों का आदान-प्रदान हुआ, समझौता एक्सप्रेस और सदा-ए-सरहद जैसी रेल और बस सेवाएं चलीं, लेकिन सीमा विवाद और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर लगाम नहीं लगी। भारत और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक निकटता है, लेकिन तीस्ता जल विवाद आज भी अनसुलझा है। यानी ट्रैक-2 डिप्लोमेसी रिश्तों को सहज बना सकती है, लेकिन जटिल राजनीतिक समस्याओं का विकल्प नहीं हो सकती। कई बार यह 'टोकनिज्म' भी बन जाती है यानी केवल प्रतीकात्मकता। यदि सांस्कृतिक इशारों के साथ ठोस नीतिगत कदम न हों, तो लोग उन्हें केवल दिखावा मानने लगते हैं। साफ्ट पावर की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके पीछे वास्तविक राजनीतिक इच्छाशक्ति कितनी है।

इसकी जरूरत क्यों बढ़ रही : आज दुनिया अभूतपूर्व ध्रुवीकरण के दौर से गुजर रही है। रूस-यूक्रेन युद्ध, अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा, पश्चिम एशिया का संकट और बढ़ती आर्थिक असमानताएं वैश्विक तनाव बढ़ा रही हैं। ऐसे समय में केवल कठोर शक्ति पर आधारित कूटनीति पर्याप्त नहीं है। देशों को मानवीय जुड़ाव की भी आवश्यकता है। यही वजह है कि सांस्कृतिक कूटनीति का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। लोग अब केवल सरकारों से नहीं, बल्कि संस्कृतियों से जुड़ते हैं। भारत के लिए यह अवसर भी है और चुनौती भी। अवसर इसलिए, क्योंकि भारत के पास विशाल सांस्कृतिक पूंजी है। चुनौती इसलिए, क्योंकि साफ्ट पावर तभी प्रभावी होती है जब घरेलू स्तर पर भी लोकतांत्रिक मूल्यों और सांस्कृतिक आत्मविश्वास की छवि मजबूत हो।

भारत क्या सीख सकता है : भारत यदि अपनी साफ्ट पावर को रणनीतिक रूप से विकसित करे तो वह वैश्विक राजनीति में अनोखी स्थिति बना सकता है। भारतीय भोजन, योग, आयुर्वेद, बालीवुड, संगीत, क्रिकेट, डिजिटल कंटेंट और स्थानीय ब्रांड ये सब अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रभाव के उपकरण बन सकते हैं। 'मेलोडी डिप्लोमेसी' यह संकेत देती है कि कभी-कभी सबसे सरल प्रतीक सबसे गहरा असर छोड़ते हैं। भविष्य में शायद हम चाय डिप्लोमेसी, मसाला डिप्लोमेसी, स्ट्रीट फूड डिप्लोमेसी या डिजिटल मीम डिप्लोमेसी जैसे नए शब्द सुनें। क्योंकि आधुनिक कूटनीति अब केवल संधियों से नहीं, बल्कि साझा सांस्कृतिक अनुभवों से भी संचालित होगी।

दुनिया में शायद ही कोई ऐसा विवाद हो जो केवल टाफियों या आमों से खत्म हो जाए। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि संवाद की शुरुआत अक्सर छोटे और मानवीय इशारों से होती है। मेलोडी की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि कूटनीति केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि संबंध निर्माण की कला भी है। जब नेता जनता की भावनाओं से जुड़े प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, तो वे केवल संदेश नहीं भेजते- वे विश्वास का वातावरण बनाते हैं। और शायद इसी कारण एक रुपये की टाफी दुनिया को यह सिखा रही है कि कभी-कभी सबसे प्रभावशाली कूटनीति वही होती है, जो सबसे सरल दिखाई देती है।

मैंगो डिप्लोमेसी के जरिये संवाद का सिलसिला

ट्रैक-2 डिप्लोमेसी का एक और रूपक मैंगो डिप्लोमेसी है। दक्षिण एशिया में 'मैंगो डिप्लोमेसी' लंबे समय से साफ्ट पावर का दिलचस्प माध्यम रही है। आम केवल फल नहीं, बल्कि इस क्षेत्र की सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा है। भारतीय उपमहाद्वीप में आम आतिथ्य, प्रेम, समृद्धि और अपनत्व का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि आमों का आदान-प्रदान अक्सर राजनीतिक संदेश भी बन जाता है। खास तौर से भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने वर्षों तक आमों का इस्तेमाल रिश्तों में मिठास लाने के लिए किया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने 2008 में भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आम भेजे थे। यह उस दौर की बात है जब दोनों देशों के बीच तनाव था, लेकिन बैक-चैनल संवाद जारी रखने की कोशिश हो रही थी।

इसी प्रकार पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी जुलाई 2015 को भारत के प्रधानमंत्री मोदी को आम भेजे थे। यह तोहफा एलओसी पर तनाव की घटनाओं के बीच भेजा गया था। बांग्लादेश ने 2023 और 2025 में भारत को 'हरिभंगा' आम भेजकर संबंधों को सहज बनाने का प्रयास किया। यह उस समय हुआ जब तीस्ता जल विवाद और वीजा संबंधी तनाव मौजूद थे। इन घटनाओं का महत्व इस बात में नहीं था कि उनसे तुरंत कोई बड़ा समझौता हो गया। महत्व इस बात का था कि संवाद के दरवाजे खुले रहे। मैंगो डिप्लोमेसी का सबसे रोचक उदाहरण 1968 में देखने को मिला। पाकिस्तान ने चीन के नेता माओ जेडोंग को आम भेंट किए। चीन उस समय सांस्कृतिक क्रांति के दौर से गुजर रहा था। आम चीनियों के लिए बेहद दुर्लभ फल था। नतीजा यह हुआ कि उन आमों को लगभग पवित्र वस्तु की तरह देखा जाने लगा। कई जगहों पर उनके मोम के प्रतिरूप बनाए गए और उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया। यह घटना बताती है कि सांस्कृतिक प्रतीकों की शक्ति कई बार राजनीतिक दस्तावेजों से भी अधिक प्रभावशाली हो सकती है।

एक समय था जब विदेश नीति और कूटनीति केवल विदेश मंत्रालयों और राजनयिकों तक सीमित रहती थी। लेकिन डिजिटल युग ने इस ढांचे को बदल दिया है। आज अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर इंटरनेट मीडिया का प्रभाव है। जनता भी इसमें सक्रिय भागीदार बन चुकी है। किसी नेता की एक तस्वीर, एक मीम या एक सांस्कृतिक प्रतीक लाखों लोगों तक कुछ ही मिनटों में पहुंच जाता है। आधुनिक कूटनीति औपचारिक बैठकों तक सीमित नहीं है। अब यह नैरेटिव की लड़ाई भी है। कौन-सा देश दुनिया के सामने अधिक मानवीय, दोस्ताना और सांस्कृतिक रूप से आकर्षक दिखता है या फिर दौरे पर गए शीर्ष नेता और उसके प्रतिनिधिमंडल को मिले तोहफों के प्रति अनिच्छा, सतर्कता और एक किस्म की हिकारत दिखाई जाती है- यह भी वैश्विक प्रभाव का हिस्सा बन चुका है। (डा. संजय वर्मा)

खरी-खरी

तेल की कहानी

सूर्यदीप कुशवाहा

वाह रे तेल! तुम्हारी महिमा अपरंपार है। कुछ साल पहले तक तुम सिर्फ गाड़ियों का पेट भरते थे, लेकिन आज तुमने इंसानों का कचूमर निकाल दिया है। पेट्रोल पंप पर जाना अब किसी पेट्रोल भराने जैसा नहीं, बल्कि किसी महंगे फाइवस्टार होटल में जाने जैसा महसूस होता है। महंगाई ने आम आदमी को इतना संस्कारी बना दिया है कि अब लोग ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी बंद करना नहीं भूलते। लाल बत्ती होते ही लोग ऐसे फुर्ती से पैर जमीन पर टिकाते हैं और इंजन बंद करते हैं, मानो देश की पूरी अर्थव्यवस्था को बचाने की जिम्मेदारी अकेले उन्हीं के कंधों पर हो। लोग अब सड़कों पर बेमतलब के लिए नहीं जाते, बल्कि मतलब से जाते हैं। लोग इस बात पर रिसर्च करके चलते हैं कि किस रूट पर कम रेड लाइट और कम ट्रैफिक मिलेगा, ताकि तेल बचाया जा सके।

नासा से निवेदन है कि वे चांद और मंगल पर पानी खोजने का काम थोड़ी देर के लिए रोक दें। कृपया कोई ऐसा फार्मूला खोजें जिससे गाड़ियां पानी या हवा या चलने लगें। आज का युवा बाइक स्टार्ट करने से पहले दो बार मंत्र पढ़ता है कि कहीं रास्ते में तेल खत्म न हो जाए।

इस तेल ने हमारी सेहत भी सुधार दी है। डाक्टर वर्षों से कह रहे थे कि वाक करो, सेहत बनेगी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अब तेल की कीमतों ने सबको पैदल चलने और साइकिल चलाने पर मजबूर कर दिया है। इसे कहते हैं, आपदा को अवसर में बदलना। आम आदमी अब अपनी गाड़ी को गैराज में ऐसे सजा कर रखता है जैसे कोई कीमती शो-पीस हो। रविवार को उसे साफ किया जाता है, अगरबत्ती दिखाई जाती है और फिर चुपचाप पैदल ही बाजार सब्जी लेने निकल जाता है।

अंत में यही कहा जा सकता है कि तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और आम आदमी जमीन में धंस रहा है। बहुत जल्द अधिकांश लोग सड़क पर पैदल चलते और साइकिल की सवारी करते हुए नजर आएंगे। फिर लोग अगली पीढ़ी को तेल के किस्से सुनाएंगे। तेल की कहानियां स्कूली पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाई जा सकती हैं। यह कोई बहुत दूर की बात नहीं है। जिस तरह से हम तेल फूंक रहे हैं, उसका यही नतीजा होगा।

पोस्ट

विरोध के लिए लोग काकरोच के प्रतीक के रूप में अपनी राजनीतिक प्रतिक्रिया देने लगे हैं। हमें इस प्रतिक्रिया को भांपना होगा।
तवलीन सिंह@tavleen_singh

देश में पेपर लीक की समस्या के दौर में यूपीएससी द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षाओं का शुचितापूर्ण संचालन देश की अन्य संस्थाओं के लिए एक आदर्श केस स्टडी होना चाहिए।
शिवम शर्मा@shiva_m2912

कहा जा रहा है कि यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर बहुत कठिन आया। कोई पेपर मुश्किल है, तो वह सबके लिए कठिन है। मेरी दृष्टि में अब यूपीएससी को ऐसे अभ्यर्थी चाहिए जो मानसिक रूप से दृढ़, भावनात्मक रूप से संतुलित और किसी भी प्रकार की परिस्थिति में बेहतर करने की क्षमताएं रखते हों।
अवनीश शरण@AwanishSharan

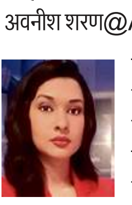

त्विषा शर्मा की मौत पर चौतरफा चर्चा जारी है। चर्चा के इस क्रम में सालिसिटर जनरल की कही गई बात दिल को छू गई- तलाकशुदा बेटी, मृत बेटी से अच्छी है।
मीनाक्षी जोशी@IMinakshiJoshi

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या दिल्ली जिमखाना क्लब की जमीन खाली कराने का केंद्र सरकार का फैसला सही है?

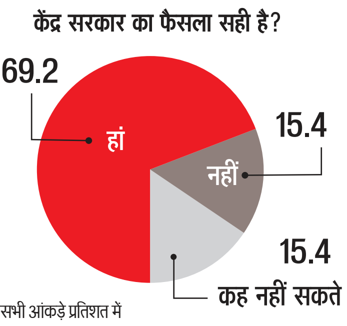

सभी आंकड़े प्रतिशत में

आज का सवाल

क्या रूबियो के दौरे से अमेरिका के साथ व्यापार समझौता होने की उम्मीद बढ़ी है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है

जनपथ

छिपकलियां कुछ पालिए खाएंगी 'काक्रोच',
घर यदि रखना ठीक है साफ कीजिए रोज।
साफ कीजिए रोज लगाकर झाड़ू-पोछा,
मेढक देते ज्ञान आजकल डाल अंगौछा!
हो जाएंगी साफ देश की सारी गलियां,
'काक्रोच' उदरस्थ करेंगी जब छिपकलियां!!
-ओम प्रकाश तिवारी

बंगाल डायरी

शक्ति साधना के आंगन में यह कैसा 'अंधेरा'

जयकृष्ण वाजपेयी
राज्य ब्यूरो प्रमुख, बंगाल

यह वह बंगाल है जहां भोर की शुरुआत 'चंडी पाठ' की गूंज से होती है। यह वह समाज है जहां परंपरा से लेकर समकालीन विमर्श तक, बेटी को सिर्फ संतान नहीं, बल्कि साक्षात 'मां' कहकर पुकारने की आत्मीय सांस्कृतिक परिपाटी रही है। राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, कविगुरु रवींद्र नाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद की इस धरती ने देश को महिलाओं के अधिकारों, उनकी शिक्षा और सशक्तीकरण का पहला आधुनिक पाठ पढ़ाया था। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के आंकड़े भी गवाही देते रहे हैं कि उत्तर या मध्य भारत के कई राज्यों की तुलना में बंगाल का लिंगानुपात कहीं बेहतर और संतुलित रहा है। कन्या भ्रूण हत्या या नवजात बच्चियों की हत्या जैसी बर्बर सामाजिक कुरीतियां इस समाज के स्वभाव का हिस्सा कभी नहीं रहीं। लेकिन हाल ही में हुगली जिले के पांडुआ से आई एक भयावह खबर ने बंगाल के इसी प्रबुद्ध और संवेदनशील होने के दावों को कठघरे में खड़ा कर दिया है।

हुगली के पांडुआ के मानुसमारी गांव में चौथी बार बेटी पैदा होने पर माता-पिता ने मिलकर अपनी ही नवजात बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी और साक्ष्य छुपाने के लिए शव को पास के नाले में फेंक दिया। समाज की सजगता देखिए कि एक पड़ोसी आगे आया, शिकायत दर्ज हुई, और पुलिस ने वैज्ञानिक तत्परता दिखाते हुए डीएनए जांच के जरिये उस सच को उजागर किया जिसे वे निर्दयी माता-पिता झुठला रहे थे। अंततः चुंचुड़ा की अदालत ने भारतीय न्याय संहिता के तहत इस कृत्य को जघन्यतम मानते हुए माता-पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई। कानून ने अपना कर्तव्य निभाया, अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया, लेकिन इस अदालती फैसले के समानांतर बंगाल के प्रबुद्ध समाज के सामने एक ऐसा यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया है जिसका उत्तर ढूंढना बेहद जरूरी हो गया है। आखिर मां दुर्गा और मां काली की अनन्य उपासक इस भूमि पर, यह कैसा अंधियारा पसर रहा है?

प्रतीकात्मक

यह कोई अकेली या अलहदा घटना नहीं है। अगर पिछले एक दशक के परिदृश्य को खंगाला जाए, तो मालदा, जलपाईगुड़ी और दिनाजपुर जैसे सुदूर ग्रामीण इलाकों से लेकर मुख्यधारा के शहरी परिवेश के छोरों तक ऐसी कई छिटपुट, लेकिन बेहद चिंताजनक घटनाएं सामने आई हैं। कहीं अंधविश्वास के नाम पर नवजात बच्चियों को लावारिस छोड़ दिया गया, तो कहीं बेटों की चाहत में माताओं को घोर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। जो सामाजिक विद्रूप उत्तर भारत के कुछ खास अंचलों की पहचान माना जाता था, वह अब चुपके से बंगाल के शांत और प्रगतिशील समाज में अपनी पैठ बना रहा है।

इस गहरे संकट की पड़ताल करने पर कुछ बेहद कड़वी सच्चाइयां सामने आती हैं। आधुनिकता और शिक्षा के ऊंचे दावों के बीच एक ऐसी संकीर्ण पितृसत्तात्मक सोच समाज के भीतर ही भीतर पनप रही है, जो वैश्वीकरण के दौर में भी और अधिक रूढ़िवादी हो गई है। उपभोक्तावादी संस्कृति ने पारंपरिक मूल्यों को इस कदर चोट पहुंचाई है कि अब मानवीय जीवन की कीमत भी आर्थिक नफे-नुकसान के तराजू पर तौली जाने लगी है। ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में आज भी यह भ्रामक और प्रतिगामी धारणा मजबूत हो रही है कि बेटा ही बुढ़ापे का एकमात्र सहारा और वंश का रक्षक है, जबकि बेटी एक आर्थिक दायित्व या बोझ है। जब यही संकीर्णता अंधविश्वास के साथ मिलती है, तो हुगली जैसी वीभत्स घटनाएं आकार लेती हैं।

एक समाज के तौर पर बंगाल के लिए यह आत्ममंथन का समय है। हम अपनी शानदार विरासत और उच्च लिंगानुपात के गौरव गान के पीछे इस उभरती हुई कड़वी हकीकत को और ज्यादा दिनों तक छुपाकर नहीं रख सकते। राष्ट्रीय स्तर पर 'बेटी बचाओ' जैसे नारे और प्रशासनिक नीतियां अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे तब तक बेअसर साबित होंगी, जब तक कि स्थानीय स्तर पर सामाजिक चेतना को पुनर्जीवित नहीं किया जाएगा। कानून अपराध होने के बाद अपराधियों को सजा तो दे सकता है, जैसा कि हुगली की अदालत ने किया, परंतु कानून उस सोच को नहीं बदल सकता जो कोख में ही एक जिंदगी का फैसला उसकी लैंगिक पहचान के आधार पर कर देती है।

इस सामाजिक बुराई पर कड़ा प्रहार करने के लिए केवल कानूनी कड़ाई काफी नहीं है, बल्कि एक व्यापक सांस्कृतिक और सामाजिक आंदोलन की आवश्यकता है। समाज के बुद्धिजीवियों, स्थानीय क्लबों, नागरिक समितियों और धार्मिक-सांस्कृतिक संस्थाओं को आगे आना होगा, ताकि इस संकीर्ण मानसिकता के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा तैयार किया जा सके। शिक्षा व्यवस्था में न केवल साक्षरता, बल्कि लैंगिक संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता देनी होगी। जब तक 'बेटी' को बोझ मानने वाले सोच पर हर मोर्चे से तीखा वार नहीं होगा, तब तक हम अपनी बेटियों को सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन की गारंटी नहीं दे पाएंगे। हुगली की यह घटना बंगाल के सामूहिक विवेक पर एक गहरा दाग है। समय रहते इस दाग को धोने और अपनी बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समाज को जागना ही होगा, ताकि फिर किसी मासूम को इस धरती पर जन्म लेते ही अपनी जान न गंवानी पड़े।

मंथन

वैश्विक प्रभावों की भू-राजनीति

पिछली सदी के अंतिम दौर में तेजी से बढ़ा वैश्वीकरण अभियान अलग राह पकड़ चुका है। कुछ वर्षों से वैश्विक समस्याओं के उभरने से एक अलग तरह की भू-राजनीति उभरी है

रवि दास बिश्नोई
वरिष्ठ अध्येता, इंडो पैसिफिक डोमेन

लगभग पिछले तीन दशकों तक दुनिया इस भ्रम में जीती रही कि परस्पर वैश्विक जुड़ाव ने भूगोल को पराजित कर दिया है। अर्थशास्त्रियों ने सीमाओं को आर्थिक रूप से अप्रासंगिक घोषित कर दिया, तकनीकी विशेषज्ञों ने भौगोलिक दूरी के अंत पर व्याख्यान भी दिए और राजनीतिक नेतृत्व ने परस्पर जुड़े बाजारों को स्थिर वैश्विक व्यवस्था की नींव के रूप में प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। समय के साथ आपूर्ति श्रृंखलाएं महाद्वीपों तक फैल गईं और आर्थिक एकीकरण को भू-राजनीतिक संघर्षों का विकल्प माना जाने लगा। किंतु इसी वर्ष के आरंभ में ईरान संघर्ष ने इस आत्मविश्वास को अत्यंत तीव्रता से तोड़ दिया।

वस्तुतः आज शक्ति तेजी से उन राज्यों के पास केंद्रित हो रही है जो प्रवाहों को नियंत्रित करने में सक्षम हैं। पहले साम्राज्य क्षेत्रों को नियंत्रित करते थे। औद्योगिक युग में शक्तियां उत्पादन पर नियंत्रण रखती थीं। लेकिन आज भू-राजनीतिक प्रभाव उस क्षमता से निर्धारित हो रहा है जिसके माध्यम से कोई राष्ट्र तेल प्रवाह, समुद्री व्यापार, डाटा प्रवाह, सेमीकंडक्टर आपूर्ति, वित्तीय लेनदेन और लाजिस्टिक नेटवर्क को प्रभावित कर सकता हो।

इसी संदर्भ में होर्मुज समुद्री मार्ग पर ईरान की रणनीतिक पकड़ अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए एक गंभीर भौगोलिक चुनौती बन गई। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था की परिसंचरण प्रणाली व्यापक रूप से प्रभावित हुई है। इस तरह यह सैन्य टकराव से अधिक वैश्विक प्रवाहों की भू-राजनीति का संघर्ष बन गया। यही कारण है कि ईरान संघर्ष के प्रभाव युद्धक्षेत्र से कहीं आगे तक दिखाई दे रहे हैं। संघर्ष से भौगोलिक रूप से दूर स्थित देशों ने भी आर्थिक दबाव, ऊर्जा असुरक्षा और रणनीतिक अनिश्चितता का अनुभव किया। भारत इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है।

इस संघर्ष ने शीत युद्ध के बाद की व्यवस्था की संस्थागत कल्पना की कमजोरी को भी उजागर किया है। सोवियत संघ के पतन के बाद यह विश्वास पैदा हुआ था कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, कानूनी ढांचे और बहुपक्षीय व्यवस्थाएं धीरे-धीरे भू-राजनीतिक तनावों को नियंत्रित कर लेंगी। संयुक्त राष्ट्र, नाटो गठबंधन, वैश्विक व्यापार संस्थाएं और कूटनीतिक नियम संकट प्रबंधन के स्थायी साधन माने गए। लेकिन समकालीन संघर्ष यह दिखा रहे हैं कि ये संस्थाएं स्थिरता के समय तो कुछ कार्य करती हैं, परंतु तीव्र भू-राजनीतिक टकराव के समय विखंडित, चयनात्मक और रणनीतिक रूप से सीमित हो जाती हैं।

यह संस्थागत कमजोरी भारत जैसे मध्यम शक्तियों वाले देशों के लिए गहरे निहितार्थ रखती है। क्योंकि पहले राज्य अपेक्षाकृत स्थिर वैश्विक ढांचों पर भरोसा करके व्यापार, समुद्री परिवहन और कूटनीतिक संतुलन बनाए रख सकते थे। आज अनिश्चितता स्वयं संस्थागत रूप धारण कर रही है। इस तरह वैश्विक राजनीति धीरे-धीरे नियम-आधारित व्यवस्था से मोलभाव-आधारित व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, जहां परिणाम सार्वभौमिक सिद्धांतों से कम और रणनीतिक दबाव, सौदेबाजी क्षमता तथा क्षेत्रीय समीकरणों से अधिक निर्धारित होते हैं।

कई मायनों में इस वर्तमान संघर्ष ने अमेरिकी रणनीतिक शक्ति की सीमाओं को भी उजागर किया है। अमेरिका अब भी दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति है, लेकिन ईरान संकट ने दिखाया कि केवल सैन्य श्रेष्ठता अब भू-राजनीतिक नियंत्रण की गारंटी नहीं देती है। ईरान ने सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी भौगोलिक स्थिति, मिसाइल क्षमता और समुद्री अवरोधक रणनीति का उपयोग करके यह संकेत दिया कि आधुनिक युद्ध केवल तकनीकी श्रेष्ठता से नहीं जीते जाते हैं।

प्रतीकात्मक

यही कारण है कि अमेरिका के लिए इस युद्ध को लंबे समय तक विस्तार देना रणनीतिक रूप से भी उचित नहीं था। पश्चिम एशिया की अत्यधिक गर्म जलवायु, बदलते मौसमी पैटर्न, लंबी समुद्री आपूर्ति श्रृंखलाएं और मानसूनी प्रभावों से जुड़े समुद्री जोखिम अमेरिकी सैन्य अभियानों की लागत और जटिलता को लगातार बढ़ा रहे थे। आधुनिक सैन्य शक्ति हथियारों के अलावा ईंधन, लाजिस्टिक स्थिरता, जलवायु अनुकूलन और निरंतर आपूर्ति क्षमता पर भी निर्भर करती है। इस संघर्ष ने दिखाया कि प्रकृति और भूगोल अब भी युद्ध की दिशा निर्धारित करने की क्षमता रखते हैं।

अंततः ईरान संकट मानवता को उस सत्य की याद दिलाता है जिसे वह दशकों तक भूलने का प्रयास करती रही कि भूगोल कभी पराजित नहीं हुआ था। वह केवल स्थिर व्यापार मार्गों और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं की अस्थायी सुविधा के नीचे छिप गया था। इतिहास ने अब मानचित्र को पुनः खोल दिया है। और आधुनिक सभ्यता की विडंबना यह है कि तेल टैंकर अब भी संकीर्ण समुद्री मार्गों से गुजरते हैं। अर्थव्यवस्थाएं भौतिक गलियारों पर निर्भर हैं और भू-राजनीतिक वास्तविकताएं अब भी सीमाहीन दुनिया जैसे फैशनेबल सिद्धांतों से प्रभावित होने से इन्कार करती हैं।

2033 तक 45 अरब डालर होगा डाटा सेंटर का राजस्व

नई दिल्ली : कंसल्टिंग फर्म केपीएमजी ने सोमवार को एक रिपोर्ट में कहा कि वर्ष 2033 तक भारत के डाटा सेंटर उद्योग तेजी से विस्तार के दौर में प्रवेश कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2033 तक पूरे डाटा सेंटर उद्योग का राजस्व 45.69 अरब डालर तक पहुंचने का अनुमान है। वर्ष 2024 में डाटा सेंटर बाजार का आकार 58.86 करोड़ डालर रहा है, जो 2030 तक 3.55 अरब डालर पर पहुंच जाएगा। (आइएएनएस)

हम पूरे ग्रामीण भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए किफायती लोन की पहुंच बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ मिलकर एक को-लेंडिंग माडल पर काम कर रहे हैं।
– मनोज मित्तल, चेयरमैन, सिडबी

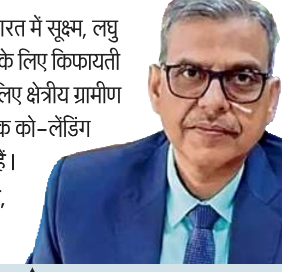

सेंसेक्स	76,488.96	▲ 1,073.61
निफ्टी	24,031.70	▲ 312.40
सोना (प्रति दस ग्राम)	₹ 1,65,200	▲ ₹ 300
चांदी (प्रति किलो ग्राम)	₹ 2,71,000	बदलाव नहीं
डालर	₹ 95.26	▼ ₹ 0.34
क्रूड (प्रति बैरल)	$ 97.82	

एक नजर में

भारत-दक्षिण कोरिया के बीच व्यापार वार्ता शुरू

नई दिल्ली : व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) को और बेहतर बनाने के लिए सोमवार को भारत और दक्षिण कोरिया के बीच बातचीत का अगला दौर शुरू हो गया। एक अधिकारी ने बताया कि 27 मई तक चलने वाली यह बातचीत काफी अहम है क्योंकि भारत ने दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार घाटे को लेकर गंभीर चिंताएं जताई हैं। दोनों देशों के बीच सीईपीए जनवरी 2010 में लागू हुआ था। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का दक्षिण कोरिया को निर्यात 3.31 प्रतिशत बढ़कर छह अरब डालर और दक्षिण कोरिया से आयात 1.38 प्रतिशत बढ़कर 21.35 अरब डालर रहा है। (प्रेट्र)

सेंट्रल बैंक आफ इंडिया में एलआइसी का हिस्सा बढ़ा

नई दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक आफ इंडिया में जीवन बीमा कंपनी एलआइसी की हिस्सेदारी बढ़कर छह प्रतिशत से ज्यादा हो गई है, जो पहले 3.16 प्रतिशत थी। सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ने रेग्युलेटरी फाइलिंग में बताया कि एलआइसी ने 22 मई को उसके 26.26 करोड़ शेयर खरीदे हैं जो 2.901 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर है। इस खरीदारी के बाद बैंक में एलआइसी की हिस्सेदारी बढ़कर 6.06 प्रतिशत पर पहुंच गई है। (प्रेट्र)

शेयर बिक्री के लिए सरकार ने चुनीं चार कंपनियां

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली दो तिमाही के दौरान शेयर बिक्री के लिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की चार कंपनियों का चयन किया है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इसमें कोल इंडिया लिमिटेड, एलआइसी, इंडियन ओवरसीज बैंक और भारतीय रेलवे वित्त निगम हैं। कोल इंडिया में सरकार दो प्रतिशत तक हिस्सेदारी कम कर सकती है। वहीं, एलआइसी के शेयरों की बिक्री के लिए आफर फार सेल जुलाई-सितंबर में लाया जा सकता है। (आइएएनएस)

कच्चे तेल में नरमी से सेंसेक्स 1,074 अंक चढ़ा

अमेरिका और ईरान बातचीत को लेकर बेहतर होते माहौल ने भी शेयर बाजार को दिया सहारा

मुंबई, प्रेट्र : कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट और अमेरिका-ईरान बातचीत को लेकर बेहतर होते माहौल के बीच सोमवार को सेंसेक्स और निफ्टी में एक प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 1,073.61 अंक या 1.42 प्रतिशत बढ़कर 76,488.96 पर बंद हुआ। दिन के दौरान, यह 1,143.72 अंक बढ़कर 76,559.07 पर पहुंच गया था। वहीं एनएसई निफ्टी 312.40 अंक या 1.32 प्रतिशत बढ़कर 24,031.70 पर बंद हुआ।

कारोबारियों ने कहा कि डालर के मुकाबले रुपये में तेजी और बैंकिंग व वित्तीय शेयरों में खरीदारी से धारणा को मजबूती मिली। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से बजाज फाइनेंस, लार्सन एंड टुब्रो, एचडीएफसी बैंक, इटरनल, बजाज फिनसर्व और कोटक महिंद्रा बैंक सबसे ज़्यादा फायदे में रहे। इसके उलट, इंफोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़, सन फार्मा और हिंदुस्तान यूनिलीवर पिछड़ गए। ग्लोबल तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 5.52 प्रतिशत गिरकर 97.82 डालर प्रति बैरल पर आ गया। सेंसेक्स बीते सप्ताह शुक्रवार को 231.99 अंक बढ़कर 75,415.35 अंक, जबकि निफ्टी 64.60 अंक की तेजी के साथ 23,719.30 अंक पर रहा था। बीएसई स्मालकैप में 1.18 प्रतिशत और मिडकैप सूचकांक में 0.92 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

- रुपये में तेजी और बैंकिंग व वित्तीय शेयरों में खरीदारी से धारणा को मजबूती मिली
- वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 5.52 प्रतिशत गिरकर 97.82 डालर प्रति बैरल पर आया

सेक्टरवार तेजी (%में)

पीएसयू बैंक	2.96
बैंकेक्स	2.27
शीर्ष 10 बैंक	2.19
प्राइवेट बैंक इंडेक्स	2.07
फाइनेंशियल सर्विसेज	2.06
टेलीकम्युनिकेशन	1.89
आटो	1.76

76,488.96 पर बंद हुआ बीएसई का मानक सूचकांक सेंसेक्स

312 अंक चढ़कर 24,031 पर बंद हुआ एनएसई का निफ्टी

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और अमेरिका-ईरान समझौते को लेकर बढ़ती उम्मीदों के चलते बाजार में तेजी रही। होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने की दिशा में प्रगति की खबरों से वैश्विक धारणा में सुधार हुआ है। हालांकि, घटनाक्रम में लगातार बदलाव को देखते हुए स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है।
–**विनोद नायर**, रिसर्च हेड, जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड

सोने में 300 रुपये की तेजी, चांदी स्थिर रही

नई दिल्ली, प्रेट्र : डालर में कमजोरी और अमेरिका व ईरान के बीच समझौते की उम्मीद से सोमवार को सोना 300 रुपये बढ़कर 1,65,200 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। हालांकि, चांदी 2.71 लाख रुपये प्रति किलो पर स्थिर रही।

कच्चे तेल में गिरावट से तेल कंपनियों के शेयरों में तेजी

नई दिल्ली, प्रेट्र : पेट्रोल-डीजल की कीमतों में नई वृद्धि के बाद सोमवार को तेल विपणन कंपनियों के शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। बीएसई पर भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के शेयर 4.30 प्रतिशत बढ़कर 308.25 पर बंद हुए। दिन के दौरान, स्टाक 4.55 प्रतिशत बढ़कर 309 के इंट्राडे हाई पर पहुंच गए थे। वहीं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के शेयर 3.52 प्रतिशत बढ़कर 403.40 पर बंद हुआ। दिन के दौरान, यह 5.86 प्रतिशत बढ़कर 412.55 के दिन के हाई पर पहुंच गया। इंडियन आयल कारपोरेशन के शेयर 3.15 प्रतिशत बढ़कर 143.90 पर पहुंच गया।

डालर के मुकाबले रुपये में लगातार तीसरे दिन मजबूती

मुंबई, प्रेट्र : अमेरिका एवं ईरान के बीच शांति समझौते की बढ़ती उम्मीदों के बीच सोमवार को रुपया 34 पैसे मजबूत होकर 95.26 प्रति डालर पर बंद हुआ। यह रुपये में तेजी का लगातार तीसरा सत्र है। पिछले तीन कारोबारी सत्रों में रुपया डालर के मुकाबले 160 पैसे मजबूत हुआ है। कारोबारियों ने कहा कि आरबीआइ गवर्नर संजय मल्होत्रा के बयान से भी रुपये को समर्थन मिला। मल्होत्रा ने कहा है कि केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में व्यवस्थित मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा।

विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 95.36 प्रति डालर के भाव पर खुला और इसने दिन में 95.12 के ऊपरी एवं 95.44 के निचले स्तर को छुआ। कारोबार के अंत में रुपया 95.26 प्रति डालर पर बंद हुआ, जो पिछले सत्र की तुलना में 34 पैसे की बढ़त है। शुक्रवार को रुपया 75 पैसे मजबूत होकर 95.60 प्रति डालर पर बंद हुआ था। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से भी बाजार को समर्थन मिला कि अमेरिका एवं ईरान ने शांति समझौते पर बातचीत लगभग पूरी कर ली है। दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डालर की मजबूती को दर्शाने वाला डालर सूचकांक 0.26 प्रतिशत गिरकर 99.98 पर आ गया।

- 34 पैसे बढ़कर 95.26 प्रति डालर पर बंद हुआ रुपया
- तीन दिनों में डालर के मुकाबले रुपये में 160 पैसे की वृद्धि

केंद्र एलटीसीजी पर निवेशकों की चिंताओं को सुनने के लिए तैयार

वित्त मंत्री ने कहा-सरकार इस मामले पर निवेशकों से फीडबैक और सुझाव लेगी, बढ़ सकती है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम

नई दिल्ली, प्रेट्र : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सरकार शेयर बाजार निवेशकों की कर प्रणाली को लेकर उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए तैयार है और इसमें लांग टर्म कैपिटल गेन (एलटीसीजी) और शार्ट टर्म कैपिटल गेन (एसटीसीजी) टैक्स से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीतारमण ने कहा कि सरकार इस मामले पर निवेशकों से सुझाव और फीडबैक लेने के लिए तैयार है।

शेयर बाजार भागीदारों की एलटीसीजी और एसटीसीजी टैक्स की समीक्षा से जुड़े मांगों के बारे में उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा, "इस खास मुद्दे पर और किसी भी मुद्दे पर हम लोगों की बात सुनने को तैयार हैं।" हालांकि, वित्त मंत्री ने कराधान प्रणाली में किसी बदलाव की बात नहीं कही है। एलटीसीजी और एसटीसीजी शेयर और दूसरी वित्तीय परिसंपत्तियों के बेचने से कमाए गए मुनाफे पर लगाए जाने वाले टैक्स हैं। सीतारमण के इस बयान को निवेशक इस बात का संकेत मान रहे हैं कि सरकार हितधारकों के साथ बातचीत करने और बाजार से जुड़े कराधान के मुद्दों पर उनकी चिंताओं पर विचार करने को तैयार हैं। वित्त मंत्री से जब घरों में बेकार पड़े सोने को वित्तीय रूप से ज्यादा लाभकारी बनाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को बढ़ाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

75 बड़े शहरों में घरों की बिक्री 16% बढ़कर 9.33 लाख करोड़ रही

नई दिल्ली, प्रेट्र : पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में देश के 75 बड़े शहरों में घरों की बिक्री मूल्य के लिहाज से 16 प्रतिशत बढ़कर 9.33 लाख करोड़ रुपये रही। हालांकि, संख्या के लिहाज से घरों की बिक्री एक प्रतिशत घटकर 7,09,793 इकाई रही है। रियल एस्टेट रेटिंग से जुड़ी कंपनी लियासेस फोरास के अनुसार, 'पिछले वित्त वर्ष में इन 75 शहरों में आवासीय संपत्तियों की नई आपूर्ति 10 प्रतिशत बढ़कर 6,20,842 यूनिट हो गई।

लियासेस फोरास ने कहा, "आर्थिक चिंताओं के बावजूद 75 से अधिक शहरों में घरों की बिक्री एक जैसी नहीं रही जबकि नए घरों की आपूर्ति साल-दर-साल लगभग 10 प्रतिशत बढ़ी है। इससे बिना बिके घर 13 प्रतिशत बढ़कर लगभग 12 लाख यूनिट हो गए और यह बढ़ती आपूर्ति जमाव को दिखाता है।

मैन्यूफैक्चरिंग बढ़ाकर आयात बिल कम करेगा भारत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि मैन्यूफैक्चरिंग बढ़ाकर आयात बिल को कम करने के लिए कई प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। कैपिटल गुड्स, केमिकल्स, इलेक्ट्रानिक्स जैसे कई उत्पादों की घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ाने को लेकर उद्यमियों के साथ लगातार बैठक हो रही है। मंत्रालय उन सभी वस्तुओं की पहचान कर रहा है, जिनकी मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ाया जा सकता है ताकि आयात को कम किया जा सके। मंत्रालय की वेबसाइट पर इस प्रकार के सभी आइटम की विस्तृत जानकारी दी जाएगी ताकि उद्यमियों को निवेश में आसानी हो। भारत कैपिटल गुड्स, मशीन टूल्स, इलेक्ट्रानिक्स, ट्रांसपोर्ट उपकरण जैसे आइटम का 250 अरब डालर से अधिक का सालाना आयात करता है। रुपये में कमजोरी को ध्यान में रखते हुए सरकार आयात बिल कम करने का प्रयास कर रही है।

पीयूष गोयल

- वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा- मंत्रालय उन सभी वस्तुओं की पहचान कर रहा है, जिनकी मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ाया जा सकता
- भारत कैपिटल गुड्स, मशीन टूल्स, इलेक्ट्रानिक्स जैसे उत्पादों का 250 अरब डालर से अधिक का आयात करता है सालाना

गोयल ने बताया कि इस साल अप्रैल की तरह ही मई के पहले तीन सप्ताह में भी निर्यात में बढ़ोतरी का रुख दिख रहा है। इस साल अप्रैल में वस्तु निर्यात में पिछले साल अप्रैल की तुलना में 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में रिकार्ड 95 अरब डालर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) आया है, जो पूर्व के वित्त वर्ष 2024-25 के मुकाबले 17 प्रतिशत अधिक है। सर्विस सेक्टर भी लगातार मजबूत हो रहा है। सभी प्रमुख विकसित देशों से व्यापार समझौते हो चुके हैं या होने वाले हैं और इससे भी निर्यात को बढ़ावा मिल रहा है।

आर्थिक बुनियाद मजबूत होने की वजह से वैश्विक संकट के इस काल में भी दुनिया निवेश के लिए भारत की ओर देख रही है। इसलिए आने वाले वर्षों में भी विदेशी निवेश में बढ़ोतरी जारी रहेगी। इससे यह पता चलता है कि पश्चिम एशिया संकट से विश्व भले दिक्कत में हो, भारत का विकास लगातार जारी है। विभिन्न वैश्विक एजेंसियों ने गत वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही (जनवरी-मार्च) में भी विकास दर सात प्रतिशत से अधिक रहने की संभावना जाहिर की है।

सरकार के फैसलों से भारत निवेश के लिए पसंदीदा जगह बना

गोयल ने बताया कि निवेश को लेकर भारत के प्रति दुनिया का आकर्षण कोई एक दिन में नहीं बना है। पिछले 12 सालों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के साथ कारोबारी नियम को सरल करने व अन्य आर्थिक फैसलों की वजह से भारत निवेश के लिए पसंदीदा जगह बन गया है। गोयल ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद किसानों को दी जाने वाली खाद की कीमत में बढ़ोतरी नहीं की गई है।

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

राष्ट्रीय फलक

टाटा संस की बोर्ड बैठक आज, घाटे में चल रही कंपनियों पर होगी चर्चा

मुंबई, प्रेट्र : टाटा संस का बोर्ड मंगलवार को बैठक करेगा और इसमें समूह की घाटे में चल रही कंपनियों पर चर्चा होगी। हालांकि, सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि बोर्ड मीटिंग में टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति पर कोई चर्चा होने की संभावना नहीं है, क्योंकि समूह के अंदर मतभेद बढ़ रहे हैं। एक सूत्र ने बताया कि घाटे में चल रहीं कंपनियां अपने कारोबार की हालत और आगे के रास्ते पर प्रेजेंटेशन दे सकती हैं। माना जा रहा है कि चंद्रशेखरन और टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने पिछले सप्ताह कंपनियों के प्रदर्शन पर चर्चा की थी। नोएल टाटा संस के बोर्ड में नामित निदेशक हैं।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 में टाटा समूह की गैर सूचीबद्ध कंपनियों को 10,905 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है और यह बढ़कर 29,000 करोड़ तक जा सकता है। टाटा संस में बढ़ते नुकसान को लेकर नोएल टाटा परेशान हैं। नोएल टाटा टाटा संस को आइपीओ के जरिये सूचीबद्ध कराने में हिचकिचा रहे हैं। अभी टाटा संस एक निवेश कंपनी है, जिसे आरबीआइ ने शीर्ष 15 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में शामिल किया है और इनका सूचीबद्ध होना जरूरी है। नोएल के बेटे नेविल टाटा पहले ही समूह से जुड़े कुछ ट्रस्ट या फाउंडेशन में शामिल हो चुके हैं।

- बोर्ड मीटिंग में टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति पर चर्चा की संभावना नहीं

एन चंद्रशेखरन। फाइल

कुकिंग आयल के लिए मानक पैकेजिंग पर विचार

नई दिल्ली, प्रेट्र : उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि वह खाना पकाने वाले तेल (कुकिंग आयल) के लिए मानक पैकेजिंग लाने की संभावना पर विचार कर रहा है। दरअसल, अभी बाजार में विभिन्न मात्रा के कुकिंग आयल बिक रहे हैं। 20 मई को बड़ी एडिबल आयल इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के एक बैठक हुई। एसोसिएशन ने बाजार में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के पैकेज साइज की बढ़ती संख्या और इसके चलते ग्राहकों को कीमतों की तुलना में होने वाली दिक्कतों के बारे में चिंता जताई।

बैठक के दौरान, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने बताया कि खाने के तेल अभी कई पैकेज मात्रा (650ग्राम, 700ग्राम, 810ग्राम, 850ग्राम और 870ग्राम) में बेचे जाते हैं। प्रतिनिधियों ने बताया कि अलग-अलग मात्रा वाले एक जैसे दिखने वाले पैक कीमतों की तुलना करने और सोच-समझकर चुनाव करने में गुमराह कर सकते हैं। बयान में कहा गया, 'बैठक के दौरान यह स्पष्ट किया गया कि अगर इस तरह की कोई जरूरत लागू की जाती है तो यह देश में बने और आयात किए गए खाने के तेल दोनों पर लागू होगी।' उपभोक्ता मामलों के सचिव ने कहा कि उद्योग जगत से मिले सुझावों की जांच की जा रही है ताकि ग्राहकों के लिए कीमतों की तुलना आसान हो सके।

प्रतीकात्मक

पश्चिमी रेलवे ने गोरेगांव-मलाड खंड पर अतिक्रमण हटाया

मुंबई, प्रेट्र : पश्चिमी रेलवे ने सोमवार को मुंबई के गोरेगांव और मलाड के बीच पटरियों के किनारे अतिक्रमण हटाया और 1500 वर्ग मीटर भूमि को खाली कराया। कुल 36 स्थायी अतिक्रमण और 24 अस्थायी संरचनाएं हटाई गईं।

पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक ने बताया कि बांबे हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार पूर्वी तरफ किलोमीटर मार्कर 28-3 और 28-6 के बीच यह कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि इस अभियान के दौरान पुलिस के 168 जवान, आरपीएफ के 25 जवान और रेलवे पुलिस के 65 जवान मौके पर तैनात थे।

उन्होंने बताया कि लगभग 80 रेलवे कर्मचारियों के साथ ही तीन जेसीबी मशीनें और तीन डंपर भी इस कार्य में लगाए गए थे। बता दें अतिक्रमण के कारण सुरक्षा को लेकर भी खतरा उत्पन्न करता है।

रणवीर सिंह पर लगा प्रतिबंध, डान-3 विवाद पर सिने संस्था की कार्रवाई

एंटरटेनमेंट ब्यूरो, मुंबई

फिल्म डान-3 विवाद में अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ निर्माता फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी की शिकायत पर सिनेकर्मियों के लिए काम करने वाली संस्था फेडरेशन आफ वेस्टर्न इंडिया सिने इंप्लाइज (एफडब्ल्यूआइसीई) ने सोमवार को कहा कि उसके चार लाख से अधिक सदस्य अब अभिनेता के साथ काम नहीं करेंगे। दरअसल, फिल्म धुरंधर की सफलता के बाद रणवीर ने डान फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म डान-3 अंतिम पलों में करने से इन्कार कर दिया था, जबकि फिल्म पर तीन वर्षों से काम चल रहा था। इसके बाद निर्माता तथा निर्देशक फरहान अख्तर ने इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन (आइएफटीडीए) में गत 11 अप्रैल को शिकायत दर्ज कराई थी। आइएफटीडीए ने आगे की कारवाई के लिए यह मामला एफडब्ल्यूआइसीई के पास भेज दिया था। निर्माताओं का दावा है कि प्री-प्रोडक्शन चरण में ही 45 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जा चुके थे।

शिकायतकर्ताओं का पक्ष सुनने के बाद एफडब्ल्यूआइसीई ने रणवीर को संस्था के सामने अपना पक्ष रखने का संदेश भेजा। रणवीर की तरफ से कहा गया कि एफडब्ल्यूआइसीई इस मामले के लिए सही फोरम नहीं होगा।

- चार लाख से अधिक सदस्य अब उनके साथ नहीं करेंगे काम

रणवीर सिंह। फाइल

बच्ची की हत्या मामले में मीडिया ब्रीफिंग में हंसते दिखे पुलिस अधिकारी

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : तमिलनाडु के कोयंबटूर में 10 साल की एक मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी और हत्या के मामले में पुलिस का एक ऐसा गैर-जिम्मेदाराना बर्ताव सामने आया है, जिसने लोगों को नाराज कर दिया है। हुआ यह कि इस मामले में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान पुलिस के कुछ वरिष्ठ अधिकारी हंसते नजर आए। इसका वीडियो प्रसारित होने पर इंटरनेट मीडिया पर लोगों ने ऐसे संवेदनशील मामले में पुलिस के व्यवहार पर नाराजगी जताई और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

बच्ची से दरिंदगी व हत्या मामले में सोमवार को प्रेस कान्फ्रेंस बुलाई गई थी। इसमें तमिलनाडु वेस्ट जोन की आइजी राम्या भारती समेत कई अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान खासतौर पर आइजी भारती जोर-जोर से हंसती नजर आईं।

यूएई के 500 करोड़ के धन संबंधी अध्यादेश मामले में सुनवाई करेगा कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : यूएई की अदालत द्वारा रास अल खैमाह इन्वेस्टमेंट अथारिटी (राकिया) के पक्ष में और हैदराबाद के उद्योगपति निम्मगड्डा प्रसाद के खिलाफ पारित 500 करोड़ रुपये से अधिक के धन संबंधी अध्यादेश मामले पर सुप्रीम कोर्ट जुलाई में सुनवाई करेगा। इससे पहले भारत के पूर्व सीजेआइ यूयू ललित द्वारा शुरू की गई मध्यस्थता विफल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया।

राकिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्य बागची तथा जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ को सूचित किया कि मध्यस्थता प्रक्रिया विफल हो गई है। अब इस मामले की सुनवाई जुलाई में अदालत द्वारा ही की जाएगी।

इससे पहले 16 मार्च को प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए यूयू ललित को मध्यस्थ नियुक्त किया था। सोमवार को पीठ ने कहा कि वह फिलहाल अंतरिम आवेदनों पर सुनवाई नहीं करेगी और मुख्य मामले की सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में प्रतिदिन के आधार पर करेगी।

यह विवाद आंध्र प्रदेश में बंदरगाह और हवाई अड्डे के विकास के लिए शुरू किए गए एक संयुक्त प्रोजेक्ट 'वैनपिक' से जुड़ा है। यह परियोजना साल 2008 में शुरू हुई थी, लेकिन बाद में यह सफल नहीं हो पाई और इसके बाद दोनों पक्षों के बीच वित्तीय विवाद खड़ा हो गया।

- पूर्व सीजेआइ यूयू ललित द्वारा शुरू की गई मध्यस्थता विफल होने के बाद कोर्ट ने यह निर्णय लिया
- आंध्र प्रदेश में बंदरगाह और हवाई अड्डे के विकास के लिए शुरू किए गए एक संयुक्त प्रोजेक्ट से जुड़ा है विवाद

कोलकाता से श्रीनगर तक फैला आइपीएल सट्टा नेटवर्क ध्वस्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : आइपीएल में चल रहे अंतरराज्यीय सट्टा नेटवर्क का रायपुर पुलिस ने राजफाश किया है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट (एसीसीयू) ने 72 घंटे तक कार्रवाई करते हुए कोलकाता, गुरुग्राम, श्रीनगर, गोवा और छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से जुड़े पांच बड़े सट्टा पैनल ध्वस्त कर 26 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कुल चार करोड़ 29 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है।

पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 17.92 लाख रुपये नकद, 59 मोबाइल फोन, चार लैपटाप, एक चारपहिया वाहन समेत करीब 50 लाख रुपये का सामान जब्त किया है। रायपुर के चार थाना क्षेत्रों में दर्ज मामलों के तार कोलकाता, हरियाणा के गुरुग्राम-फरीदाबाद, झारखंड के देवघर, श्रीनगर, गोवा, महाराष्ट्र के गोंदिया, बिहार, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, रायगढ़, खरसिया और बालोद तक जुड़े थे।

हाथरस में रेलवे ट्रैक पर खड़ी कार से टकराई आगरा फोर्ट एक्सप्रेस

जागरण संवाददाता, हाथरस

आपसी रंजिश के चलते चार लोगों ने पड़ोसी कार चालक से बुरी तरह मारपीट की। जान बचाने के लिए चालक कार को रेलवे ट्रैक पर खड़ी कर भाग गया। रविवार देर रात आगरा फोर्ट एक्सप्रेस की टक्कर से ट्रैक पर खड़ी कार दूर जा गिरी। इस टक्कर के कारण कोई बड़ा हादसा तो नहीं हुआ, लेकिन ट्रेन करीब सवा घंटे खड़ी रही। इस मामले में एक मुकदमा कार मालिक ने मारपीट करने वाले चार लोगों के खिलाफ तो दूसरा मुकदमा रेलवे के गेट मैन ने ट्रैक पर कार खड़ी करने का दर्ज कराया है।

रविवार रात आगरा-रामनगर 'आगरा फोर्ट एक्सप्रेस' तय समय रात 11:50 बजे से कुछ देर लेट चल रही थी। रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर खड़ी कार ट्रेन की टक्कर से दो सौ मीटर दूर घिसटने के बाद दूसरे ट्रैक पर जा गिरी। इस कारण हुए धमाके से यात्रियों में दहशत फैल गई। रेलवे, जीआरपी और आरपीएफ के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। रात एक बजे ट्रेन रवाना की गई। कार मालिक रतन शर्मा ने शांतनु कौशिक उर्फ डेविड, मोना, भानू और अंकित के खिलाफ मुकदमा कराया। उसका कहना है कि आरोपितों ने उसके बेटे से शराब लाने को कहा था। मना करने पर आरोपितों ने उस पर हमला किया। वह जान बचाने के लिए भाग निकला तो आरोपितों ने उसकी कार ट्रैक पर खड़ी कर दी। थाना प्रभारी अरविंद सक्सेना ने बताया कि डेविड को गिरफ्तार कर लिया गया है।

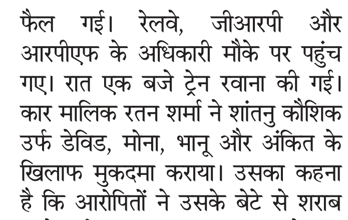

रेलवे ट्रैक पर क्षतिग्रस्त कार। जागरण

जम्मू से मुंबई के लिए रवाना हुई चेरी स्पेशल पार्सल वैन

जागरण संवाददाता, जम्मू : जम्मू-कश्मीर की लजीज चेरी अब रेलवे की रफ्तार के साथ सीधे मुंबई के बाजारों में पहुंच रही है। सोमवार की सुबह इस सीजन की पहली चेरी स्पेशल पार्सल वैन को जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए रवाना किया गया। यह पार्सल वैन 33 घंटे के रिकार्ड समय में बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी, जिससे मुंबई के बाजारों में ताजी चेरी उपलब्ध हो सकेगी। तेज और सुरक्षित परिवहन के कारण चेरी की गुणवत्ता पर असर नहीं पड़ेगा और किसानों को बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है। पार्सल वैन में 966 बाक्स वाली 12 टन प्रीमियम गुणवत्ता वाली चेरी को लोड किया गया। इस विशेष पार्सल वैन को ट्रेन संख्या 19028 जम्मू तवी-बांद्रा टर्मिनस विवेक एक्सप्रेस के साथ जोड़ा गया। चेरी जैसे नाजुक फल की ताजगी और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं।

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

समाधान की आशा

होर्मुज पर बात आगे नहीं बढ़ पाई। रविवार को एक समय ऐसा लगा कि अमेरिका-ईरान समझौते की ओर एक कदम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन सोमवार सुबह तक अमन की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आया। समझौते की स्थिति न बन पाने के अनेक कारण हैं, पर मुख्य कारण है- ईरान में अनुभवी नेतृत्व का अभाव। गहरी चोट खाने के बाद वहां का नया नेतृत्व कोई भी जोखिम उठाने के पक्ष में नहीं है। ईरान का नया नेतृत्व लंबे समय तक के लिए शांति चाहता है, लेकिन शायद अमेरिकी वार्ताकार उसे आश्वस्त नहीं कर पा रहे हैं। संकेत यही है कि परमाणु हथियार बनाने के अपने इरादे से ईरान पीछे हट सकता है, पर बदले में वह स्वाभाविक ही कोई फायदा चाहता है। क्या अमेरिका आश्वासन दे सकता है कि वह फिर ईरान पर कभी आक्रमण नहीं करेगा? क्या अमेरिका आगे बढ़कर ईरान के पुनर्निर्माण में सहायक हो सकता है? पाकिस्तानी वार्ताकारों की कोशिश है कि अमेरिकी प्रस्तावों पर ईरान भरोसा कर ले, पर ईरानी नेतृत्व पाकिस्तान की हकीकत से वाकिफ है। ईरान कभी भी पाकिस्तान नहीं हो सकता। वह अपनी आजाद आवाज को बचाए रखने के लिए जमीन-आसमान एक कर देगा।

इधर, भारत में लोग लगातार उम्मीद लगाए हुए हैं कि राहत की खबर आएगी, पर आए दिन पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। सोमवार को ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक पखवाड़े में चौथी बार बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 2.71 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। ईंधन की कीमत बढ़ने का यह क्रम तब तक जारी रह सकता है, जब तक तेल विपणन कंपनियों का घाटा पूरा न होने लगे। तेल क्षेत्र में सुधार के संकेत दिख रहे थे, पर अमेरिका-ईरान वार्ता में कोई सफलता नहीं मिली, जिससे कच्चे तेल की आपूर्ति में व्यवधान की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कभी ईरान को मनाने या बहलाने की कोशिश करते हैं, तो कभी धमकियां देने लगते हैं। ट्रंप को एक बार दुनिया पर ईमानदारी से निगाह डालकर देखना चाहिए। युद्ध रोकने के लिए कुछ त्याग जरूरी है। युद्ध से अमेरिका को 2.6 अरब डॉलर से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हो चुका है, पर ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों में अनेक जगह ऐसी तबाही मची है कि जख्म भरने में काफी वक्त लग जाएगा। अनुमान है, कम से कम 5,000 लोग मारे गए हैं। ध्यान रखना चाहिए कि युद्ध अगर जारी रहा, तो आर्थिक मंदी और महंगाई से करोड़ों लोगों की जिंदगी पटरी से उतर जाएगी।

भारत में तमाम लोग लगातार उम्मीद लगाए हुए हैं कि ईरान से राहत भरी कोई खबर आएगी, पर यहां तो पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ने के दिन चल रहे हैं।

एक ओर, जहां भारत सरकार जल्द से जल्द युद्ध के समाधान के पक्ष में है, वहीं दूसरी ओर, आम लोगों की स्थिति को लेकर चिंतित भी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को ही कहा है कि सरकार पश्चिम एशिया संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रही है। विशेष रूप से ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा भंडार (3 एफ) पर सरकार का ज्यादा ध्यान है। महंगा होते ईंधन और रुपये के मुकाबले चढ़ती विदेशी मुद्रा की चर्चा के बीच उर्वरक पर लोगों का ज्यादा ध्यान नहीं जा रहा है, पर हकीकत में उर्वरक संकट खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था और जीविका की बुनियाद है, इसकी विकास दर को बचाए रखने के प्रयासों में कमी नहीं आनी चाहिए। यह समय चुनौतियों से भरा हुआ है, पर वित्त मंत्री की यह सलाह भी सही है कि अनेक अच्छे कार्यों को भुलाकर निराशावादी या नकारात्मक माहौल न बनाया जाए।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 26 मई, 1951

कोरिया में शान्ति प्रयास

जब युद्ध में कोई पक्ष हार रहा हो, तो उसके लिए समझौते का कोई प्रस्ताव करना मुश्किल होता है। उसके ऐसे प्रयास को उसकी कमजोरी समझा जा सकता है। कोरिया के युद्ध में पासा एक बार फिर संयुक्त राष्ट्रीय सेनाओं के पक्ष में पलट गया है। साम्यवादियों ने जो वसन्तकालीन आक्रमण शुरू किया था, उसे विफल कर दिया गया है। साम्यवादी एक बार फिर पीछे हट गये हैं और संयुक्त राष्ट्रीय सेनाओं ने पुनः आगे बढ़ना शुरू कर दिया है।

संयुक्त राष्ट्रीय सेनायें कोरिया युद्ध के इतिहास में तीसरी बार 38 अक्षांश रेखा को कुछ स्थलों पर पार करके उत्तरी कोरिया की सीमा में दाखिल हो गयी हैं। अब यह कहा जा सकता है कि कोरिया में इस समय संयुक्त राष्ट्रीय सेनाओं का पलड़ा भारी है और अब यदि संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से कोरिया में शांति स्थापना के लिए नये प्रस्ताव पेश किये जायें, तो इसे उसकी कमजोरी की निशानी नहीं समझा जा सकता। कोरिया में युद्ध जितने दिन अधिक जारी रहता है, उतना ही उसके फैलने का खतरा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का यह घोषित मन्तव्य है कि वह कोरिया युद्ध को फैलने देना नहीं चाहता। ऐसी अवस्था में यह बहुत उपयुक्त अवसर है, जब संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से कोरिया में युद्ध विराम के लिए नये सिरे से प्रयत्न किये जाने चाहिए।

जनरल रिजवे ने, जब वह कोरिया में आठवीं सेना के कमाण्डर थे, इस आशय के उद्गार प्रकट किये थे कि यदि दक्षिण कोरिया को आक्रमणकारियों से मुक्त कर दिया गया, तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ की बड़ी भारी विजय होगी। पिछली बार जब संयुक्त राष्ट्रीय सेनायें 38 अक्षांश रेखा के निकट पहुंच रही थीं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के संबंध में उसकी ओर से एक अधिकृत घोषणा प्रकाशित करने के बारे में विचार किया जा रहा था, किन्तु जनरल मैकार्थर ने अपने वक्तव्य द्वारा वह अवसर ही नहीं आने दिया। जनरल मैकार्थर अब अपने पद से हट गये हैं और उनके स्थान पर जनरल रिजवे नियुक्त हुए हैं। अब यदि संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसी घोषणा कर देता है कि संयुक्त राष्ट्रीय सेनाओं के 38 अक्षांश रेखा पर पहुंचने के साथ कोरिया में उसके सैनिक उद्देश्य की पूति हो जाती है और यदि प्रतिपक्षी इस मंजिल पर सैनिक कार्रवाई बन्द करने के लिए तैयार हों, तो कोरिया युद्ध समाप्त हो सकता है।

इबोला महामारी फैलने के मायने

कुछ अफ्रीकी देशों ने चिंता बढ़ा दी है। यदि दुनिया इबोला जैसे महारोगों को रोकना चाहती है, तो उसे स्वास्थ्य वित्त व्यवस्था को स्थायी, विविध और न्यायपूर्ण बनाना होगा।

यहां स्कैन करें

चंद्रकांत लहारिया | वरिष्ठ चिकित्सक और महामारी विशेषज्ञ

कांगो नदी दुनिया की विशाल और गहरी नदियों में गिनी जाती है। इसके एक किनारे पर कांगो गणराज्य की राजधानी ब्राजाविल बसी है, तो दूसरी तरफ कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी किंशासा। दुनिया में यह अनोखा दृश्य कहीं और नहीं मिलता, जहां दो राष्ट्रीय राजधानियां एक-दूसरे के ठीक सामने स्थित हों। किंशासा की ऊंची इमारतें पहली नजर में किसी आधुनिक वैश्विक महानगर का आभास देती हैं, लेकिन यह दुनिया के सबसे गरीब, संघर्षरत और अस्थिर देशों में से एक की राजधानी भी है। इसी देश और इसके पड़ोसी युगांडा में एक बार फिर इबोला महामारी उभरी है, जिसके कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है।

इबोला के वैश्विक महामारी बनने की अभी आशंका नहीं है। यह गंभीर बीमारी तो है, लेकिन यह एक से दूसरे इंसान में तभी फैलती है, जब पहले वाले व्यक्ति में इसके लक्षण मौजूद हों। इसीलिए भारत या अन्य अप्रभावित देशों को तत्काल कोई बड़ा खतरा नहीं है, किंतु बड़ा सवाल यह है कि महामारी से निपटने की तैयारी, वैश्विक सहयोग व स्वास्थ्य सुरक्षा पर लगातार चर्चा के बावजूद इबोला रोग बार-बार क्यों लौट आता है?

इसका उत्तर सिर्फ चिकित्सा विज्ञान में नहीं, बल्कि राजनीति, अर्थव्यवस्था और वैश्विक असमानताओं में भी छिपा है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य प्राकृतिक संसाधनों, खनिजों व दुर्लभ धातुओं से अत्यंत समृद्ध देश है। दुनिया की आधुनिक तकनीकी व इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था जिन खनिजों पर निर्भर है, उनमें से कई का स्रोत यही क्षेत्र है। मगर इस संपदा की कीमत स्थानीय समाज और पर्यावरण चुका रहे हैं। खनन, जंगलों की कटाई और प्राकृतिक आवासों के लगातार बढ़ते अतिक्रमण ने मनुष्यों व जंगली जीवों के बीच की दूरी को कम कर दिया है। नतीजतन, मनुष्य ऐसे रोगजनकों के संपर्क में आ रहे हैं, जो पहले केवल वन्य-जीवों तक सीमित थे। वैज्ञानिक लंबे समय से चेतावनी देते रहे हैं कि पर्यावरण विनाश और संसाधनों का अनियंत्रित दोहन नई महामारियों के उभरने के बड़े कारण बन सकते हैं। इबोला उसी व्यापक संकट का हिस्सा है।

अफ्रीका के कई देश पिछले दशकों में नए संक्रमणों और उभरती बीमारियों के केंद्र रहे हैं। इबोला इनमें से सबसे भयावह बीमारियों में से एक है। यह ऐसी बीमारी बन चुकी है, जिसके कारण सबसे अधिक बार वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करना पड़ा है। हालांकि, सवाल यह भी है कि यदि दुनिया हर बार इसके कारण स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करती है, तो फिर इसका स्थायी समाधान क्यों नहीं निकालती?

कारण यह है कि संकट आने पर वैश्विक स्वास्थ्य संस्थाएं तेजी से सक्रिय हो जाती हैं, लेकिन संकट को स्थायी रूप से रोकने के लिए वे आवश्यक निवेश नहीं करतीं। जिन देशों में बार-बार इबोला महारोग फैलता है, वहां स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पहले से लचर हैं। प्रयोगशालाएं सीमित हैं। स्वास्थ्यकर्मियों की भारी कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंच पा रहीं। और, कई क्षेत्रों में जातीय संघर्ष व राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है। ऐसे में, जब इबोला महामारी फैलती है, तब दुनिया अचानक चिंतित हो उठती है। अंतरराष्ट्रीय टीमें पहुंचती हैं, फंड जारी किए जाते हैं, पर जैसे ही संक्रमण कम होता है, दुनिया का ध्यान हटने लगता है। कुछ वर्षों बाद यही चक्र फिर से चलता है- स्वास्थ्य आपातकाल, अस्थायी सक्रियता और फिर विस्मृति।

यह केवल इबोला की कहानी नहीं है। यह वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था की उस प्रवृत्ति को दर्शाता है, जिसमें गरीब देशों को प्रभावित करने वाली बीमारियों को तब तक गंभीरता से नहीं लिया जाता, जब तक कि वे अमीर देशों की सीमाओं में नहीं पहुंच जातीं। 'मंकी पॉक्स' इसका हालिया उदाहरण है। वर्षों तक यह बीमारी अफ्रीकी देशों में सीमित रूप से फैलती रही, पर जैसे ही 2022 में इसके मामले यूरोप और उत्तर अमेरिका में दिखने लगे, अंतरराष्ट्रीय चिंता अचानक बढ़ गई। प्रश्न यह नहीं है कि मंकी पॉक्स को गंभीरता से क्यों लिया गया? प्रश्न यह है कि दुनिया तब तक क्यों प्रतीक्षा करती रही, जब तक बीमारी अमीर देशों तक नहीं पहुंच गई?

इबोला रोग वैश्विक स्वास्थ्य शासन की संस्थागत सीमाओं को भी उजागर करता है। इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की अक्सर निंदा की जाती है, पर असल समस्या कहीं गहरी है। दुनिया यह अपेक्षा तो करती है कि डब्ल्यूएचओ वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा का नेतृत्व करे, पर उसे पर्याप्त संसाधन और शक्ति देने की पहल नहीं करती। डब्ल्यूएचओ का बड़ा हिस्सा दुनिया के अमीर देशों की स्वैच्छिक फंडिंग पर निर्भर है। उन देशों की प्राथमिकताएं समय और नई सरकारों के साथ बदलती रहती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन चेतावनी दे सकता है, समन्वय कर सकता है, तकनीकी मदद दे सकता है, पर देशों को दीर्घकालिक निवेश के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

यह बहस तब और अहम हो जाती है, जब महामारी संधि, रोगजनक साझा करने व भविष्य की तैयारी पर चर्चा हो रही हो। कई निम्न और मध्यम आय वाले देश अब पूछने लगे हैं कि यदि वे रोगजनकों और जैविक नमूनों की मार झेलते हैं, तो क्या उन्हें वैक्सीन, तकनीक और उत्पादन क्षमता तक समान पहुंच मिल सकेगी? कोविड-19 ने बताया था कि संकट के समय वैश्विक समानता के दावे कितने कमजोर पड़ जाते हैं।

इसी बीच, वैश्विक स्वास्थ्य वित्त-पोषण में बढ़ती अनिश्चितता ने व्यवस्थागत संवेदनशीलता को और उजागर किया है। अमेरिका सहित कई देशों द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आर्थिक कटौती ने साफ किया है कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा कुछ चुनिंदा देशों और फाउंडेशनों पर निर्भर है। लिहाजा, जब किसी एक देश की घरेलू राजनीति बदलती है, तो उसका असर दुनिया भर की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर दिखने लगता है। यदि दुनिया वास्तव में इबोला जैसे रोगों को रोकना चाहती है, तो उसे स्वास्थ्य वित्त व्यवस्था को अधिक स्थायी, विविध और न्यायपूर्ण बनाना होगा। अफ्रीकी देशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे, प्रयोगशालाओं और वैक्सीन निर्माण-क्षमता में दीर्घकालिक निवेश करना होगा। महामारी से निपटने की तैयारी केवल आपातकाल आने के बाद राहत भेजने तक सीमित नहीं रह सकती। 'ग्लोबल साउथ', ब्रिक्स के देशों और अफ्रीकी संघ को अधिक आर्थिक व नीतिगत भागीदारी करनी होगी।

अहम बात यह है कि निम्न आय वाले देशों को प्रभावित करने वाली बीमारियों को तब भी प्राथमिकता दी जाए, जब वे अमीर देशों तक नहीं पहुंची हों। इबोला का बार-बार लौटना एक वायरस की वापसी भर नहीं है। यह इस तथ्य का प्रमाण है कि वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था आज भी भेदभावपूर्ण बनी हुई है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

तमिल राजनीतिक दलों में उलटफेर का दौर

दक्षिण एक्सप्रेस

यहां स्कैन करें

एस श्रीनिवासन | वरिष्ठ पत्रकार

तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय सरकार को बने अभी मुश्किल से दो हफ्ते ही हुए हैं, लेकिन उसने दो दशक पुराने द्रमुक गठबंधन को तोड़कर रख दिया है, वहीं 54 साल पुरानी अन्नाद्रमुक पार्टी विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पर दो फाड़ हो गई। इस उथल-पुथल के बीच फंसी भाजपा और उसके एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल चुपचाप बैठे हैं और विजय सरकार पर हमले के लिए सही मौके का इंतजार कर रहे हैं।

द्रमुक गठबंधन के सभी पुराने सहयोगी तेजी से विजय की सत्ताधारी पार्टी तमिलगा वेट्री कषगम, यानी टीवीके की ओर झुकने लगे हैं। इससे यह आशंका बढ़ गई है कि कहीं द्रमुक अकेला न पड़ जाए। एम के स्टालिन और उनकी पार्टी के लिए यह घटनाक्रम बेहद दुखद है। पराजय के बाद द्रमुक गठबंधन छोड़ने वाली पहली पार्टी कांग्रेस थी। जब चुनाव नतीजे टीवीके के पक्ष में आए, तब राज्य कांग्रेस के नौजवान नेताओं ने कोई मौका नहीं गंवाया और अपना फैसला हाईकमान तक पहुंचा दिया। उन्होंने हाईकमान को मजबूर किया कि वह टीवीके गठबंधन में शामिल होने और कैबिनेट का हिस्सा बनने को लेकर असमंजस त्याग दे। कांग्रेस ने कम्युनिस्ट पार्टियों व आईयूएमएल की राज्य इकाइयों को भी टीवीके गठबंधन में शामिल होने के लिए राजी करने में अहम भूमिका निभाई। इसके लिए उसने दिल्ली व केरल में मौजूद अपने शीर्ष नेताओं के जरिये दबाव बनाया। इसके बाद तमिलनाडु की एकमात्र दलित पार्टी- वीसीके के पास टीवीके के साथ गठबंधन करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा।

विजय के सत्तासीन होने के बाद दोनों मुख्य खेमों में जो भगदड़ की स्थिति दिख रही है, उससे तमिलनाडु की राजनीति दिलचस्प हो उठी है।

कांग्रेस के अलावा, वीसीके और आईयूएमएल को भी विजय की काबीना में जगह मिली है। अतीत में, न तो द्रमुक ने और न ही अन्नाद्रमुक ने कभी किसी गठबंधन सहयोगी को मंत्रिमंडल में कोई पद दिया था। अब वाइको के नेतृत्व वाली पार्टी एमडीएमके भी डीएमके गठबंधन से अलग होने की संभावना पर विचार कर रही है। फिलहाल, द्रमुक गठबंधन में एकमात्र अहम सहयोगी पार्टी डीएमडीके ही बची है, जिसका नेतृत्व दिवंगत विजयकांत की पत्नी प्रेमलता कर रही हैं।

जानकारों का कहना है कि इस तरह का राजनीतिक बिखराव और अकेलापन द्रमुक के लिए कोई नई बात नहीं है। सन् 1991 में भी इस पार्टी को कुछ ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था, जब राजीव गांधी की हत्या के बाद उसके सहयोगियों ने साथ छोड़ दिया था। साल 2011 और 2016 में भी द्रमुक पार्टी ऐसे हालात से निपट चुकी है। मूल सवाल है कि क्या स्टालिन पार्टी को इस संकट से उबार पाएंगे? फिलहाल, बिल्कुल नए चेहरे के हाथों मिली अप्रत्याशित हार ने पार्टी को सदमे में डाल दिया है।

ई पलानीसामी के नेतृत्व वाली पार्टी अन्नाद्रमुक अंदरूनी कलह से जूझ रही है। एसपी वेलुमणि व केसी वीरमणि के नेतृत्व में बागी हुए विधायकों ने अन्नाद्रमुक में वापस लौटने का फैसला कर लिया है। चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री का संगठन पर मजबूत नियंत्रण है, इसलिए बागियों के पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। विजय ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। चूंकि ये सभी नेता भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपी हैं, इसलिए भी विजय कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। उधर, इस हार से आहत भगवा पार्टी ने फिलहाल शांत रहने का फैसला किया है।

परिस्थितियों ने विजय को प्रशासन पर अपनी पकड़ और मजबूत करने में मदद की है। पिछले हफ्ते, पुलिस ने 24 घंटे के भीतर एक रेप के मामले को सुलझा लिया और विजय ने निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से कई बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राज्य सरकार से पूर्व मंत्रियों- अनिता राधाकृष्णन (अन्नाद्रमुक), सेंथिल बालाजी (द्रमुक) और अन्य के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति मांगी है। यदि सरकार 120 दिनों के भीतर कोई कदम नहीं उठाती, तो मान लिया जाएगा कि अनुमति मिल गई है। हालांकि, विजय के सामने एक बड़ी चुनौती है। जिस व्यक्ति ने खुद को 'शुद्ध शक्ति' या 'तूया शक्ति' और डीएमके को 'दुष्ट शक्ति' या 'तीया शक्ति' घोषित किया था, अब उसे अपने कहे पर खरा उतरना होगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

घृणा से भिन्न नहीं ईर्ष्या

एक दिन मेरे पास एक शिक्षिका आईं और कहा, 'मेरी यह धारणा थी कि मैं बच्चों से बहुत प्रेम करती हूं, लेकिन अब लगता है कि घृणा, गहरे विद्वेष का एक अंतःप्रवाह हमेशा मुझमें बहता रहा है। इस बात की प्रतीति से मैं भयभीत और बेचैन हो उठी हूं।... मैंने कभी घृणा की प्रक्रिया को बारीकी से देखा ही नहीं है।'

मैंने उनसे कहा, आइए, हम उसका अवलोकन करें और देखें कि क्या होता है; जैसे-जैसे घृणा अपने आप को खोलती जाए, हम बस अक्रिय होकर उसके प्रति जागरूक रहें। चौंकिए मत, निंदा मत कीजिए या बहाने मत ढूंढ़िए, केवल अक्रिय होकर उसका अवलोकन कीजिए। घृणा एक प्रकार की कुंठा है। परितुष्टि और कुंठा सदा साथ ही चलते हैं।

मैंने शिक्षिका से पूछा कि आपने विवाह किया है? उन्होंने कहा, 'मुझे एक विवाहित व्यक्ति से प्रेम हो गया था और हम गुप्त रूप से साथ रहे। मैं उसकी पत्नी और बच्चों से भयंकर ईर्ष्या करती थी और मेरे बच्चे हों, ऐसी तड़प रहते हुए भी इसकी कल्पना से डरती थी।'

ईर्ष्या तो घृणा ही है न? यदि कोई प्रेम करता है, तो दूसरी किसी चीज के लिए स्थान ही नहीं रहता है। दरअसल, हम प्रेम करते ही नहीं, धुआं हमारे जीवन को अवरुद्ध कर देता है और ज्योति बुझ जाती है। शिक्षिका ने माना, 'हां! मैं अब देख सकती हूं कि स्कूल में, अपनी विवाहिता बहनों के साथ और मेरे लगभग सभी अन्य संबंधों में एक संग्राम चल रहा था, जो केवल ढका हुआ था। एक आदर्श अध्यापिका बनना मेरा ध्येय था और मैं उसी रूप में सम्मानित भी हो रही थी।'

याद रखिए, आदर्श जितना मजबूत होगा, उतना ही गहरा दमन होगा, उतना ही गहरा द्वंद्व और द्वेष होगा।

शिक्षिका ने कहा, 'जी हां, मैं यह सब देख पा रही हूं और आश्चर्य यह है कि स्वयं को देखते समय मैं वस्तुतः जैसी हूं, वैसी ही होने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।'

आपको आपत्ति नहीं है, क्योंकि उसमें एक तरह की क्रूर पहचान है, स्वीकृति है। है न? यह क्रूर स्वीकृति ही एक तरह का सुख लाती है, ऊर्जा देती है। जैसे ईर्ष्या दुखदायी होते हुए भी एक सुखद संवेदन देती थी, वैसे ही अब आपके अतीत का ज्ञान आपको एक तरह के स्वामित्व का भाव देता है और यह भी सुखद है। अब ईर्ष्या और हताशा के स्थान पर, वंचित रह जाने के स्थान पर, एक नया शब्द आपके हाथ आ गया है, वह है घृणा और उसका ज्ञान। इस ज्ञान में अभिमान है, जो द्वेष का ही दूसरा रूप है। हम एक विकल्प से दूसरे की तरफ मुड़ते हैं, लेकिन तत्वतः सारे विकल्प एक समान हैं।... विचार मुक्ति का आश्वासन देता है, लेकिन उत्पन्न करता है एक और द्वेष। इसके प्रति जागरूक हो जाइए और इसके सत्य का प्रकट होने दीजिए।

यदि कोई प्रेम करता है, तो दूसरी किसी चीज के लिए स्थान ही नहीं रहता है। दरअसल, हम प्रेम करते ही नहीं, धुआं हमारे जीवन को अवरुद्ध कर देता है और ज्योति बुझ जाती है।

जे कृष्णमूर्ति

सी पी राधाकृष्णन | उप-राष्ट्रपति, भारत

एक पुस्तकालय किसी बच्चे का भविष्य संवार सकता है, एक किताब किसी के जीवन को बदल सकती है, एक निश्चयी व्यक्ति पूरे समाज को बदल सकता है। युवाओं में पढ़ने की आदतों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है।

अनुलोम-विलोम

कॉकरोच जनता पार्टी

नौजवानों में बढ़ रही नाराजगी के संकेत

भारत की राजनीति में इन दिनों 'कॉकरोच जनता पार्टी' नाम अचानक चर्चा का विषय बन गया है। पहली नजर में यह केवल इंटरनेट पर चल रहा मजाक दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में यह देश के युवाओं के भीतर बढ़ रही नाराजगी और निराशा का प्रतीक बन चुका है। बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और राजनीतिक विमर्श में वास्तविक मुद्दों की कमी ने युवाओं के भीतर गहरा असंतोष पैदा किया है। यही असंतोष अब व्यंग्य और डिजिटल अभियानों के रूप में सामने आ रहा है। इस पूरे विवाद की शुरुआत उस कथित टिप्पणी से हुई, जिसमें बेरोजगार युवाओं के लिए अपमानजनक शब्दों का उपयोग किए जाने का आरोप लगा। इसके बाद सोशल मीडिया के मंचों से नौजवानों ने उसी शब्द को विरोध के प्रतीक में बदल दिया। 'कॉकरोच जनता पार्टी' नाम से व्यंग्यात्मक पोस्टर, घोषणा-पत्र और वीडियो वायरल होने लगे। कुछ ही दिनों में लाखों लोग इससे जुड़ गए। यह केवल हास्य नहीं, बल्कि व्यवस्था के प्रति घटते भरोसे का संकेत है। आज का युवा केवल भाषण नहीं सुनना चाहता, बल्कि रोजगार, पारदर्शिता और सम्मान चाहता है। उसे लगता है कि उसकी वास्तविक समस्याएं राजनीतिक प्राथमिकताओं से बाहर होती जा रही हैं। यही कारण है कि इंटरनेट अब राजनीतिक अभिव्यक्ति का मजबूत मंच बन चुका है। हालांकि, डिजिटल आंदोलनों की अपनी सीमाएं भी होती हैं, पर इनको हल्के में नहीं लिया जा सकता। इतिहास बताता है कि जब समाज में असंतोष बढ़ता है, तब उसकी पहली आवाज अक्सर व्यंग्य के रूप में ही सामने आती है। 'कॉकरोच जनता पार्टी' भी उसी बदलते माहौल का संकेत है।

अवनीश कुमार गुप्ता, टिप्पणीकार

देश के हालात कितने खराब हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक ऑनलाइन मीम कैंपेन ने सत्ता और विपक्ष, दोनों को एक साथ बिदका दिया है। कुछ बालकों ने प्रधान न्यायाधीश की टिप्पणी पर सोशल मीडिया में छुरछुरी छोड़ दी। निराश, नाराज और नाखुश लाखों बच्चे उस छुरछुरी के जरिये अपनी भड़ास निकालने लगे। उसमें कुछ युवा और बड़ी उम्र के लोग भी शामिल हुए। वास्तव में, 'कॉकरोच जनता पार्टी' एक सोशल मीडिया प्रतिक्रिया है। यह प्रतिक्रिया क्यों आई, इस पर विचार करने की जगह बच्चों की कुंडली बांचने का सिलसिला चल पड़ा, ज्ञानी लोग डीप स्टेट से लेकर विदेशी पैसा और अंदर के खेल पर जुगाली करने लगे। डरिए, इन बच्चों ने यदि इस क्षण का राजनीतिक इस्तेमाल कर लिया, तो आपका क्या होगा!

प्रकाश के रे, टिप्पणीकार

आभासी फॉलोअर्स से हकीकत नहीं बदलती

'कॉकरोच जनता पार्टी' को लेकर इंटरनेट पर बहस गरम है। कोई इसे युवाओं के आक्रोश का प्रतीक बता रहा है, कोई संपूर्ण क्रांति की याद दिला रहा है, तो कोई अन्ना आंदोलन की ठगी का हवाला दे रहा है। हालांकि, सबमें एक बात सामान्य है- सब यही बोल रहे हैं, यह सब इंटरनेट पर है, कुछ जमीन पर हो, तो बात बने। साथ ही एक अजीब धारणा भी है कि जैसे जमीन पर कुछ हो ही नहीं रहा, मानो असली संघर्ष का इंतजार है किसी वायरल पोस्ट के लिए। हकीकत यही है कि जमीन पर बहुत कुछ हो रहा है। बस देखने वाली नजर चाहिए।

इस साल की शुरुआत से ही बरौनी (बिहार), पानीपत (हरियाणा), सिंगरौली (मध्य प्रदेश) से होते हुए अप्रैल-मई तक हड़तालों की एक जबर्दस्त लहर मानेसर, नोएडा, भिवाड़ी, बाड़मेर, हरिद्वार और रुद्रपुर तक फैल चुकी है। हाल के दशकों में मजदूरों का यह सबसे व्यापक और तीव्र आंदोलनों में से एक है। हर दिन किसी न किसी फैक्टरी में हड़ताल हो रही है। मीडिया ने उनको पूरी तरह नजरंदाज कर दिया है या फिर 'हिंसा' और 'बवाल' की शब्दावली में निपटा दिया है। हालांकि, दमन भी उतनी ही तेजी से हुआ है। मानेसर में 60, नोएडा में 1,100 से ज्यादा और देहरादून में 13 मजदूरों की गिरफ्तारियां, यूनियन सदस्यों पर गुंडा ऐक्ट, जिलाबदर और 'साजिश' के मुकदमे, एनएसए- सब कुछ हुए हैं। किंतु कॉकरोच पार्टी 'आउट ऑफ द बॉक्स' है और सिस्टम को चैलेंज कर रही है- यह विश्लेषण करने में हमारी प्रगतिशील बिरादरी ने रात के दो बजे तक कोई कसर नहीं छोड़ी। और हाँ, बाद में इस मज़दूर आंदोलन पर अकादमिक पर्चे खूब लिखे जाएंगे- नोट्स ऑन द वर्कर्स मुवमेंट या कैन वर्कर्स स्पीक। जब जरूरत है, तब उनको फुर्सत कहां।

वास्तव में, जो लड़ाई जमीन पर चल रही है, वह न ट्रेंडिंग है, न ग्लैमरस। न उस पर कोई स्नैपी मीम बनता है। उसमें धूल है, थकान है, दमन है और बेहद कम संसाधनों में लड़ते हुए लोग हैं, जिनके लिए 'आंदोलन' कोई 'इंटलेक्चुअल एक्सरसाइज' नहीं, बल्कि रोज की रोटी और इज्जत का सवाल है। तो एक बार मानेसर और नोएडा की उस बस्ती में जाइए, जहां किसी गिरफ्तार मजदूर का परिवार नहीं जानता कि वकील कहां से लाया जाए। एक बार उस यूनियन दफ्तर तक पहुंचिए, जिस पर 'साजिश' का मुकदमा लटका है। वह लड़ाई असली है, उसके लोग असली हैं, उनकी जरूरतें असली हैं और वे आपका इंतजार कर रहे हैं। बस एल्गोरिदम और मजदूरों की रील्स आप तक नहीं पहुंच रही।

के संतोष, टिप्पणीकार

सत्संग से पाइए सच्चा सुख

तुलसीदास ने 'श्रीरामचरितमानस' में कहा है- 'बिनु सतसंग बिबेक न होई' यानी सत्संग के बिना विवेक नहीं आता। जब तक व्यक्ति का विवेक जाग्रत नहीं होता, तब तक उसे जीवन में सच्चा सुख नहीं मिलता। सत्संग की महत्ता यज्ञ, दान, तीर्थ से भी कई गुणा अधिक मानी गई है। सन्मार्ग की ओर ले जाने वाले सत्संग से जीवन की सभी समस्याओं का निदान हो जाता है।

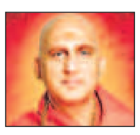

अध्यात्म
स्वामी अवधेशानंद गिरि

सत्संग संजीवनी बूटी है। इससे विवेक जाग्रत होता है। सत्संग ही वह औषधि है, जो मृतप्राय मनुष्य को भी शुभता संपन्न बना देती है। मनुष्य का कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है? यह स्पष्ट विवेक केवल सत्संग से प्रकट होता है। भागवत के एकादश स्कंध में भगवान नारदजी से कहते हैं-

नाहं तिष्ठामि वैकुण्ठे, योगिनां हृदये न च।
मद्भक्ता यत्र गायन्ति, तत्र तिष्ठामि नारद॥

'हे नारद! मैं यज्ञ, वेद, तीर्थ, तप और त्याग से वश में नहीं होता, किंतु सत्संग से शीघ्र ही अपने भक्तों के अधीन हो जाता हूं।' संसार के प्रति सभी आसक्तियां सत्संग नष्ट कर देता है। सत्संग से ही संयम जैसे दिव्य गुण- धैर्य, सदाचार, सेवा और स्नेह का प्राकट्य होता है। इसमें ही जीवन का वास्तविक आनंद, दिशा और उद्देश्य समाहित है। सत्संग से जहां राग, द्वेष, लोभ, मोह, क्रोध जैसे दुर्गुण विलीन होते हैं, वहीं प्रेम, श्रद्धा, करुणा, त्याग और विनय जैसे श्रेष्ठ गुण विकसित होते हैं।

चित्त को निर्मल करता सत्संग

सत्संग का लाभ अक्षुण्ण है अर्थात यह कभी समाप्त नहीं होता। अन्य सभी लाभ क्षणिक होते हैं, परंतु सत्संग का प्रभाव आत्मिक उत्कर्ष और भगवत्प्राप्ति तक जाग्रत रहता है।

जीवन के समस्त कष्टों, भ्रमों और क्लेशों का एकमात्र समाधान सत्संग है। यह विचारों का अमृत, भावों का रस और आत्मा का पोषण है। सत्संग से चित्त में कोमलता आती है। मन में स्थिरता आती है। भावों में भगवद्संपृक्ति आती है और आत्मा को परमशांति का अनुभव होता है। सत्संग ही वह महान साधन है, जिसके द्वारा धर्मशास्त्रों का ज्ञान, भगवत्प्रेम, सेवाभाव और चरित्र बल प्राप्त होता है। सत्संग की बहुत महिमा है। जीवन में सत्संग को सदैव बनाए रखना चाहिए। संयम अर्थात धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। सत्संग में ही जीवन का वास्तविक आनंद निहित है। जीवन का सर्वोत्तम लाभ सत्संग है। सत्संग सुगम है और इसके बिना भगवत्प्राप्ति नहीं हो सकती।

भगवान भाष्यकार ने तो सत्संग को आत्मोद्धार का मूल मंत्र बताया है। भगवान गौड़पादाचार्य स्पष्ट कहते हैं कि यदि सत्संग न हो, तो मनुष्य ज्ञान नहीं पा सकता और यदि ज्ञान न हो, तो वह अपने वास्तविक स्वरूप को कभी भी जान नहीं पाएगा।

सत्सत्वं हि मोक्षस्य कारणं परमं स्मृतम्।
असत्स तु नो कुर्यात्बुद्धिमान्सत्यवेधिनीम्॥

अर्थात सत्संग ही मोक्ष का परम कारण है।

विवेक और आत्मज्ञान की जाग्रति

बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी दुःसंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह विवेक और सत्य के मार्ग से विचलित कर देता है। 'विवेकचूड़ामणि' में सत्संग पर विचार करते हुए आद्यगुरु भगवान भाष्यकार ने तीन वस्तुएं संसार में दुर्लभ बताई हैं, जो केवल ईश्वर अनुग्रह से ही प्राप्त हो सकती है। मनुष्य शरीर, मोक्ष की तीव्र इच्छा (मुमुक्षुता) तथा महापुरुषों की संगति (सत्संग) और यही मोक्ष का द्वार है। अतः यदि दुर्लभ मानव शरीर व सत्संग प्राप्त हो भी जाए, तो उसका सार्थक उपयोग करना उससे भी अधिक दुर्लभ है, क्योंकि सत्संग से ही विवेक और आत्मज्ञान जाग्रत होता है।

सत्संग की महत्ता यज्ञ, दान, तीर्थ आदि से भी कई गुणा अधिक है। सत्संग ही हमें सन्मार्ग की ओर ले जाता है। मनुष्य को इस जीवनकाल में अपने 'अभीष्ट' का ज्ञान ही नहीं हो पाता है। वह इस माया रूपी संसार में अपनी अतृप्त कामनाओं की पूर्ति में भागता हुआ मृत्यु को प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन का एकमात्र 'अभीष्ट' आत्मज्ञान और भगवत्प्राप्ति है। सत्संग से ही हमें इस 'अभीष्ट' की सहज अनुभूति होती है और हम भगवत्प्राप्ति के कार्य में प्रवृत्त होते हैं।

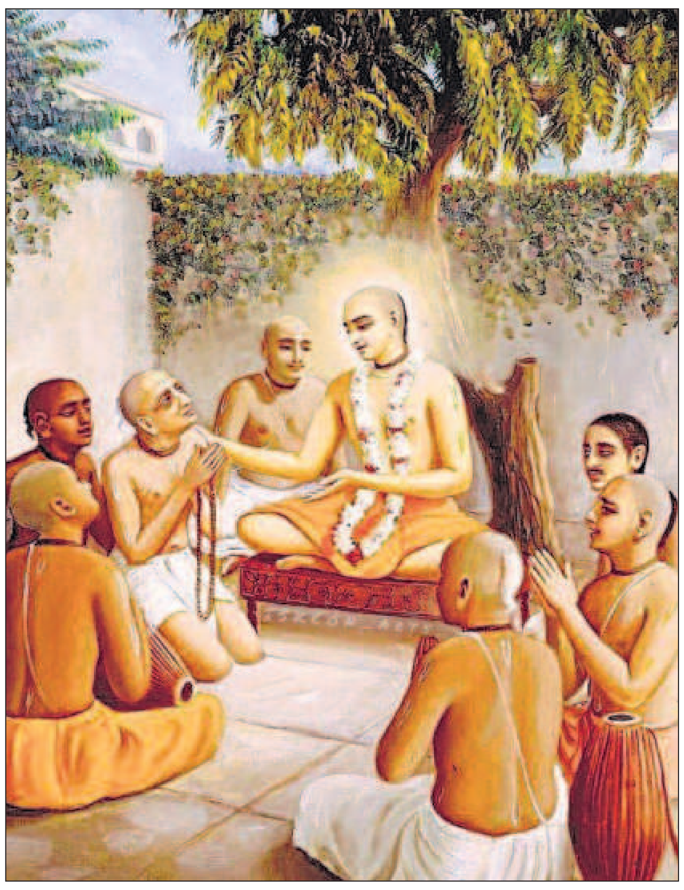

आध्यात्मिक शक्ति का विकास

सत्संग ही जीवन की सभी समस्याओं का एकमात्र निदान है। प्रभु के नाम-स्मरण तथा कीर्तन से महान आध्यात्मिक शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। अतः प्रत्येक क्षण भगवन्नाम स्मरण करते रहें, क्योंकि प्रभु के नाम का सतत और निर्बाध स्मरण मानसिक शांति, आत्मिक संतृप्ति, अंतःकरण की पवित्रता और सत-चित-आनंद प्रदान करने वाला है।

दिव्य उपलब्धियों की प्राप्ति

जीवन में अलौकिक परिवर्तन लाने हेतु एक ही मुख्य उपाय है- 'सत्संग,' जिससे विचार, भावना, स्वभाव, दैनिक जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ सकता है। हृदय में नवनीत-सी कोमलता, चित्त की अडोल स्थिरता, अलौकिक एवं रसपूर्ण भगवद्भाव, धर्मशास्त्रों का गूढ़ एवं व्यावहारिक ज्ञान, महापुरुषों के जीवन से प्रेरणाप्रद शिक्षाएं, आत्मस्वरूप का दिव्य साक्षात्कार, सेवा की शास्त्रीय प्रणाली का सुस्पष्ट बोध, संकीर्तन की भावविभोर परंपरा तथा सेवा-शृंगार के माधुर्य में वृद्धि- ये समस्त दिव्य उपलब्धियां केवल और केवल सत्संग रूपी ज्ञान-सरोवर में डुबकी लगाने से ही संभव हैं। सत्संग से ही हमारा विवेक जाग्रत होता है और विवेक से ही मोक्ष का द्वार खुलता है।

सत्संग ही जीवन की सभी समस्याओं का एकमात्र निदान है। प्रभु के नाम-स्मरण तथा कीर्तन से महान आध्यात्मिक शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। अतः प्रत्येक क्षण भगवन्नाम स्मरण करते रहें, क्योंकि प्रभु के नाम का सतत और निर्बाध स्मरण मानसिक शांति, आत्मिक संतृप्ति, अंतःकरण की पवित्रता और सत-चित-आनंद प्रदान करने वाला है।

ईद अल अजहा (28 मई)

हर मुमकिन मदद का पैगाम

ईद अल अजहा को भारतीय उपमहाद्वीप में बकरा ईद और बड़ी ईद भी कहा जाता है। यह मूलतः बालिगों का त्योहार है, क्योंकि इसकी सभी रस्में-रिवायतें घर के बड़े अर्थात जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा ही पूरी की जाती हैं।

हज का फर्ज कई नियमों में बंधा होता है, इसलिए कुर्बानी पर भी कई बंदिशें आयद हो जाती है। पहला नियम हज और कुर्बानी पर यह लागू होता है कि पैसा अपनी हलाल की कमाई का हो। इसमें उधार लेन-देन का कोई नियम नहीं है। आपको हज और कुर्बानी अपनी मेहनत की कमाई में करनी है। पहले आपको अपने लालचीपन तथा बेईमानी के स्वभाव की कुर्बानी देनी होगी, तभी आपकी कुर्बानी और हज कुबूल किया जाएगा।

हज और कुर्बानी में उधारी नहीं चलती, इसलिए प्रत्येक मुस्लिम न हज कर पाता है और न ही कुर्बानी, लेकिन हज का पर्व और ईद की खुशी तो पूरे समाज के लिए है। इस्लाम बांट कर खाने को तरजीह देता है, इसलिए कुर्बानी के सामान में तीन हिस्से बना दिए गए हैं।

एक जो कुर्बानी करता है उसका। दूसरा गरीब रिश्तेदारों का। तीसरा यतीम, माजोर और मजलूमों का। कहा गया है कि अपने समाज में ऐसे लोगों को तलाश कीजिए और उन तक उनका हक पहुंचाइए।

इस्लाम हर अवसर पर नमाज और इबादत को तरजीह देता है। सबसे पहले शहर की ईदगाह और बड़ी मस्जिदों में नमाज अदा की जाती है। उसके बाद कुर्बानी की सुन्नत पूरी की जाती है। जी हां! कुर्बानी हजरत इब्राहिम की सुन्नत की अदायगी है न कि फर्ज।

यह समझना जरूरी है कि सुन्नत पूरी करने की बंदिश नहीं है, मगर फर्ज की अदायगी जरूरी हैं। पांच फर्ज हैं- कलमा, नमाज, रमजान, जकात और हज।

पहले तीन फर्ज में कोई शर्त नहीं है। यह सभी अमीर-गरीब के लिए है, जिसमें माल-औ-दौलत की जरूरत नहीं होती, लेकिन जकात और हज में कुछ नियम लागू हो जाते हैं। जैसे कि कितनी दौलत हो, तो जकात जरूरी है। इसी प्रकार हज भी कई नियमों के बंधन में किया जाता है।

सिर्फ पैसा होने से आप हज के हकदार नहीं हो जाते हैं।

कुर्बानी का आध्यात्मिक पक्ष महत्वपूर्ण है। कुर्बानी अपने भीतर के पशुवत आचरण की भी देनी होती है। अपने श्रेष्ठ होने के अहंकार के साथ-साथ अपने धन एवं नस्लीय गर्व की मानसिकता की कुर्बानी भी इसमें शामिल है। हज उन पर फर्ज है, जो अपनी दुनियावी फर्जों को पूरा कर चुके हों। उन पर किसी प्रकार का कर्ज न हो, इसलिए लोग पहले अपने बच्चों को पढ़ाते-लिखाते हैं, उनकी शादी-ब्याह आदि से निबट कर ही हज पर जाते हैं।

ईद अल अजहा का साफ संदेश है -अपने समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद करना। उनके सुख और खुशी की वजह बनना। आप हज नहीं कर पाते, आप कुर्बानी नहीं कर पाते, कोई बात नहीं। अपनी हैसियत से किसी की मदद करना भी कुर्बानी के जज्बे में शामिल है। आपकी मीठी बोली तथा सहृदय व्यवहार भी इबादत का ही एक रूप है। आप छोटी-छोटी मदद कर, थोड़ी-थोड़ी खुशियां बांटकर भी अपने रब को राजी रख सकते हैं।

-मुख्तार अहमद

चिंतन

आत्मज्ञान से दूर करें दुविधा

सदियों से यही कहा गया है कि अपने आपको जानो, अपने आपको पहचानो। बाहरी रूप से हम अपने आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आत्मा के बारे में यही माना जाता है कि वह शरीर में एक चैतन्य शक्ति है, जो शरीर को चला रही है। शरीर हड्डी-मांस का एक पिंजड़ा है। जब आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है, तब शरीर मृत हो जाता है। आत्मा अजर-अमर-अविनाशी शक्ति है। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। यह सारा ज्ञान तो हमारे पास है, फिर जानने के लिए शेष क्या बचा है?

मनुष्य कई बार यह सोचता है कि हमारे जीवन में आत्मा के ज्ञान की क्या आवश्यकता है? क्या आत्मज्ञान की या आध्यात्मिकता की इस आधुनिक जीवनशैली में कोई उपयोगिता है? कोई प्राप्ति है? क्या इस ज्ञान से हमारी वर्तमान समस्याओं का हल प्राप्त हो सकता है? मानव अध्यात्म में रुचि तभी लेगा, जब उसे यह निश्चय हो जाएगा कि इससे बहुत बड़ी प्राप्ति होगी। वास्तव में 'स्व' की यथार्थ पहचान अथवा आत्मज्ञान की आवश्यकता इसलिए है, क्योंकि उससे मनुष्य अपनी सभी उलझनों एवं समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकता है।

इस संबंध में 'महाभारत' का एक प्रसंग है। महाभारत युद्ध के समय अर्जुन विषादग्रस्त होकर अपने शस्त्र छोड़कर भगवान से कहने लगे कि वह युद्ध नहीं करना चाहता। क्या तब उसे अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं था? जब भगवान उसके साथ थे और उसकी विजय निश्चित थी, तो क्या उसे भगवान पर भरोसा नहीं था? उस समय भगवान ने उसे कौन-सा ज्ञान दिया, जिससे वह अपने विषाद से मुक्त होकर युद्ध के लिए तैयार हो गया? भगवान ने सर्वप्रथम उसे आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा आत्म निश्चय में स्थित किया। उसे स्वधर्म का परिचय देकर उसकी अनंत शक्ति को उजागर करने की विधि बताई, जिससे वह एक सच्चा कर्मयोगी बनकर हर चुनौती का सामना सफलतापूर्वक कर सके।

जीवन भी एक संघर्ष है। यहां हर वक्त मनुष्य को युद्ध करना पड़ता है। जीवन के कई संघर्षों को वह पार कर जाता है, लेकिन जीवन की कई चुनौतियों के सामने वह अर्जुन की तरह विषादग्रस्त हो जाता है। ऐसी विषादपूर्ण मनःस्थिति के समय यह आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मज्ञान उसके मन का भय एवं तनाव दूर करके उसे निर्भय और शक्ति संपन्न बनाता है।

दुविधा में जकड़ा मानव भी अर्जुन की तरह 'क्या करूं, क्या न करूं' के पशोपेश में पड़ जाता है। परमात्मा द्वारा सिखाया गया राजयोग जितना अर्जुन के लिए उपयोगी था, उतना ही वह आज के तनावग्रस्त मानव के लिए भी उपयोगी है। आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा मनुष्य स्वयं की आत्मशक्ति को पहचान कर और उसके प्रयोग से वह कई प्रकार की समस्याओं का हल करके अपने मन को तनाव और भय से मुक्त कर सकता है।

-ब्रह्मा कुमारी चक्रधारी दीदी

आस्था-अनास्था
डॉ. प्रकाशचंद्र गंगराड़े

मस्तिष्क पर तिलक क्यों लगाते हैं?

मस्तिष्क पर तिलक क्यों लगाते हैं?
-मनोहर चोपड़ा, दिल्ली

ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मपर्व 26 में कहा गया है-

स्नानं दानं तपो होमो देवतापितृकर्म च।
तत्सर्वं निष्फलं याति ललते तिलकं बिना।
ब्राह्मणास्तिलकं कृत्वा, कुर्यात्सन्ध्यान्यत्रपणम्॥

अर्थात स्नान, होम, देव और पितृकर्म करते समय यदि तिलक न लगा हो, तो यह सब कार्य निष्फल हो जाते हैं। ब्राह्मण को चाहिए कि वह तिलक धारण करने के बाद ही संध्या, तर्पण आदि संपन्न करे। स्कंदपुराण में बताया गया है कि अनामिका से तिलक करने से शांति, मध्यमा से आयु, अंगूठे से स्वास्थ्य और तर्जनी से मोक्ष की प्राप्ति होती है।

इसके अलावा ब्राह्मण भोजन हेतु किया गया तिलक तीन अंगुली से पूरे ललाट पर, विष्णु की उपासना में ऊर्ध्व तिलक दो पतली रेखा में, शक्ति के उपासक स्वरूप दो बिंदी और महादेव के भक्त त्रिपुंड तीन रेखाओं का आड़ा तिलक लगाते हैं।

शास्त्रों के मतानुसार श्राद्ध, यज्ञ, जप, देवपूजन में त्रिपुंड धारण करने वाले व्यक्ति मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। उल्लेखनीय है कि हमारे मस्तिष्क (ललाट) से ही तिलक, टीका, बिंदिया का संबंध इसलिए जोड़ा गया है कि सारे शरीर का संचालन कार्य वही करता है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने शिवनेत्र की जगह को ही पूजनीय माना है।

ललाट के मध्य मानव शरीर का वह बिंदु है, जिससे निरंतर चेतन-अचेतन दोनों अवस्थाओं में विचारों का झरना प्रवाहित होता है। इसी को आज्ञाचक्र भी कहते हैं। हमारी दोनों भौंहों के बीच सुषुम्ना, इड़ा और पिंगला नाड़ियों के ज्ञान तंतुओं का केंद्र मस्तिष्क ही है, जो दिव्य नेत्र या तृतीय नेत्र के समान माना जाता है। इस पर तिलक लगाने से आज्ञा चक्र जाग्रत होकर व्यक्ति का ओज और तेज बढ़ता है।

(साभार : 'हिंदुओं के रीति रिवाज तथा मान्यताएं', पुस्तक महल, दिल्ली)

सप्ताह के व्रत-त्योहार

26 मई से 01 जून 2026 तक

26 मई (मंगलवार) : प्रथम (अधिक) ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि (दिन-रात)। भद्रा सायं 05.47 मिनट से।

27 मई (बुधवार) : प्रथम (अधिक) ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि प्रातः 06.22 मिनट तक पश्चात द्वादशी तिथि। भद्रा प्रातः 06.22 मिनट तक। पुरुषोत्तम (कमला) एकादशी व्रत।

28 मई (गुरुवार) : प्रथम (अधिक) ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी तिथि प्रातः 07.58 मिनट तक पश्चात त्रयोदशी तिथि। प्रदोष व्रत।

29 मई (शुक्रवार) : प्रथम (अधिक) ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी तिथि प्रातः 09.51 मिनट तक पश्चात चतुर्दशी तिथि।

30 मई (शनिवार) : प्रथम (अधिक) ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी तिथि प्रातः 11.58 मिनट तक पश्चात पूर्णिमा तिथि। भद्रा प्रातः 11.58 मिनट से रात्रि 01.06 मिनट तक। श्री सत्यनारायण व्रत। व्रत की पूर्णिमा।

31 मई (रविवार) : प्रथम (अधिक) ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा तिथि दोपहर 02.15 मिनट तक पश्चात प्रतिपदा तिथि। ज्येष्ठी योग। स्नान-दानादि की अधिक मासीय ज्येष्ठी पूर्णिमा। गंडमूल सायं 04.12 मिनट से।

01 जून (सोमवार) : द्वितीय (अधिक) ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा तिथि सायं 04.38 मिनट तक पश्चात द्वितीया तिथि। द्वितीय (अधिक) ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष प्रारंभ। जून मास प्रारंभ। गंडमूल विचार।

-पं. ऋभुकांत गोस्वामी

भेजें अपने सवाल

स्वर्ग-नरक की कल्पना का आधार क्या है?

पाप क्या है, पुण्य क्या है? धर्म क्या है, अधर्म क्या है? ईश्वर की आराधना कैसे करें? ऐसे सवाल अकसर हमारे मन में उठते हैं, पर इनका जवाब हमारे पास नहीं होता। मन-मस्तिष्क में आने वाले ऐसे ही सवालों के जवाब हमारे पैनल में शामिल धर्माचार्य आपको देंगे।

अपने सवाल हमें इस पते पर भेजें:
धर्मक्षेत्र, हिन्दुस्तान, 11वां तल,
द आइकॉन टॉवर, एफ सी-24 सी,
फिल्म सिटी, सेक्टर-16ए, नोएडा,
गौतम बुद्ध नगर-201301
(उत्तर प्रदेश)

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

मेष : मन परेशान हो सकता है। आत्मसंयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखें। माता-पिता की सेहत का ध्यान रखें। नौकरी में स्थान परिवर्तन हो सकता है।

वृष : आत्मसंयत रहें। अपनी भावनाओं को वश में रखें। नौकरी में कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है। परिश्रम अधिक रहेगा। कारोबार में भी भागदौड़ अधिक रहेगी।

मिथुन : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन परेशान भी रहेगा। माता की सेहत का ध्यान रखें। रहन-सहन अव्यवस्थित रहेगा। परिवार का साथ मिलेगा।

कर्क : मन परेशान रहेगा। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। वाहन के रख-रखाव तथा वस्त्रों आदि पर खर्च बढ़ेंगे।

सिंह : वाणी में मधुरता रहेगी। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। बौद्धिक कार्यों से आय में वृद्धि हो सकती है। सेहत का ध्यान रखें।

कन्या : मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा। नौकरी में कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है। परिश्रम अधिक रहेगा। मित्रों का सहयोग भी मिलेगा।

तुला : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु धैर्यशीलता बनाए रखें। नौकरी में बदलाव के अवसर मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में वृद्धि के साथ दूसरे स्थान पर जा सकते हैं।

वृश्चिक : मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें। माता-पिता का साथ मिलेगा। खर्चों की अधिकता रहेगी। भागदौड़ अधिक रहेगी।

धनु : मन अशांत हो सकता है। व्यर्थ के क्रोध से बचें। कारोबार में बदलाव हो सकता है। किसी मित्र का सहयोग भी मिल सकता है। लाभ के अवसर मिलेंगे।

मकर : आत्मसंयत रहें। अपनी भावनाओं को वश में रखें। नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। कार्यक्षेत्र में वृद्धि के साथ तरक्की के अवसर भी मिल सकते हैं।

कुंभ : किसी अज्ञात भय से परेशान हो सकते हैं। कारोबार में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। सचेत रहें। भागदौड़ अधिक रहेगी। खर्चों में वृद्धि होगी।

मीन : मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। कारोबार में वृद्धि होगी। भागदौड़ अधिक रहेगी। किसी मित्र का सहयोग भी मिल सकता है। वाहन सुख में वृद्धि हो सकती है।

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

26 मई, मंगलवार, **शक संवत् :** 05 ज्येष्ठ (सौर) 1948, **पंजाब पंचांग :** 12 ज्येष्ठ मास प्रविष्टे 2083, **इस्लाम :** 08 जिल्हिजा, 1447, **विक्रमी संवत् :** प्रथम (अधिक) ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि (दिन-रात), हस्त नक्षत्र (दिन-रात), सिद्धि योग रात्रि 03.11 मिनट तक पश्चात व्यतिपात योग, वणिज करण। चंद्रमा कन्या राशि में (दिन-रात)।

सूर्य उत्तरायण। सूर्य उत्तर गोल। ग्रीष्म ऋतु। अपराह्न 03 बजे से सायं 04.30 मिनट तक राहुकालम्। भद्रा सायं 05.47 मिनट से।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

कृपया यह बताएं कि बालकनी का प्रयोग वास्तु के अनुसार किस प्रकार करें?
-अतिशय कुमार, अयोध्या

■ अगर बालकनी पूर्व दिशा में है, तो उसमें छोटे-छोटे पौधे लगाएं। गमलों का रंग हल्का हरा हो, तो अच्छा रहेगा। यदि बालकनी उत्तर दिशा में है, तो इसमें छोटे पौधों के साथ कोई छोटा फाउंटेन भी लगा सकते हैं। यदि बालकनी पश्चिम दिशा में है, तो इसमें कम पौधे लगाएं। गमलों का रंग सफेद रखना ठीक रहेगा। यदि बालकनी दक्षिण दिशा में है, तो इसमें थोड़े भारी गमले रखें। गमलों का रंग लाल हो सकता है। इस दिशा में आप चाहें, तो थोड़े से पत्थर भी रख सकते हैं। कोई छोटे पहाड़ का रूप भी दे सकते हैं।

वर्ग पहेली : 8340

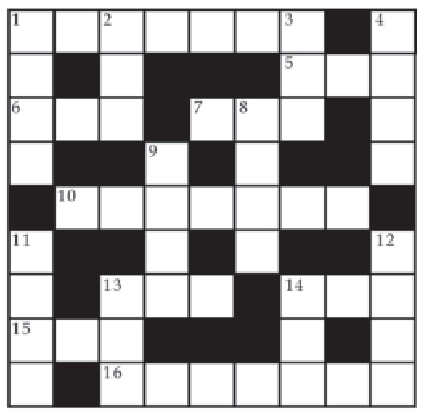

बाएं से दाएं
1. खोई हुई वस्तु को प्राप्त करना; ढूंढ निकालना; बाहर लाना (4,3)
5. एकाएक ऊपर से नीचे आना; टूटना; ढहना (3)
6. अभिभूत; तर्क सिद्ध बात से सहमत; विभोर होने वाला (3)
7. मुख से निकली बात; वाणी; इकरार; वादा (3)
10. अनशन करना; भोजन न लेना; व्रत करना (4,3)
13. एक पत्तेदार सब्जी; पालने वाला; रक्षक; संवर्धक; मानने वाला (3)
14. कुशल; जानकार; ज्ञाता; प्रवीण; सिद्धहस्त (3)
15. ठहराव; विश्रामस्थल (3)
16. तारीफ करना; प्रशंसा करना; बड़ाई करना (4,3)

ऊपर से नीचे
1. भटकाना; भ्रमित करना; भुलावा देना (4)
2. नाव में लगा पाल बांधने का मोटा व लंबा लट्ठा; नौका स्तंभ; कूपक; मथूल (3)
3. रोयों की लंबी भौंरी जो गरदन या पीठ पर होती है; सर्पिणी (3)
4. अस्वाभाविक; कृत्रिम; दिखावटी; नकली; बनाया हुआ; मानव रचित (4)
8. गरमी या रूखेपन के कारण तिड़कना; फटना; कली खिलना (4)
9. सेवा में नियुक्त रहने का समय; सेवावधि (4)
11. पढ़ाने वाला; शिक्षा देने वाला; गुरु (4)
12. ऊपर से टपकना; पानी गिरना; मेह पड़ना; वर्षा होना (4)
13. बरसात; वर्षा ऋतु (3)
14. मद के रूप में होने वाला; मद्य पदार्थ; आनंददायक; नशीला (3)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8339

सुडोकू : 8322

*मध्यम

	8						6	
5		9			3			1
				6	9		4	
	7	1		9				
		3	2		6	1		
				1		4	2	
	3		6	5				
7			4			3		6
	1						7	

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8321

5	4	6	1	8	3	7	2	9
3	7	9	5	6	2	8	1	4
1	8	2	4	7	9	5	3	6
4	3	8	9	2	6	1	7	5
7	2	5	8	4	1	9	6	3
9	6	1	3	5	7	4	8	2
8	1	3	6	9	5	2	4	7
6	5	7	2	1	4	3	9	8
2	9	4	7	3	8	6	5	1

प्रेरणा

रिश्ते ज्यादा समय और नजदीकी से नहीं, बल्कि प्यार और समझ से अनमोल बनते हैं। -अरस्तु

संपादकीय

हमारा कृषि प्रधान देश होना आयातों में नहीं झलकता

वर्ष 2013-14 में भारत कृषि उत्पादों का निर्यात आयात के मुकाबले 27 अरब डॉलर ज्यादा (15.5 अरब आयात और 43.3 अरब निर्यात) करता था। 2025-26 में यह अंतर घटकर मात्र 12.7 अरब (40.4 अरब के मुकाबले 53.1 अरब डॉलर) रह गया है। भारत में विदेश से वनस्पति तेल, दाल, फल और कच्चा कपास आता है। जरा सोचें, एक कृषि प्रधान देश में क्या उक्त सामग्रियों का डॉलर देकर आयात करना नीतिगत दोष नहीं है? सरकार मानती है कि किसानों को भारी पानी-खपत वाली फसलें जैसे गन्ना, गैर-बासमती चावल और गेहूं की जगह दलहन और तिलहन की खेती की ओर जाना चाहिए। कृषि वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि समान फसल और क्रॉप रोटेशन के अभाव में उत्पादकता/उर्वरता ही नहीं, भूजल-स्तर भी घट रहा है। लेकिन सरकार यह बात किसानों को समझा नहीं पा रही है। सरकार ने इस बार पुरानी गलती से बचते हुए आगामी खरीफ की 14 फसलों की एमएसपी घोषित करते हुए कोशिश की है कि कपास, दालों और तिलहन उत्पादों पर एमएसपी ज्यादा दी जाए, जबकि चावल पर मात्र 3% वृद्धि की है। मोटे अनाज की खेती प्रोत्साहित करने की कोशिश भी की गई है। लेकिन चूंकि दलहन और तिलहन पाला/रोग से जल्द खराब होते हैं, लिहाजा जब तक इनकी बीमा और फसल खरीद की गारंटी नहीं होगी, समस्या पूर्ववत ही बनी रहेगी।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com

कोई गुरु न मिले तो हनुमान जी को अपना गुरु बनाइए

दुनियादारी के प्रति भ्रम हो तो उसका निपटारा हो भी जाता है, लेकिन जब भ्रम ईश्वर के प्रति होता है तो पूरा जीवन गड़बड़ा सकता है। काकभुशुंडिजी ने एक पंक्ति बोली- निर्गुन रूप सुलभ अति सगुन जान नहिं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ, सहज ही समझ में आ जाने वाला है, लेकिन गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के मन में भी भ्रम हो जाता है। ईश्वर का चरित्र दो प्रकार का है- एक सुगम है, एक अगम है। सुगम यानी सरल, सुविधाजनक और अगम का अर्थ होता है पहुंच से बाहर, समझ से परे, असीम। जब कभी जीवन में ईश्वर के प्रति ऐसी स्थिति हो तो सबसे सरल उपाय है किसी गुरु की शरण में चले जाना। और कोई गुरु न मिले तो हनुमान जी को गुरु बनाइए और हनुमान जी से जुड़कर इस प्रकार के भ्रम से अपने आप को दूर कर लीजिए।

• Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

स्पीक-अप • वस्त्र उद्योग की तस्वीर बदल रही है...

अंग्रेजों ने जो हमसे छीना, उसे हम धीरे-धीरे फिर पा चुके हैं

टेक्सटाइल्स

मिन्हाज मर्चेंट
लेखक, प्रकाशक और संपादक
mmleditorial@gmail.com

18वीं सदी में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 25% हिस्सा हुआ करता था। वस्त्र उद्योग उसकी समृद्धि का केंद्रीय आधार था। भारतीय कपास पूरी दुनिया पर छाई हुई थी। सूती वस्त्रों का निर्यात यूरोप, अमेरिका और एशिया के बाजारों में होता था। फिर ब्रिटिश आए। उन्होंने सूरत में व्यापारिक बंदरगाह स्थापित किए और छोटी-छोटी फैक्ट्रियां बनाईं। 1757 के बाद, जब रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया, ब्रिटिशों ने भारत के वस्त्र उद्योग पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। कुछ ही वर्षों में कपास व्यापार का विनाश शुरू हो गया।

अंग्रेज लंबे समय से सूती वस्त्रों की लोकप्रियता को लेकर चिंतित थे। 1700 तक यूके एक देश के रूप में अस्तित्व में नहीं था। उस समय इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दो स्वतंत्र स्टेट थे, जिनके अपने अलग कानून थे। 1707 में जाकर ही ये दोनों एकजुट होकर यूनाइटेड किंगडम बने। उससे बहुत पहले ही इंग्लैंड ने कैलिको एक्ट (1700) पारित कर दिया था। इस कानून के तहत भारत से आने वाले मुद्रित या रंगे हुए सूती वस्त्रों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये वस्त्र इंग्लैंड में इतने लोकप्रिय हो चुके थे कि अंग्रेजों के वस्त्र उद्योग को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। 1757 में बंगाल पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद ब्रिटिशों ने भारत को क्रमशः गैर-औद्योगीकृत करना शुरू किया, जिसकी शुरुआत भारत के फलते-फूलते वस्त्र उद्योग से हुई।

ब्रिटेन ने भारत से होने वाले निर्यात पर 70 प्रतिशत से अधिक शुल्क लगा दिया। यह स्थिति कुछ हद तक ट्रम्प के टैरिफ की याद दिलाती है। लेकिन लगभग 300 वर्ष पहले अमेरिका स्वयं ब्रिटेन का उपनिवेश था। ब्रिटेन ने अपने पुराने अमेरिकी उपनिवेश का उपयोग अपने नए भारतीय उपनिवेश के शोषण के लिए किया।

अमेरिका के दक्षिणी हिस्से में होने वाली कपास की खेती से भारत में होने वाले शुल्क-मुक्त आयात ने कृषि को केवल कच्चे कपास के उत्पादन की ओर धकेल दिया। उसी समय ब्रिटिश कारखानों में निर्मित तैयार वस्त्र बड़ी मात्रा में भारत में आने लगे। ईस्ट इंडिया कम्पनी ने आयात शुल्क को शून्य कर दिया। भारतीय बुनकर प्रतिस्पर्धा में पिछड़े और दिवालिया हो गए।

अपने भारतीय उपनिवेश से प्राप्त सस्ते कच्चे माल के बल पर 1760 के दशक में ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति ने गति पकड़ी। भारतीय किसानों, जमींदारों और श्रमिकों से वसूले गए कर-राजस्व ने इंग्लैंड में नई मशीनों के विकास को वित्तपोषित किया। औद्योगिक क्रांति ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को भी मजबूत बनाया। भारत में इसका ठीक उलटा हुआ। रोजगार समाप्त होने लगे। वस्त्र-उद्योग के पारम्परिक केंद्र- सूरत, ढाका और मुर्शिदाबाद कठिनाइयों, जनसंख्या-ह्रास और समय-समय पर आने वाले अकालों के शिकार बने, जिनमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई।

अब 2026 पर आइए। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की समाप्ति के लगभग 79 वर्ष बाद स्थिति पूरी तरह उलट चुकी है। भारत एक बार फिर दुनिया के अग्रणी वस्त्र और परिधान निर्माताओं में शामिल है। भारतीय वस्त्र बाजार अब 250 अरब डॉलर (24 लाख करोड़ रुपये) से अधिक की बिक्री का प्रतिनिधित्व करता है। भारत एक बार फिर दुनिया का सबसे बड़ा कपास और जूट उत्पादक भी है, जिसकी वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी 35 प्रतिशत है। कपास उद्योग प्रत्यक्ष रूप से 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 10 करोड़ अन्य लोगों को रोजगार देता है।

औपनिवेशिक बेड़ियों से मुक्त होने के बाद भारतीय टेक्सटाइल्स सेक्टर आने वाले वर्षों में एक उभरते हुए निर्णायक उद्योग के रूप में दिखाई देता है। ईयू और यूके के साथ मुक्त व्यापार समझौते निर्यात को नई गति दे सकते हैं, क्योंकि शुल्क लगभग शून्य तक घट सकते हैं- यह पूर्ववर्ती सदियों की स्थिति का उलटा होगा।

ब्रिटिश राज ने भारत के कपड़ा उद्योग को ध्वस्त कर दिया था, लेकिन आज फिर हम दुनिया का सबसे बड़ा कपास और जूट उत्पादक बन चुके हैं। कपास उद्योग करोड़ों लोगों को रोजगार देता है। पर हम इससे भी बेहतर कर सकते हैं।

लेकिन एक टेक्सटाइल्स-पावरहाउस के रूप में भारत की प्रगति के बावजूद वह वस्त्रों के निर्यात में अभी पीछे है। चीन 300 अरब डॉलर से अधिक के साथ दुनिया का सबसे बड़ा वस्त्र निर्यातक है। फिर बांग्लादेश (49 अरब डॉलर), वियतनाम (42 अरब डॉलर), तुर्किये (39 अरब डॉलर) और भारत (38 अरब डॉलर) हैं। सरकार की उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना ने घरेलू उत्पादकों की मदद की है। वर्तमान में दुनिया के पांचवें सबसे बड़े वस्त्र निर्यातक के रूप में भारत उस स्थिति में पहुंच चुका है, जहां वह उचित नीतियों के साथ 2030 तक चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्यातक बनकर उभर सकता है। तीन सौ वर्षों बाद वस्त्र उद्योग की धारा एक बार फिर भारत के पक्ष में मुड़ती दिखाई दे रही है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

दूरदृष्टि • अपनी प्रासंगिकता गंवा रहा है संयुक्त राष्ट्र

क्या दुनिया में आज ऐसी कोई संस्था नहीं, जो दखल दे सके?

यूएन

डॉ. अरुणा शर्मा
इस्पात मंत्रालय की पूर्व सचिव
arunasharma1908@gmail.com

विश्व युद्धों के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन) की स्थापना इसलिए की गई थी, ताकि भविष्य में हिरोशिमा-नागासाकी जैसी विनाशकारी घटनाओं और व्यापक पैमाने पर होने वाले युद्धों को रोकने के लिए बातचीत का मंच तैयार किया जा सके। इसके कुछ सर्वमान्य सिद्धांतों में क्षेत्रों का अधिग्रहण न करना, नागरिकों, रेडक्रॉस और सहायता एजेंसियों को हमले के क्षेत्र से बाहर रखना और उन्हें पहुंच प्रदान करना शामिल था।

लेकिन यूक्रेन, ईरान और लेबनान में जो हुआ, वो इन सिद्धांतों के बिलकुल उलट था। यूएन, नाटो और ब्रिक्स सदस्य देशों ने सभी पक्षों को बातचीत की मेज पर लाने के लिए दखल जरूर दिया, लेकिन यहां तक पहुंचने में उन्हें कई महीने और साल लग गए। क्या आज यह आवश्यक नहीं कि ऐसी स्थिति न बने, इसके लिए यूएन को सशक्त बनाए जाए? यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सतत विकास लक्ष्यों में बाधा न आए।

यूं तो एक चार्टर के जरिए बने यूएन का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, मानवाधिकारों को बढ़ावा देना, सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, पर्यावरण की रक्षा करना और आपात स्थितियों में मानवीय सहायता प्रदान करना है। यह संघर्षों को रोकने, अंतरराष्ट्रीय कानून बनाए रखने और सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वैश्विक प्रयासों के समन्वय जैसे कार्य भी करता है। लेकिन रूस-यूक्रेन युद्ध, ईरान-इजराइल युद्ध, गाजा, लेबनान आदि में यूएन को अपने इन उद्देश्यों की प्राप्ति में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालात ऐसे बन गए कि यूएन के लिए मानवीय सहायता सुनिश्चित करना तक कठिन हो गया और युद्ध-अपराधों की निंदा भी यूएन चार्टर के बजाय देशों के दबदबे के अनुसार की गई। ऐसे में इस संगठन को फिर से ताकतवर बनाने के लिए हमें शुरुआत से विचार करने की जरूरत है।

रूस-यूक्रेन युद्ध में यूएन महज कागजी कार्रवाई तक सीमित रहा था। उसने रूस की बिना शर्त-वापसी के प्रस्ताव पारित किए, शांति का फॉर्मूला पेश करने का प्रयास किया। लेकिन यह फॉर्मूला हमले के 4 साल बाद आया, इसलिए प्रभावहीन रहा। मानवीय सहायता सुनिश्चित करने में भी वह विफल रहा, क्योंकि प्रभावितों तक पहुंचने से उसे बार-बार रोका गया। भारी जनहानि होने के बाद जाकर वह 1.3 करोड़ प्रभावितों तक मदद पहुंचा सका। यूएन की इस मूकदर्शक भूमिका के कारण 2025 यूक्रेनवासियों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ।

फिर 2026 में इजराइल और ईरान के बीच नया मोर्चा खुल गया। इसने वैश्विक व्यापार मार्गों और आवागमन को बाधित किया। मानवाधिकारों का पूर्णत: उल्लंघन हुआ, जिसमें शुरुआत में ही ईरान में स्कूली छात्राओं पर हमला हुआ और लेबनान में भी ऐसी ही घटनाएं सामने आईं। यूएन के अन्य सदस्य भी तभी सक्रिय हुए, जब ऊर्जा सप्लाई रुक गई। यूएन महासचिव के बयान भी संयम रखने जैसी अपील तक सीमित रहे, जबकि उद्देश्य महज अपील करना नहीं था, बल्कि सदस्य देशों को एकजुट होकर यह सुनिश्चित करना था कि यूएन के स्थापित मानदंडों का उल्लंघन न हो। ऐसे में क्या फिर से विचार करने जरूरत नहीं कि यूएन के पास स्वयं की ताकत होनी चाहिए?

यूएन का लक्ष्य मानवाधिकार उल्लंघन रोकना और समृद्धि लाना है। लेकिन युद्धों ने इन प्रयासों को बाधित किया और देशों को महंगाई और गरीबी के दुष्चक्र में धकेल दिया है। व्यापार और सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है। नागरिकों की जानें जा रही हैं और उन्हें गरीबी में धकेला जा रहा है। इस सब का दीर्घकालिक असर होगा। अंतरराष्ट्रीय कानून भी इन युद्धों के शिकार बने हैं। बड़ी चिंता इस संघर्ष के अन्य क्षेत्रों में फैलने की है।

आवश्यकता है कि यूएन सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन हो। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका के साथ ईरान, भारत, द. अफ्रीका को स्थायी सदस्य बनाया जाए। महासभा द्वारा अस्थायी सदस्यों को चुने जाने की व्यवस्था भी जारी रहनी चाहिए।

आज फिर से यूएन और उसकी संस्थाओं को मजबूत करने की जरूरत महसूस हुई है। पहला कदम दक्षिण अफ्रीका द्वारा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में मानवीय अपराधों के खिलाफ मुकदमा शुरू करना था। इससे संघर्ष को बड़े युद्ध में बदलने से रोकने के लिए कुछ अवसर मिला, लेकिन यह भी 'कागजी शेर' ही साबित हुआ। न कोई संकल्प दिखा, न ठोस कार्रवाई की गई। हां, कूटनीतिक संवाद जरूर जारी रहे। लेकिन क्या अब अंतरराष्ट्रीय कानूनों को मनवाने के लिए यूएन को और ताकतवर बनाने की जरूरत नहीं है?

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए **QR कोड** को स्कैन करें।

दैनिक भास्कर — अब आप NYT के सभी आर्टिकल **DB एप** पर हर मंगलवार पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें डीबी एप।

© The New York Times

दैनिक भास्कर से विशेष अनुबंध के तहत

इस हफ्ते चर्चा में...

ईरान युद्ध से अमेरिकी बैंकों का कारोबार बढ़ा

4.75 लाख करोड़ रुपए

की ट्रेडिंग की है यूएस के जेपी मोर्गन, सिटी बैंक सहित 6 बड़े बैंकों ने पहली तिमाही में। युद्ध के कारण बैंकों को अधिक फीस मिली।

19 हजार करोड़ रुपए

अनुदान दे रही है अमेरिकी सरकार आईबीएम सहित नौ क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित कंपनियों को।

5.52 लाख करोड़ रुपए

का मुनाफा कमाया है चिप कंपनी एनवीडिया ने साल की पहली तिमाही में। यह पिछले साल से 200% अधिक है।

टेक्नोलॉजी — एआई के कारण किस तरह की नौकरियों में अवसर बन रहे हैं और लोग इसे किस नजर से देखते हैं, इसके फायदे-नुकसान...

नौकरियों को एआई से उतना गंभीर खतरा नहीं, जितना अनुमान जताया गया है : पिचई

केविन रूज, केसी न्यूटन और व्हिटनी जोन्स

गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स के टेक्नोलॉजी पॉडकास्ट 'हार्ड फोर्क' के होस्ट्स के साथ बातचीत की। इस दौरान गूगल सर्च के भविष्य, एआई एजेंट्स के इस्तेमाल और कॉलेज ग्रेजुएट्स को लेकर चर्चाएं हुईं। पिचई ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) बेहद तेजी से दुनिया को बदल रहा है। ऐसे में लोगों का चिंतित होना स्वाभाविक है। दरअसल लोग इतने बड़े तकनीकी बदलाव को समझने और उसके अनुरूप ढलने के लिए अभी तैयार नहीं हैं। एक आंकड़ा सामने आया कि केवल 16% लोग ही एआई को ज्यादातर अच्छा मानते हैं, जबकि 35% लोग इसे खराब मानते हैं। इस पर पिचई ने कहा कि टेक कंपनियों की यह जिम्मेदारी है कि वे एआई के फायदे लोगों तक पहुंचाएं और दिखाएं कि यह तकनीक जीवन को कैसे बेहतर बना सकती है। एआई से नौकरियां खत्म होने और काम बदलने की आशंकाओं पर उन्होंने कहा कि वास्तविक स्थिति उतनी गंभीर नहीं होगी, जितना अनुमान है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि हर पीढ़ी में भविष्य को लेकर चिंताएं होती हैं, लेकिन आखिरकार वही पीढ़ी बेहतर दुनिया बनाती है।

एंट्री लेवल के युवाओं की क्षमताएं बढ़ेंगी

एंट्री-लेवल युवाओं के भविष्य पर बात करते हुए पिचई ने कहा कि एआई लोगों की क्षमताओं को बढ़ाएगा। जैसे स्प्रेडशीट आने से काम करने का तरीका बदला था, वैसे ही एआई भी कई लोगों के लिए नई शुरुआत का रास्ता खोलेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में दुनिया में पहले से कहीं ज्यादा लोग कोडिंग कर पाएंगे। पिचई के मुताबिक एआई डॉक्टरी जैसे पेशों में भी बड़ा बदलाव ला सकता है। अभी डॉक्टरों का बहुत ज्यादा समय कागजी कार्रवाई और तकनीकी प्रक्रियाओं में चला जाता है, एआई से इस समय की बचत होगी, जिससे डॉक्टर बचे हुए समय को मरीजों के साथ बिता पाएंगे।

एआई से साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ की मांग बढ़ी, यूएस में 76 करोड़ तक का पैकेज

केट कॉन्गर

एआई के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञों की मांग तेजी से बढ़ रही है। जॉब सर्च प्लेटफॉर्म ग्लासडोर के मुताबिक इस साल की पहली तिमाही में साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी जॉब में 11% की बढ़ोतरी हुई है। बड़ी वजह एआई आधारित कोडिंग टूल्स का तेजी से इस्तेमाल माना जा रहा है, जिससे सिस्टम में बग्स व सुरक्षा खामियों का खतरा बढ़ रहा है।

टेक कंपनियों के कर्मचारी अब बड़े पैमाने पर एआई से कोड जनरेट कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे काम की गति तो बढ़ती है, लेकिन कई बार सॉफ्टवेयर में कमजोरियां भी पैदा हो जाती हैं। प्रमुख एआई कंपनियां पहले ही चेतावनी दे चुकी हैं कि एंथ्रोपिक के 'मायथोस' जैसे मॉडल का इस्तेमाल सॉफ्टवेयर की कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए किया जा सकता है। लिंक्डइन की चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अफसर ली किसनर के मुताबिक सिक्योरिटी विशेषज्ञों की मांग लगातार बढ़ रही है। एआई का असर केवल साइबर सिक्योरिटी तक सीमित नहीं है। प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल और एआई इंडस्ट्री में भी नई नौकरियां पैदा हो रही हैं। नए कॉलेज ग्रेजुएट्स के लिए एआई इंजीनियर की मांग सबसे ज्यादा बताई जा रही है। गूगल

के वाइस प्रेसिडेंट निक फॉक्स का कहना है कि पहले की तुलना में अब ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जरूरत है। हालांकि दूसरी तरफ टेक इंडस्ट्री में छंटनी भी हो रही है। मेटा ने पिछले सप्ताह करीब 8 हजार कर्मचारियों की छंटनी की। अमेजन हाल में 16 हजार नौकरियां खत्म कर चुकी है। स्ट्राइप, स्नैप और ब्लॉक जैसी कंपनियों ने भी हजारों कर्मचारियों को निकाला है। एंथ्रोपिक के 'मायथोस' और बाद में ओपनएआई के जीपीटी 5.4 साइबर मॉडल के आने के बाद साइबर सिक्योरिटी हायरिंग में और तेजी आई है। सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव्स का पैकेज 66 से 76 करोड़ तक पहुंच गया है।

© The New York Times

इमिग्रेशन — अमेरिकी सरकार की नई नीतियों से मुश्किल में हजारों इमिग्रेंट्स

ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन से पहले मूल देश लौटना होगा

क्रिस्टीना मोरालस

अमेरिकी सरकार की नई नीति ने हजारों इमिग्रेंट्स को मुश्किल में फंसा दिया है। हाल ही में सिटीजनशिप और इमिग्रेशन सर्विसेस एजेंसी ने कहा है कि ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले लोगों को पहले अपने मूल देश लौटना पड़ेगा। अब आवेदक और इमिग्रेशन वकील समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बदलाव से स्थायी निवास की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एजेंसी का कहना है कि केवल असाधारण परिस्थितियों में ही अमेरिका में पहले से रह रहे लोगों को परमानेंट रेसीडेंस की मंजूरी दी जाएगी। अमेरिका में स्थायी तौर पर बसने के इच्छुक किसी अन्य व्यक्ति को अपने गृह देश में अमेरिकन कौन्सुलेट में आवेदन करना पड़ेगा।

इमिग्रेशन वकील चार्ल्स कुक ने कहा कि बदलाव उन लोगों के लिए खासतौर से चिंताजनक है, जिन्होंने अमेरिकी नागरिकों से शादी की है और वे स्थायी निवास चाहते हैं। ऐसे इमिग्रेंट्स को ग्रीन कार्ड लेने से पहले अपने इमिग्रेशन दर्जे को तय करने की जरूरत रहती है और आमतौर पर वे अमेरिका में रहते हुए ऐसे मामलों को निपटा लेते हैं। कुक कहते हैं, यह इमिग्रेशन की गति धीमी करने और इमिग्रेशन को इतना जटिल और असुविधाजनक बनाने का प्रयास है कि आप अपने देश लौट जाएं।

2024 में 14 लाख लोगों को ग्रीन कार्ड मिला

सैन फ्रांसिस्को में यूएस इमिग्रेशन सर्विस का ऑफिस।

इमिग्रेशन वकीलों और उनके समर्थक संगठनों का कहना है कि नए नियमों से ग्रीन कार्ड आवेदन कम होंगे। 2024 में 14 लाख ग्रीन कार्ड जारी किए गए थे। कार्ड पाने वाले आठ लाख से अधिक लोग अमेरिका में पहले से हैं और प्रक्रिया के तहत उनका इमिग्रेशन दर्जा बदला गया है।

नेशनल इमिग्रेशन लॉ सेंटर में कानूनी रणनीति के वाइस प्रेसिडेंट एफरेन ओलिवरेस का कहना है, नई नीति का उद्देश्य ग्रीन कार्ड प्रक्रिया को अस्त-व्यस्त करना है। ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पूरी होने तक अधिकतर आवेदकों को अपने परिवारों के साथ अमेरिका में रहने की अनुमति है, लेकिन अब देश में बने रहना अपवाद होगा। ओलिवरेस कहते हैं, पहले कई बार डिपोर्ट किए जा चुके या गंभीर आपराधिक इतिहास जैसी असाधारण परिस्थितियों में किसी को अपने देश से आवेदन के लिए कहा जाता था।

कार्रवाई के भय से नाम न छापने की शर्त पर कुछ इमिग्रेंट्स ने कहा कि वे भ्रमित और चिंतित हैं कि इस बदलाव का उनके या उनके पार्टनर के आवेदनों के लिए क्या मतलब होगा। इमिग्रेंट्स की मदद करने वाले एक गैरलाभकारी संगठन इमिग्रेशन प्रैक्टिस के मैनेजिंग डायरेक्टर कार्ला ओस्टोलेजा कहते हैं, इस परिवर्तन का असर तुरंत तो नहीं लेकिन बहुत ज्यादा महसूस किया जाएगा।

© The New York Times

फिलिस्तीनियों पर हिंसा

इजराइल के राष्ट्रपति ने यहूदियों पर निशाना साधा

इसाबेल कर्शनर

इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हरजोग ने इजराइली समाज में बढ़ती हिंसा और अमानवीय व्यवहार पर गंभीर चिंता जताई है। यरूशलम एकता पुरस्कार समारोह में उन्होंने अधिकृत वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ यहूदी हिंसा और हिरासत में कैदियों के साथ दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाया। हरजोग ने कहा कि उनकी इच्छा सिर्फ एकता पर बोलने की थी, लेकिन कुछ इजराइलियों की कार्रवाइयों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की आलोचना कराई है। उनके मुताबिक समाज का बड़ा हिस्सा अब हिंसा से स्तब्ध नहीं होता, जबकि कुछ लोग इसे हल्के में लेने लगे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि उग्रपंथी और अमानवीय व्यवहार सामान्य होता जा रहा है और इसे समाज के कुछ वर्ग खुले तौर पर समर्थन दे रहे हैं। राष्ट्रपति ने इजराइल में अरब अल्पसंख्यकों के बीच बढ़ती गन हिंसा और ईसाइयों-मुसलमानों के खिलाफ उग्रपंथियों के शर्मनाक और बेहूदा व्यवहार की भी आलोचना की।

© The New York Times

युद्ध — ईरान के पास 11 टन से ज्यादा परमाणु ईंधन

ट्रम्प-ईरान समझौता : फिलहाल राहत, मुश्किल मुद्दे अब भी बाकी

डेविड ई. सैंगर और टायलर पेजर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जिस समझौते को ऐतिहासिक बता रहे हैं, वह अभी न शांति समझौता है, न परमाणु और न ही मिसाइल समझौता। खुद ट्रम्प मान चुके हैं कि यह अभी पूरी तरह तय भी नहीं हुआ है। इसके बावजूद इस अस्थायी समझौते से दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद अहम होर्मुज स्ट्रेट दोबारा खुलने की उम्मीद बढ़ गई है।

अमेरिका और ईरान के बीच यह समझौता ऐसे समय हुआ है, जब दोनों देशों के बीच तनाव खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका था। यदि ट्रम्प और ईरान के सर्वोच्च नेता अंतिम मसौदे को मंजूरी देते हैं, तो दुनिया के करीब एक-चौथाई तेल की आपूर्ति वाला समुद्री रास्ता फिर खुल सकता है।

अमेरिका में रिपब्लिकन नेताओं को डर था कि तेल संकट गहराने पर नवंबर के मध्यावधि चुनावों से पहले पेट्रोल 4.50 डॉलर प्रति गैलन तक पहुंच सकता है। वहीं ईरान की अर्थव्यवस्था भी तेल आय में गिरावट से दबाव में थी। ऐसे में दोनों देशों ने टकराव जारी रखने के बजाय पीछे हटना बेहतर समझा।

हालांकि ट्रम्प का मौजूदा रुख उनके पुराने बयान से बिल्कुल अलग है। 11 हफ्ते पहले उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ 'बिना शर्त आत्मसमर्पण' के अलावा कोई समझौता नहीं होगा। अब उनका कहना है कि बातचीत 'सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रही है।'

फिलहाल सबसे कठिन मुद्दे टाल दिए गए हैं। ईरान के पास अब भी 11 टन से ज्यादा परमाणु ईंधन है, जिसमें करीब 970 पाउंड ऐसा यूरेनियम शामिल है, जो बम बनाने के स्तर के करीब माना जाता है। मिसाइल कार्यक्रम पर भी कोई सहमति नहीं बनी है। अमेरिका में ट्रम्प को अपने ही दल के नेताओं की आलोचना झेलनी पड़ रही है, जबकि विशेषज्ञ इसे जरूरत की शांति बता रहे हैं।

© The New York Times

खपत का पैटर्न बदला • विदेश यात्रा पर भारतीयों का खर्च 8 साल में पांच गुना, प्रोसेस्ड फूड पर पढ़ाई के मुकाबले तीन गुना ज्यादा तेजी से बढ़ा, ये वित्तीय बोझ बढ़ा रहे

कर्ज की किस्तें आय से 6 गुना तक ज्यादा बढ़ीं, परिवारों की बचत 4% से भी कम

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

भारतीय परिवारों के खर्च का तौर-तरीका बदल रहा है। लेकिन यह बदलाव उतना सुखद नहीं है, जितना एकबारगी नजर आता है। आय के मुकाबले खर्च ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। दो विपरीत तस्वीरें उभर रही हैं। एक तरफ महंगे आईफोन और विदेशी उड़ानें हैं और दूसरी तरफ सिकुड़ती बचत और ईएमआई का बढ़ता बोझ है। कोटक म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट 'द ग्रेट कंजम्पशन शिफ्ट' बताती है कि पिछले 8 साल में ग्रामीणों का डेटा बिल उनकी मजदूरी से तीन गुना तेज बढ़ा। पिछले 7 में से 5 साल ईएमआई की रफ्तार तनख्वाह से 6 गुना तक ज्यादा तेज रही। थाली में अनाज का हिस्सा घटा और शेयरों की रिटेल ट्रेडिंग में (2022-25 के बीच) ₹2.87 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। इस बदलाव का सबसे ज्यादा नुकसान मध्यम वर्ग झेल रहा है।

स्थायी ट्रेंड: ढाई दशक से खाने पर खर्च का अनुपात लगातार घट रहा

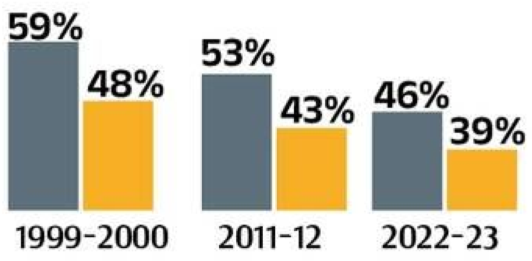

▪ **नोट:** भोजन पर खर्च कुल घरेलू बजट में हिस्सेदारी के तौर पर। ▪ **अनाज पर खर्च की** हिस्सेदारी हिस्सा ग्रामीण में 22% से घटकर 5%, शहरों में 12% से घटकर 4% रह गया।

घरेलू बजट: प्रोसेस्ड फूड पर खर्च 4%, एजुकेशन पर 1.5% ही बढ़ा

कुल घरेलू खर्च में अनाज की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 9% घटी, लेकिन गाड़ियों पर 3% बढ़ी

खर्च की श्रेणी	घटा/बढ़ा
बेवरेज, प्रोसेस्ड फूड	▲ 4.2%
मोबाइल, गैजेट्स	▲ 3.6%
गाड़ियां	▲ 3.1%
किराया	▲ 2.1%
शिक्षा	▲ 1.5%
अनाज	▼ 8.8%
दालें	▼ 1.6%

नए शौक: ऑनलाइन शॉपिंग, गैजेट, ओटीटी पर खर्च तेज रफ्तार से बढ़े

बिजनेस	ग्रोथ
मीशो की आय	106%
ब्लिंकिट ऑर्डर वैल्यू	95%
हियरेबल्स मार्केट	52%
एपल इंडिया की आय	47%
ड्रीम11 की आय	45%
ओटीटी सब्सक्राइबर	40%
एसआईपी निवेशक	22%

नोट: सालाना कंपाउंडेड ग्रोथ 2019 से 2026 के बीच, ब्लिंकिट के आंकड़े 2025-26 के

एपल vs एचयूएल बड़ा संकेत

वित्त वर्ष 2020-21 में भारत में एपल की आय हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल) से आधी थी। 2025-26 में एपल ने एचयूएल को लगभग 2 गुना पीछे छोड़ा। एपल इंडिया को 1,42,500 करोड़ रुपए आय के मुकाबले एचयूएल की आय 64,468 करोड़ रुपए ही रही।

चुनौती: 7 में से 5 साल ईएमआई आय से कई गुना ज्यादा बढ़ी

▪ **2022-23 में** ईएमआई का बोझ 25% बढ़ा, पर आय 8.3% ही बढ़ पाई।
▪ **2024-25 में** ईएमआई का बोझ 13.4% बढ़ा, लेकिन इस बीच आय सिर्फ 2.1% ही बढ़ी।
▪ **2024 में** परिवारों की वित्तीय बचत जीडीपी की 3.9% रह गई, जो 2021 में 11.2% थी।

दिलचस्प: विदेश यात्रा पर खर्च 2018 के मुकाबले 450% बढ़ा

फरवरी 2026 में विदेश यात्रा पर भारतीयों का औसत खर्च 1.45 लाख करोड़ रुपए रहा। यह 2018 के मुकाबले करीब 450% ज्यादा है। यही नहीं, बीते 3 साल में विदेशी निवेश (शेयर/बॉन्ड) भी 7.3 गुना बढ़ा है। यानी दूसरे देशों में दिलचस्पी बढ़ी है।

फासला: अमीरों की आय मध्यम वर्ग से तीन गुना तेजी से बढ़ी

▪ **शहरी** अमीर तबके की आय सालाना 18%, जबकि मध्यम वर्ग की 6% बढ़ी।
▪ **ग्रामीण** इलाकों में आय सालाना 10%, ग्रामीण मजदूरों की आय ₹7.2% बढ़ी
▪ **केवल** 2% भारतीय इनकम टैक्स चुकाते हैं, चीन में 10%, अमेरिका में 43%।
▪ **टैक्स रिटर्न भरने वाले** 10 साल में 150% बढ़े, पर टैक्स देने वाले 28% ही।

तीन चीजें, जहां सबसे ज्यादा खर्च और नुकसान हुआ

▪ **फॉरेन ट्रेवल:** एक साल में भारतीयों का विदेश यात्रा खर्च ₹1.45 लाख करोड़ का रहा। यह देश की पूरे बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री से भी बड़ा है।
▪ **ट्रेडिंग लॉस:** 2022-25 के बीच रिटेल शेयर ट्रेडर्स का कुल घाटा ₹2.87 लाख करोड़ हो गया। इतने में हर घर को एक वॉशिंग मशीन दे सकते हैं।
▪ **साइबर ठगी:** 6 साल में साइबर ठगी से ₹53 हजार करोड़ का नुकसान हुआ। यह रकम देश की पूरी ब्रांडेड फास्ट फूड चेन इंडस्ट्री के बराबर है।

बिजनेस ब्रीफ

बोर्ड मीटिंग से पहले नोएल, चंद्रशेखरन की मुलाकात

मुंबई| टाटा संस की मंगलवार को होने वाली बोर्ड मीटिंग से पहले टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा और टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने मुलाकात की। इसी के साथ दोनों के बीच 3 महीने से जारी गतिरोध के खत्म होने के आसार हैं। इस बैठक में चंद्रशेखरन के तीसरे टर्म और घाटे में चल रही एअर इंडिया, टाटा डिजिटल जैसी कंपनियों के प्रदर्शन पर चर्चा होगी। आरबीआई के नियमों के तहत टाटा संस की लिस्टिंग पर भी बड़ा फैसला हो सकता है।

सेबी शुरू करेगा कमोडिटी डेरिवेटिव रेगुलेशन विभाग

मुंबई| सेबी 'कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट' को जुलाई से दोबारा शुरू करने की योजना बना रहा है। इसे 2021 में दूसरे विभाग में मिला दिया गया था। इंडस्ट्री की मांग पर यह कदम उठाया जा रहा है। जानकारों के मुताबिक, इक्विटी और कमोडिटी मार्केट के काम करने के तरीके अलग हैं। अलग विभाग से कमोडिटी बाजार में विदेशी निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने और 'ट्रेड इन इंडिया' को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

खाद सब्सिडी तीन लाख करोड़ तक पहुंच सकती है

नई दिल्ली| ईरान जंग के चलते वित्त वर्ष 2026-27 में भारत का खाद सब्सिडी बिल 3 लाख करोड़ रुपए के पार जा सकता है। यह बजट अनुमान (1.71 लाख करोड़ रुपए) से दोगुना है। ग्लोबल मार्केट में यूरिया की कीमतें 482 डॉलर से बढ़कर करीब 959 डॉलर प्रति टन और एलएनजी की कीमतें 10.4 से बढ़कर 17.4 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू हो गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस संकट को देखते हुए देशवासियों से ईंधन, खाद और विदेशी मुद्रा संभलकर इस्तेमाल की अपील की है।

आईटी कंपनियों के एच-1बी वीसा 40 फीसदी घटे

न्यूयॉर्क| अमेरिका में वीसा को लेकर नियमों को कड़ा किए जाने से शीर्ष भारतीय आईटी कंपनियों के लिए एच-1बी वीसा मंजूरियों में 40 फीसदी की गिरावट आई है। आधिकारिक अमेरिकी आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक भारत की छह सबसे बड़ी आईटी कंपनियों (टीसीएस, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो और टेक महिंद्रा) को केवल 11,041 एच-1बी वीसा मिले, जो पिछले साल के 18,469 वीसा के मुकाबले काफी कम हैं।

भास्कर एनालिसिस क्रूड सस्ता, बैंकिंग-ऑटो में तेजी, जोखिम घटने का संकेत

ईरान डील की उम्मीद में सेंसेक्स 1,073 अंक उछला, डर का पैमाना 8% गिरा

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की उम्मीदों ने सोमवार को घरेलू शेयर बाजार में जान फूंक दी। कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट और वैश्विक बाजारों की मजबूती के दम पर सेंसेक्स 1,073.61 अंक यानी 1.42% उछलकर 76,488.96 पर बंद हुआ। निफ्टी 50 ने 312.4 अंक की बढ़त के साथ 24,031.7 का स्तर छुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 76,559 तक पहुंचा। दिन में 1,144 अंकों की इंट्राडे तेजी। इस एक दिन की रैली में बीएसई में लिस्टेड सभी कंपनियों का कुल मार्केट कैप 6.55 लाख करोड़ रुपए बढ़कर 468.8 लाख करोड़ रुपए हो गया। इस रैली में बैंकिंग सेक्टर सबसे आगे रहा। पीएसयू बैंक इंडेक्स 2.9% तक उछला। प्राइवेट बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में भी 2% से अधिक तेजी रही। ऑटो इंडेक्स 1.9% और रियल्टी 1.5% चढ़ा।

बाजार की तेजी में लार्ज कैप शेयरों (जैसे अदाणी एंटरप्राइज, आयशर मोटर्स, एलएंडटी और बजाज फाइनेंस) का अहम योगदान रहा। मिडकैप (+0.94%) और स्मॉलकैप (+1.37%) इंडेक्स भी बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं एशियाई बाजारों में भी तेजी देखने को मिली। जापान का निक्केई 225 सोमवार को पहली बार 65,000 से ऊपर पहुंचा।

तेजी के चार बड़े कारण

1. **होर्मुज खुलने की उम्मीद:** अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा, ईरान के साथ डील तय हो चुकी है। इससे होर्मुज जलमार्ग खुलने की संभावना बनी, जो 28 फरवरी 2026 से बंद है। यह दुनिया के तेल, एलएनजी सप्लाई का पांचवां हिस्सा वहन करता है। बाद में ट्रम्प ने टीम को जल्दबाजी न करने की सलाह दी, जिससे बाजार में चिंता बढ़ी।
2. **कच्चा तेल100 डॉलर/बैरल से नीचे:** जियोजीत इंवेस्टमेंट के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार ने कहा, 'क्रूड 100 डॉलर से नीचे आ गया। अगर डील पक्की हुई तो यह बाजार के लिए टर्निंग पॉइंट बन सकता है।
3. **शानदार नतीजे:** भारतीय कंपनियों के चौथी तिमाही के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं, खासकर डिजिटल प्लेटफॉर्म सेक्टर की कंपनियों ने बंपर ग्रोथ दिखाई है।
4. **रुपए में मजबूती:** डॉलर के मुकाबले रुपया अपने हालिया निचले स्तर (96.96) से सुधरा है। स्थिरता से विदेशी निवेशक लौट सकते हैं।

बीएसई 500: वीआई समेत 19 शेयर साल के ऊंचे स्तर पर

अडानी एंटरप्राइजेज, वोडाफोन आइडिया, एंजेल वन, ग्लैंड फार्मा समेत 19 शेयरों ने 52 हफ्ते का नया हाई छू लिया। हिंडालको इंड.,पॉलीकैब इंडिया, केईआई इंड., अपोलो हॉस्पिटल्स समेत 10 नई ऊंचाई पर पहुंचे।
अदाणी ग्रुप के शेयरों में क्यों आई तेजी? ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन बर्नस्टीन के मुताबिक, अदाणी ग्रुप के लिए अब बुरा वक्त बीत चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी असल ताकत है। अदाणी एंटरप्राइजेज 5% चढ़कर 2,858 रुपए पर पहुंच गया।

डर खत्म हो रहा, पर निफ्टी का 24 हजार पार टिकना जरूरी

लाइवलॉन्ग वेल्थ के फाउंडर और रिसर्च एनालिस्ट हरिप्रसाद ने कहा कि यह तेजी जोखिम लेने की बढ़ती प्रवृत्ति का संकेत है। इंडिया विक्स में 8% गिरावट रही, जो यह संकेत देती है कि बाजार में डर कम हो रहा है। निवेशक बुलिश पोजिशन बना रहे हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट्स के मुताबिक, अगर निफ्टी 24,000 के ऊपर टिकने में कामयाब रहता है, तो बाजार में तेजी का यह दौर आगे भी जारी रहेगा।

बड़ी चुनौती • सर्विस सेक्टर का स्टार्टअप प्रोंटो विवादों में, ग्राहक नाराज

होम सर्विस के नाम पर किचन-बेडरूम तक एआई की नजर, केंद्र ने जांच शुरू की

अपेक्षा राय | नई दिल्ली/बेंगलुरु

देश के टेक और घरेलू सर्विस सेक्टर में प्राइवेसी को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बेंगलुरु स्थित क्विक-सर्विस डोमेस्टिक स्टार्टअप प्रोंटो पर आरोप लगा है कि वह एआई रोबोटिक्स सिस्टम को ट्रेंड करने के लिए ग्राहकों के घरों के भीतर की जा रही गतिविधियों (जैसे- बर्तन धोना, कपड़े समेटना और सफाई) की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। इस खुलासे के बाद जहां एक तरफ ग्राहकों में भारी नाराजगी है, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने भी इस मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है।

इस बीच प्रोंटो ने माना कि वह ग्राहकों के घरों के अंदर रिकॉर्डिंग करके एआई रोबोटिक्स सिस्टम को ट्रेन कर रही थी। साथ ही ये दावा भी किया कि वह ऐसा करने वाली अकेली कंपनी नहीं है। आईटी विशेषज्ञों के मुताबिक, यह मामला सिर्फ एक कंपनी की गलती नहीं, बल्कि एक बड़े और बढ़ते खतरे की आहट है, जहां आपका घर, आपकी दिनचर्या और आपकी निजता किसी कंपनी के कारोबारी मॉडल का हिस्सा बन जाती है। यही सबसे बड़ी चिंता है।

भास्कर नॉलेज: अभी एआई ट्रेनिंग को सीधे रोकने वाला कोई कानून नहीं, ये बड़ी दिक्कत

▪ **प्रोंटो को लेकर विवाद क्या है?** प्रोंटो 10-मिनट होम सर्विस एप है, जो रोजाना देशभर में 25,000 से ज्यादा ऑर्डर पूरे करता है। एनट्रैकर ने निवेशक कंपनी ग्लेड ब्रुक कैपिटल के दस्तावेजों के हवाले से बताया कि प्रोंटो घरों के अंदर रिकॉर्डिंग करके 'फिजिकल एआई और रोबोटिक्स सिस्टम' को ट्रेन कर रहा था। एआई लैब्स के साथ पायलट प्रोजेक्ट चला रहा था।

▪ **प्रोंटो ने क्या सफाई दी?** कंपनी ने माना कि रिकॉर्डिंग में बर्तन धोना, कपड़े तह करना और सफाई जैसे काम कैप्चर किए जाते थे। यह पायलट सिर्फ 0.1% ग्राहकों तक सीमित था। भागीदारी पूरी तरह स्वैच्छिक थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में कंपनी ने कहा, 'डिफॉल्ट रूप से कोई कैमरा नहीं होता, और जब होता है तो उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है।' दावा किया कि ऐसा करने वाली वो अकेली कंपनी नहीं है।
▪ **प्रतिद्वंद्वी कंपनियों ने क्या कहा?** स्नैबबिट के फाउंडर आयुष अग्रवाल ने एक पोस्ट में लिखा, 'हमने किसी भी ग्राहक के घर को कभी किसी भी तरह से रिकॉर्ड नहीं किया।' अर्बन कंपनी के सीईओ अभिराज सिंह बहल ने कहा, 'हम भरोसे के कारोबार में हैं। ग्राहकों की प्राइवेसी को गंभीरता से लेते हैं।'
▪ **क्या यह गैरकानूनी है?** आईटी, कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, भारत में घरेलू रिकॉर्डिंग से एआई ट्रेनिंग को सीधे रोकने वाला कोई कानून नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि यह पूरी तरह वैध है। कंपनियों को मौजूदा उपभोक्ता और प्राइवेसी कानूनों के तहत सहमति, पारदर्शिता और डेटा सुरक्षा के मानक तो पूरे करने ही होंगे। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 मई 2027 से लागू होगा, तब तक का यही कानूनी खालीपन कंपनियों को ग्रे एरिया में काम करने की छूट दे रहा है।
▪ **प्रोंटो की मौजूदा स्थिति क्या है?** कंपनी ने हाल ही में लैशी ग्रूम के नेतृत्व में ₹190 करोड़ का एक्सटेंशन राउंड जुटाया। इससे उसका वैल्युएशन 1 महीने में दोगुनी होकर ₹1,900 करोड़ रुपए हो गया।

अभी 650 ग्राम, 700 ग्राम, 810 ग्राम के पैक

खाद्य तेल के पैक साइज तय होंगे, भ्रामक पैकिंग बंद होगी

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

सरकार खाने के तेल के लिए मानक पैक साइज तय करने पर विचार कर रही है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उद्योग संगठनों के साथ बैठक के बाद यह प्रस्ताव परखना शुरू कर दिया है। दरअसल बाजार में 650 ग्राम, 700 ग्राम, 810 ग्राम, 850 ग्राम और 870 ग्राम जैसे तरह-तरह के पैक आ गए हैं, जो दिखने में लगभग एक जैसे हैं। इससे ग्राहकों के लिए कीमतों की तुलना मुश्किल हो गया है।

20 मई को उपभोक्ता मामलों के सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन समेत सेक्टर के करीब 90% हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन शामिल हुए। इन संगठनों ने 200 एमएल से लेकर 20 लीटर तक के मानक पैक साइज सुझाए हैं। 200 एमएल से छोटे पैक को इससे बाहर रखने का सुझाव है, ताकि सस्ते छोटे पैक उपलब्ध रहें।

मनमाने पैक साइज की छूट 2022 में मिली थी

▪ यह बदलाव 2022 में मिली उस छूट को पलट देगा, जिसमें मानक पैक साइज की अनिवार्यता हटा दी गई थी। कंपनियों को अपने हिसाब से पैकेजिंग चुनने की आजादी है। नए प्रस्तावित नियम घरेलू और आयातित, दोनों तरह के तेल पर लागू होंगे।
▪ यह कदम ऐसे समय उठाया जा रहा है जब देश में खाद्य तेल की खपत बढ़ रही है। 2020-21 में 2.46 करोड़ टन की खपत 2022-23 में बढ़कर 2.89 करोड़ टन हो गई। प्रति व्यक्ति खपत भी 2000 के दशक की शुरुआत में 8-9 किलो थी, जो अब सालाना 19.7 किलो हो गई है।

---

60 की उम्र में 40 जैसी जिंदगी; लॉन्जेविटी पर बड़ा दांव; बुढ़ापे को मात देने की तैयारी में स्टार्टअप्स

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

क्या बुढ़ापे को रोका जा सकता है? कुछ भारतीय स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अब इसी सवाल को हकीकत में बदलने में जुटे हैं। स्मार्ट रिंग से लेकर ब्रेन सेंसर तक- 'लॉन्जेविटी साइंस' अब सिर्फ किस्मत का नहीं, डेटा और तकनीक का बड़ा खेल बनता जा रहा है, जहां बिजनेस के बड़े मौके भी हैं।

जोमैटो के सह-संस्थापक गौरव गुप्ता ने लाइफस्टाइल बदलकर अपनी मेटाबोलिक उम्र 14 साल कम कर ली और अब 'गैबिट' स्टार्टअप के जरिये यही राह दूसरों को दिखा रहे हैं। दीपिंदर गोयल 'टेंपल' नाम के वियरेबल गैजेट पर काम कर रहे हैं, जो सीधे दिमाग में रक्त प्रवाह ट्रैक करेगा। बेंगलुरु के आईआईएससी में चल रही 'भारत स्टडी' पहली बार भारतीयों की आनुवंशिक बनावट के हिसाब से बुढ़ापे का आंकड़ा तैयार कर रही है। लक्ष्य सिर्फ लंबी उम्र नहीं, बल्कि बीमारी मुक्त, सक्रिय जीवन यानी 'हेल्थस्पैन' है।

4.8 लाख करोड़ रुपए के संभावित बाजार पर नजर

संकेतक	आंकड़ा
2022 में बुजुर्ग आबादी	10.5%
2050 तक अनुमानित	20.8%
सीनियर केयर मार्केट	10 साल में ₹4.8 लाख करोड़

▪ **2050 तक** पहली बार 60+ बुजुर्गों की संख्या 14 साल के बच्चों से ज्यादा होगी

कौन क्या कर रहा... बीमारी से पहले रिस्क की पहचान में जुटे

स्टार्टअप	टेक्नोलॉजी	मकसद
गैबिट	स्मार्ट रिंग	नींद, तनाव, मेटाबॉलिज्म ट्रैकिंग
बायोपीक	AI + MRI	बीमारी से पहले रिस्क की पहचान
डिकोड एज	जेनेटिक्स रिसर्च	उम्र थामने वाले सप्लीमेंट्स
टेंपल	वियरेबल सेंसर	दिमाग तक रक्त प्रवाह की निगरानी

'भारत स्टडी' के तहत ये पहल...

▪ अब तक 1,000 डेटा सैंपल्स जुटाए ▪ पहली बार भारतीयों की आनुवंशिक विविधता पर आधारित स्टडी ▪ स्थानीय मेटाबोलिक प्रोफाइल से बीमारी-पूर्व बचाव की रणनीति ▪ हॉस्पिटल चेन एआई-डेटा से प्रिवेंटिव केयर पर काम कर रहीं।

लॉन्जेविटी: 4 चुनौतियां

1. लंबी उम्र + बीमार शरीर, ये बड़ा संकट। 2. परिवारों, अस्पतालों पर बड़े खर्च का बोझ। 3. शहरों में डायबिटीज, हृदय रोग, अकेलेपन का खतरा। 4. स्वास्थ्य सेवाओं पर अभूतपूर्व दबाव की आशंका।

रियल एस्टेट में बूम

5 लिस्टेड रीट्स ने 8,900 करोड़ का पेआउट दिया, सालाना ग्रोथ 50%

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

भारतीय रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (रीट्स) सेक्टर में निवेशकों की चांदी हो रही है। देश के 5 लिस्टेड रीट्स ने वित्त वर्ष 2026 की मार्च तिमाही में 4.25 लाख से अधिक यूनिट होल्डर्स को डिविडेंड दिया। इसकी वैल्यू करीब 2,566 करोड़ रही। वहीं, पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में यह आंकड़ा 8,900 करोड़ के पार पहुंच गया, जो सालाना आधार पर 50% से अधिक की मजबूत ग्रोथ दिखाता है। इन पांच लिस्टेड रीट्स (ब्रुकफील्ड, एम्बेसी, नॉलेज रियल्टी, माइंडस्पेस और नेक्सस सिलेक्ट) का ग्रॉस एसेट वैल्यू 2.72 लाख करोड़ रुपए और मार्केट कैप 1.7 लाख करोड़ से अधिक है। ये मिलकर देश में 18.7 करोड़ वर्ग फीट का ग्रेड-ए ऑफिस और रिटेल स्पेस संभाल रहे हैं। इंडियन रीट्स एसोसिएशन (आईआरए) के चेयरमैन आलोक अग्रवाल ने कहा, 'वित्त वर्ष 26 में 8,900 करोड़ से अधिक का वितरण 50% की सालाना ग्रोथ दिखाता है। यह सेक्टर की मजबूती और निवेशकों को स्थिर रिटर्न देने की क्षमता को दर्शाता है। रीट्स अब घरेलू और वैश्विक निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है।'

बिजनेस एंकर भारत का लाइव इवेंट सेगमेंट 2025 में 44% बढ़कर 14,500 करोड़ रुपए तक पहुंचा

ब्रांड्स को अपनी दुनिया का हिस्सा बनाना चाह रहे जेन जी

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

आप हाल के 3 ऑनलाइन विज्ञापन याद कर सकते हैं? शायद नहीं। लेकिन दोस्तों के साथ देखा गया आखिरी कॉन्सर्ट या कॉमेडी शो जरूर याद होगा। यही फर्क भारत के मार्केटिंग की दुनिया को बदल रहा है।

फिक्की-ईवाई की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का लाइव इवेंट सेगमेंट 2025 में 44% बढ़कर ₹14,500 करोड़ तक पहुंच गया। अब यह मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे तेज बढ़ने वाली कैटेगरी है। यह एक बड़े बदलाव का सिर्फ एक उदाहरण है। बुकमाईशो में पार्टनरशिप और रेवेन्यू हेड समृद्धा तिब्रेवाला फॉर्च्यून इंडिया से कहती हैं कि यह सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं के व्यवहार में ढांचागत बदलाव है। अनिरुद्ध रविचंदर के शो मिनटों में हाउसफुल हो जाते हैं, जाकिर खान 40 से ज्यादा शहरों में हॉल भर रहे हैं और 'हमारे राम' जैसे नाटक 500 शोज का आंकड़ा पार कर चुके हैं। ब्रांड्स इस बदलाव को भांप चुके हैं। पहले सफलता का पैमाना था कि कितनी आंखों ने लोगो देखा। अब सवाल यह है कि दर्शक ने कितनी गहराई से ब्रांड को महसूस किया। बुकमाईशो की ईवाई-पार्थेनन के साथ तैयार रिपोर्ट बताती है कि लाइव इवेंट में ऑन-ग्राउंड अनुभव लेने वाले 59% दर्शकों को वहां मौजूद ब्रांड्स याद रहे। 63% ने माना कि ब्रांड्स ने उनका अनुभव बेहतर बनाया और 81% को यह एकीकरण स्वाभाविक लगा। कुछ दिलचस्प उदाहरण भी हैं। मसलन, एयरबीएनबी ने सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ मुंबई के अनुभवों को क्यूरेट किया। रुपे ने टिकट बुकिंग से लेकर इवेंट तक के पूरे सफर में फैन की परेशानियां दूर कीं। लेनोवो ने लोलापालूजा में एआई-जनरेटेड पर्सनलाइज्ड पोस्टर बनाने का मौका दिया। यहां हर अनुभव अलग, हर याद निजी है। तिब्रेवाला कहती हैं कि जेन जी (15-30 साल के युवा और किशोर) ब्रांड्स से बात सुनना नहीं चाहती। यह पीढ़ी चाहती है कि ब्रांड उनकी दुनिया का हिस्सा बने। इसीलिए सफल ब्रांड अब ग्राहकों के एक्सपीरियंस पर फोकस कर रहे हैं। तिब्रेवाला के मुताबिक आगे का रास्ता और चौड़ा है। कॉमेडी, रीजनल म्यूजिक, इमर्सिव आर्ट एग्जीबिशन और टियर-2,3 शहर- सब नए मोर्चे हैं। एआई-जनरेटेड कंटेंट की बाढ़ में लाइव एंटरटेनमेंट वह इंसानी अनुभव है, जिसकी नकल कोई एल्गोरिदम नहीं कर सकता। हजारों लोगों का एक साथ एक गाना गुनगुनाना- ये पल न रिकॉर्ड होता है, न दोहराया जा सकता है। जैसा तिब्रेवाला कहती हैं, 'यादें वापस नहीं होतीं' और यही वह जगह है, जहां असली मार्केटिंग हो रही है।'

पहुंच नहीं, भागीदारी बना सफलता का नया पैमाना

पारंपरिक मार्केटिंग में 'रीच' और 'इम्प्रेशन' सफलता के पैमाने थे। अब ये सिर्फ न्यूनतम अपेक्षा हैं। ब्रांड्स अब 'एंगेजमेंट डेप्थ', दर्शक की भावनात्मक भागीदारी, इवेंट के बाद की चर्चा और टिकाऊ ब्रांड अफिनिटी को मापना चाहते हैं। लाइव इवेंट में एक दर्शक जो सहज रूप से ब्रांड का प्रचार अपने समुदाय में करे, वह करोड़ों की डिजिटल रीच से कहीं अधिक मूल्यवान है।

टेक • टीवी, स्मार्टफोन, टैबलेट, इन-कार डिस्प्ले में होगा इस्तेमाल

भारत की पहली माइक्रो-एलईडी स्क्रीन 22 महीने में लॉन्च होगी: अश्विनी वैष्णव

सुरजीत दास गुप्ता | नई दिल्ली

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश की पहली माइक्रो-एलईडी स्क्रीन करीब 22 महीनों में बाजार में आ जाएगी। उन्होंने बताया कि गुजरात के धोलेरा में स्थापित होने वाली डिस्प्ले फैब से क्रिस्टल मैट्रिक्स और लूमेन्स के तकनीकी सहयोग से माइक्रो-एलईडी स्क्रीन तैयार की जाएगी।

धोलेरा प्लांट मिनी-एलईडी और माइक्रो-एलईडी, दोनों तरह की टेक्नोलॉजी पर काम करेगा। इससे टीवी, स्मार्टफोन, टैबलेट, इन-कार डिस्प्ले और एआर/वीआर यानी ऑग्मेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी ग्लासेज तक के लिए स्क्रीन बनाई जाएंगी। वैष्णव ने बताया कि भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) के तहत चार साल में देश में 12 सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित हो चुके हैं। इनमें से दो पहले से उत्पादन में हैं।

एआई के मोर्चे पर उन्होंने कहा कि 38,000 से अधिक जीपीयू तैनात किए जा चुके हैं और 65 रुपए प्रति घंटे की दर से यह दुनिया की सबसे सस्ती एआई कम्प्यूट फैसिलिटी है।

माइक्रो एलईडी मार्केट पर अभी एपल, सैमसंग हावी

फिलहाल माइक्रो-एलईडी टेक्नोलॉजी मुख्य रूप से सैमसंग और एपल जैसी चुनिंदा कंपनियों तक सीमित है। इनकी कीमतें आम उपभोक्ता की पहुंच से बाहर हैं। इंडस्ट्री का अनुमान है कि माइक्रो-एलईडी का वैश्विक बाजार 2030 तक करीब 30 अरब डॉलर (2.8 लाख करोड़ रुपए) तक पहुंच सकता है। धोलेरा प्लांट भारत को इस उभरते बाजार में शुरुआती बढ़त दिला सकता है। यहां एपल और सैमसंग जैसी कंपनियों का फोकस भी है। दोनों भारत में बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करती हैं, यानी डिमांड की चुनौती नहीं है।

Get Exclusive Access to My Private Channel

✅ One-Time Entry Fee Only. No Monthly Fees. Lifetime Validity.

♦️ **Indian Newspaper**

1) Times of India
2) The Hindu
3) Business line
4) The Indian Express
5) Economic Times
6) Financial Express
7) Live Mint
8) Hindustan Times
9) Business Standard

♦️ **International Newspapers channel** [Europian, American, Gulf & Asia]

♦️ **Magazine Channel**

National & International [Genaral & Exam related]

♦️ **English & Hindi Editorials**

[National + International Editorials]

Click here to join